ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संरक्षक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

वाणिज्य समझौते पर पुनर्दृष्टि

अमेरिका से हुए व्यापार समझौते के मोटे प्रारूप (फ्रेमवर्क) के कानूनी ब्यौरे को अन्तिम स्वरूप देने वाली वार्ता को भारत ने फिलहाल आगे के लिए टाल दिया है। यह वार्ता वाशिंगटन में सोमवार से होने वाली थी। जाहिर है कि भारत की मोदी सरकार चाहती है कि दोनों देशों के बीच आपसी कारोबार की शर्तें अब अमेरिका के सुप्रीम या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की एकतरफा घोषित शुल्क के विरुद्ध दिये गये फैसले की रोशनी में तय होनी चाहिए। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने दो दिन पहले ही साफ कर दिया था कि ट्रम्प ने संविधान के जिस 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनामिक पावर्स एक्ट' के तहत दुनिया के विभिन्न देशों के आयातित माल पर मनमाफिक शुल्क दरें निर्धारित की हैं वे अवैध हैं और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्होंने अमेरिकी संसद (कांग्रेस) की स्वीकृति नहीं ली है। इस फैसले के तुरन्त बाद ट्रम्प ने अमेरिका के संविधान के एक अन्य अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए 150 दिन या पांच महीने के लिए अमेरिका में आने वाले समस्त आयातित माल पर पहले 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की और बाद में उसे बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया।

भारत के साथ बनी व्यापार सहमति के अन्तर्गत यह शुल्क दर 18 प्रतिशत रखी गई थी अत: अब भारत से निर्यातित माल पर यही दर लगेगी। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत व अमेरिका के बीच जिस कारोबार फ्रेमवर्क की घोषणा पिछले दिनों हुई थी उसकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की रोशनी में अब स्थिति क्या होगी? इस बारे में देश के कुछ विशिष्ट आर्थिक पंडितों की राय है कि वह फ्रेमवर्क या व्यापार प्रारूप अब केवल 'उद्देश्यात्मक या इच्छा शक्ति का वक्तव्य' बन कर रह जायेगा। इस फ्रेमवर्क के घोषणा पत्र पर दोनों ही देशों के कार्यकारी राज प्रमुखों ने हस्ताक्षर किये थे। वैश्विक गतिविधियों से जाहिर है कि जब से अमेरिका में जनवरी 2024 से राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रम्प बैठे हैं तब से पूरी दुनिया की राजनीति में भारी उथल-पुथल चल रही है। विगत 2025 वर्ष के दौरान ट्रम्प की नीतियों की वजह से पूरे विश्व में 'आर्थिक समर' का ऐसा दौर शुरू हुआ है कि इसने दुनिया के सभी देशों में अपने-अपने आर्थिक हित संरक्षण का अभियान चला दिया है। निश्चित रूप से इसे 'आर्थिक कोल्ड वार' का नाम दिया जा सकता है। मगर सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि ट्रम्प की नीतियों की वजह से इस कोल्ड वार के चलते विश्व का शक्ति क्रम गड़बड़ा गया है और विश्व व्यापार संगठन पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है। ट्रम्प ने द्विपक्षीय आधार पर जिस तरह दुनिया के बीस से अधिक आर्थिक क्षमता वाले देशों के साथ व्यापार समझौते किये उनसे विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों व विकासशील देशों के बीच जो न्यायप्रिय व्यापारिक सन्तुलन बना था वह पूरी तरह क्षत- विक्षत हो चुका है अत: ऐसे वातावरण में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का अमेरिका की एकतरफा शुल्क नीति के खिलाफ आया फैसला विकासशील देशों के लिए 'रामबाण' की तरह है। भारत बेशक फिलहाल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है मगर यह एक विकासशील देश ही है क्योंकि इसके 80 प्रतिशत से ज्यादा नागरिकों की हैसियत अभी भी विकसित देशों के नागरिकों के मुकाबले बहुत कमजोर है। अत: भारत को यह सोचना होगा कि वह फैसले के बाद बने नये वातावरण का अधिकतम लाभ अपने हित में किस प्रकार उठाये? इस सन्दर्भ में भारत ने कुछ दिनों पहले ही जो व्यापार समझौता यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ किया है वह नजीर बन सकता है। इस समझौते में भारत ने यूरोपीय देशों को निर्यात होने वाले उस भारतीय माल पर जीरो प्रतिशत शुल्क की छूट ली है जिसके उत्पादन करने में भारत में श्रमिक बल व हुनर की आवश्कता पड़ती है। अत: अमेरिका के साथ भी व्यापार शर्तें निर्धारित करते हुए भारत अपने श्रममूलक उद्योगों का संरक्षण करने की कोशिश कर सकता है।

> **यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते में भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को भी पूरी तरह संरक्षित किया है। इसके साथ ही भारत की कोशिश हो सकती है कि वह अमेरिका से आने वाले अर्थात आयातित माल पर शुल्क दरें इस प्रकार लगाये कि भारत में ऐसे क्षेत्रों में स्थापित उत्पादन इकाइयों की उत्पादकता पर प्रभाव न पड़े। लेकिन इसके साथ-साथ भारत को अपने लोगों की क्रय क्षमता को भी ध्यान रखना होगा और उपभोक्ताओं को राहत भी देनी होगी अत:वह अमेरिकी आयातित माल पर अन्ध विराम नहीं लगा सकता है।**

यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते में भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को भी पूरी तरह संरक्षित किया है। इसके साथ ही भारत की कोशिश हो सकती है कि वह अमेरिका से आने वाले अर्थात आयातित माल पर शुल्क दरें इस प्रकार लगाये कि भारत में ऐसे क्षेत्रों में स्थापित उत्पादन इकाइयों की उत्पादकता पर प्रभाव न पड़े। लेकिन इसके साथ-साथ भारत को अपने लोगों की क्रय क्षमता को भी ध्यान रखना होगा और उपभोक्ताओं को राहत भी देनी होगी अत:वह अमेरिकी आयातित माल पर अन्ध विराम नहीं लगा सकता है। विशेषकर उच्च टैक्नोलोजी व रक्षा टैक्नोलोजी के क्षेत्र में इसे अमेरिका को उचित स्थान देना ही होगा। हमें यह भी समझना होगा कि जब किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार समझौते होते हैं तो उनका असर वैश्विक रणनीतिक मामलों पर भी पड़ता है अत: रूस के साथ भारत के जो ऐतिहासिक मधुर सम्बन्ध हैं वे किसी भी तरह से प्रभावित न हों । मगर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले का दूसरा असर यह भी हो सकता है कि दुनिया में बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलन की धारा बहने लगे क्योंकि अभी तक विश्व के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों पर अमेरिका व यूरोपीय देशों का ही दबदबा रहा है जबकि ब्रिक्स (ब्राजील-रूस- भारत-चीन व दक्षिण अफ्रीका) जैसा संगठन बनने के बाद वैश्विक स्तर पर कारोबारी समीकरण बदलने की दिशा में चलने लगे थे। मगर श्री ट्रम्प ने अपनी शुल्क नीति के जरिये पूरे व्यापारिक सन्तुलन को केवल अमेरिका के ही पक्ष में झुकाने का तरीका ढूंढने का प्रयास किया। यही वजह रही कि पूरी दुनिया के देश उनकी इस नीति को विश्व के समरूपी विकास के सिद्धान्त के विरुद्ध मानने लगे थे और चिन्तित थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने संयुक्त राष्ट्रसंघ का यही उद्देश्य था।

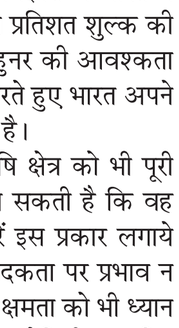

पश्चाताप के आंसू...

गीता पाढा

"जब हमारे बच्चे रील और रियल का अंतर भूल जाएं,
तब तब मानवीय संवेदनाएं केवल किताबी बातें कहलाएं,,
तेज रफ्तार वाहन न जाने किस घड़ी यमराज रूप दिखाएं,
किसी का मंनोरंजन किसी के घर का दीपक बुझाएं,,
क्यों नहीं हम अपने बच्चों को सही राह दिखा पाते,
काश! कभी एक दोषी के आंखों में भी
वास्तविक पश्चाताप के आंसू मिल पाते...।।"

विजय दर्डा
संपादक : लोकमत समूह
पूर्व राज्यसभा सांसद

अमित शाह का अब नशे पर करारा प्रहार

अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि आपने एक निश्चित अवधि में नक्सलवाद को खात्मे की कगार पर पहुंचा कर नजीर पेश की है कि नेतृत्वकर्ता में दम हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब आपसे गुजारिश है कि देश को नशे के सौदागरों से मुक्ति दिलाइए। ड्रग्स कार्टेल का खात्मा करिए। यह आसान काम नहीं है लेकिन आप में यह करिश्मा करने का दम है। उन्होंने अपनी खुशनुमा मुस्कान के साथ बस इतना कहा कि देखते जाइए, ड्रग्स कार्टेल की अब बिल्कुल ही खैर नहीं। इस देश में उनके लिए कोई जगह नहीं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर वैसे तो हमेशा ही विश्वास का भाव रहा है लेकिन जिस तरह से उन्होंने नक्सलवाद को खात्मे की कगार पर पहुंचा दिया है, उसने उनकी दृढ़ता, साहस और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता का सबको मुरीद बना दिया है। उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की घोषणा की थी तो सबको शंका थी कि 55 साल से भी ज्यादा पुराना यह रक्तरंजित रोग, जिसने न जाने कितने नेताओं, पुलिस अधिकारियों और प्रभावशाली नेताओं की जान ली, क्या वाकई इतनी जल्दी खत्म होना संभव है? मगर अमित शाह दृढ़ थे कि खात्मा तय कर लिया है तो फिर लक्ष्य पूरा होगा। दरअसल उन्होंने जब घोषणा की थी उसके काफी पहले से संबंधित राज्यों के साथ व्यूह रचना की जा रही थी। तैयारी लीकप्रूफ थी, लक्ष्य स्पष्ट था, योग्य अधिकारियों को तैनात किया जा चुका था, संसाधनों में कोई कमी नहीं रखी गई, भूले-भटकों के लिए एक हाथ में स्नेह भरा स्पर्श था तो कट्टरता दिखाने वालों के लिए आग उगलती बंदूकें थीं। सफल नेतृत्वकर्ता का यही अंदाज होता है।

निश्चित रूप से अब बारी ड्रग्स के सौदागरों की है और केंद्रीय स्तर पर सघन व्यूह रचना के साथ काम चल भी रहा है। आम धारणा यही है कि अमित शाह घोषणा से ज्यादा परिणामों में विश्वास करने वाले नेता हैं। जब थोड़ी सी जानकारी सामने आती है तो ढेर सारा काम हो चुका होता है। अभी मैं गोवा में था। वहां के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों राज्यों के आला पुलिस अधिकारियों से मैं बात कर रहा था तो पता चला कि ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ कितनी सघन तैयारी चल रही है। शायद कम ही लोगों को पता होगा कि केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2020 को नशामुक्त भारत अभियान की घोषणा की थी। ऐसा नहीं कि अचानक घोषणा कर दी गई हो। उसके पहले 2018 में एक सर्वेक्षण किया गया जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई। निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। पता चला कि 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं जिनमें से 5.7 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर स्थिति में हैं। दूसरे स्थान पर भांग है जिसका सेवन करीब 3.1 करोड़ लोग करते हैं। करीब 25 लाख लोग गंभीर लत से पीड़ित हैं। लगभग 2.26 करोड़ लोग अफीम खाते हैं जिनमें 77 लाख लोग गंभीर हालत में हैं। करीब 8.5 लाख लोग नसों में इंजेक्शन के माध्यम से नशीली दवाएं लेते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। इतना ही नहीं सूंघ कर नशा करने वालों की संख्या भी काफी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही योजना बनी और नशे के सौदागरों की नकेल कसने का काम प्रारंभ हुआ।

> **नक्सलवाद के अंत का लक्ष्य करीब-करीब पूरा, अब ड्रग्स के सौदागरों के खात्मे का अभियान, ड्रग्स कार्टेल को नेस्तनाबूद करना आसान काम नहीं लेकिन लक्ष्य के प्रति दृढ़ता हो तो कुछ भी असंभव नहीं।**

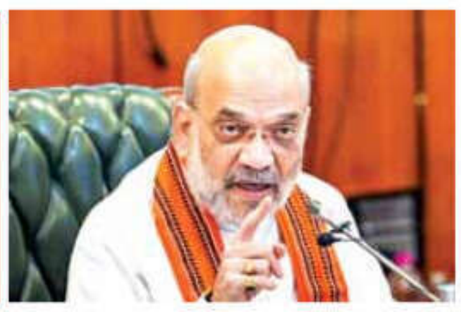

आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर में राष्ट्रीय नारकोटिक्स टास्क फोर्स के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा स्पष्ट ब्यौरा दिया था। उन्होंने टास्क फोर्स से कहा था कि भारत में ड्रग्स कार्टेल के तीन चरण हैं। पहला जो विदेश में बैठा है और सीमा से ड्रग्स अंदर भेजता है। दूसरा जो देश के भीतर है और विभिन्न राज्यों तक ड्रग्स पहुंचाता है और तीसरा जो स्थानीय स्तर पर ड्रग्स की पुड़िया चौक-चौराहों तक पहुंचाता है। तीनों कार्टेल पर एक साथ पूरी शक्ति के साथ आघात करने की जरूरत है और यह आघात पूरी शक्ति के साथ चल रहा है। हमारी खुफिया एजेंसियां बेहतरीन काम कर रही हैं। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि भारत की जेलों में करीब 16 हजार ड्रग्स तस्कर बंद हैं। ये तस्कर बांग्लादेश, फिलीपींस, घाना, म्यांमार, मलेशिया और नाइजीरिया जैसे देशों से हैं। इन्हें डिपोर्ट करने का काम प्रारंभ हो चुका है, जो ड्रग्स तस्कर विदेशों में बैठे हैं, उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी चल रही है।

मगर सबसे बड़ा अभियान तो इस बात को लेकर चल रहा है कि बॉर्डर से ड्रग्स की तस्करी भारत में हो ही नहीं पाए। निश्चित रूप से यह आसान काम नहीं है क्योंकि ड्रग्स कार्टेल का नेटवर्क बड़ा पुख्ता है। ड्रग्स के धंधे में अथाह पैसा है जिसका उपयोग प्रलोभन से लेकर धमकी देने या जान लेने तक में किया जाता है। पंजाब और राजस्थान बॉर्डर से लेकर गुजरात में समुद्री सीमा तक ड्रग्स तस्करों की मदद पाकिस्तानी आर्मी और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही है। ड्रग्स भेजने के लिए तस्करों को ड्रोन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरा बड़ा रास्ता है गुजरात का समुद्र तट। खासकर हेरोइन नाम का नशा कंटेनर में छुपा कर तस्करी करने के कई प्रकरण सामने आ चुके हैं। पांच साल पहले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ऐसे ही एक कंटेनर में छिपा कर लाई गई 21 हजार करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश में नेपाल के रास्ते तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते ड्रग्स की तस्करी हो रही है और ये सारे ड्रग्स तस्कर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैक्सिको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस, नेपाल, म्यांमार से लेकर नाइजीरिया और घाना तक के ड्रग्स कार्टेल एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं, वे एक-दूसरे के नेटवर्क का उपयोग भी करते हैं। ऐसी स्थिति में लड़ाई निश्चय ही बहुत बड़ी है। मगर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और अमित शाह की दृढ़ता पर भरोसा किया जाना चाहिए कि जिस तरह भारत ने नक्सलवाद के खिलाफ जंग जीती है। ड्रग्स कार्टेल को भी नेस्तनाबूद करने में हम सफल होंगे। अमित शाह जी, देश आपके साथ है। एक बात और कहना चाहता हूं कि ड्रग्स के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवा, हमारे शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता निभा सकते हैं। कार्रवाई तो पुलिस करेगी लेकिन ये सभी लोग खुफिया सूचना के सूत्र तो बन ही सकते हैं।

यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ड्रग्स के सौदागरों का जाल गांव-गांव तक फैला है और हमारे युवाओं को ही वो शिकार बना रहे हैं।

रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए घातक

रोहित माहेश्वरी

मुफ्त की रेवड़ी पर बीती 19 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए गंभीर सवाल उठाए। न्यायालय ने कहा कि हम किस तरह की संस्कृति विकसित कर रहे हैं? न्यायालय ने पूछा कि क्या राज्यों का काम सिर्फ वेतन देना और मुफ्त उपहार बांटना रह गया है? पीठ ने कहा कि ऐसी नीतियों से लोगों में काम करने की इच्छा खत्म हो रही है और देश का 'वर्क कल्चर' खराब हो रहा है।

रेवड़ी संस्कृति देश की राजनीति के केंद्र में आ चुकी है। फ्री बीज की शुरुआत सन् 1956 से हुई मानी जा सकती है, जब मध्याह्न भोजन योजना पहली बार वर्ष 1956 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. कामराज द्वारा शुरू की गई थी। ऐसा माना जाता है कि आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की 2 रुपए किलो चावल योजना ने आज के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की नींव रखी थी। तेलंगाना की रायथु बंधु और ओडिशा की कालिया योजनाओं ने किसानों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अग्रदूत के रूप में कार्य किया है।

दक्षिण भारत से शुरू हुई इस प्रथा को अरविंद केजरीवाल ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसका बाद में दूसरे दलों ने अनुसरण किया। एक ओर अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ इस प्रथा की आलोचना करते हैं, तो दूसरी ओर कई नेता मतदाताओं के लिए मुफ्त चीजों की वकालत करते हैं। चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे और चुनाव अक्सर इस मायने में जुड़े होते हैं कि राजनीतिक दल अपने घोषणापत्रों में इसका वादा करते हैं और सत्ताधारी दल अक्सर चुनाव से ठीक पहले उन्हें बांट देते हैं।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह जीवन की अच्छी गुणवत्ता से समझौता है, क्योंकि मुफ्त उपहारों की संस्कृति स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान एवं विकास आदि जैसी अन्य जरूरी आवश्यकताओं पर कम पूंजीगत व्यय को दर्शाती है। साथ ही यह बजटीय संकट को भी जन्म देती है। 2019 में दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स द्वारा भारत के 543 संसदीय क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया गया था। उस सर्वेक्षण के अनुसार, 42 फीसद से अधिक मतदाता किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के पीछे उम्मीदवार की कल्याणकारी योजनाओं के बजाय नकदी, शराब और मुफ्त उपहारों के वितरण को एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं।

ताजा मामले में न्यायालय ने चिंता जताई कि अधिकांश राज्य पहले से ही 'रेवेन्यू डेफिसिट' में हैं, फिर भी वे मुफ्त बिजली, राशन और नकदी बांट रहे हैं। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि इस कारण बुनियादी ढांचे यानी सड़क, स्कूल, अस्पताल के विकास के लिए "एक पैसा भी नहीं बचता"। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि "जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करना समझ में आता है लेकिन बिना भेदभाव के सबको मुफ्त सुविधाएं देना 'तुष्टिकरण की राजनीति' है।"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि आखिर रेवड़ियां बांटने का बोझ टैक्स देने वाले लोगों पर ही पड़ेगा। यदि 'रेवड़ियां' मिलती रहेंगी तो काम कौन करेगा? आखिर हम यह कैसी संस्कृति बना रहे हैं? सरकारों को 'मुफ्तखोरी' के बजाय रोजगार-सृजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

बहरहाल सर्वोच्च अदालत ने मौखिक टिप्पणी कर दी और राजनीतिक दलों के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वे शीर्ष अदालत की बात मानने को बाध्य नहीं हैं। ये 'रेवड़ियां' नहीं हैं, बल्कि कल्याणकारी योजनाएं हैं। हम कल्याणकारी लोकतंत्र हैं और जनता की मदद करना हमारा फर्ज है। लिहाजा क्षमा के साथ सर्वोच्च अदालत से भी हमारा सवाल है कि वह मौखिक टिप्पणियां क्यों करती है? सिर्फ चिंता व्यक्त करने से क्या होगा? सर्वोच्च अदालत को संविधान ने विशेषाधिकार भी दिए हैं और उनका इस्तेमाल कर अदालत ने फैसले भी सुनाए हैं तो मुफ्तखोरी पर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते? अदालत सरकारों को स्पष्ट निर्देश दे कि चुनाव से पहले योजनाओं की घोषणा कब करें? 'रेवड़ियां' को भी परिभाषित करें। 11 अगस्त 2022 को रेवड़ी कल्चर पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मुद्दा समाज और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्री बीज की वजह से इकोनॉमी पैसे गंवा रही है। हम इस बात से सहमत हैं कि फ्री बीज और वैलफेयर के बीच अंतर है।

सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष और परोक्ष करों से आता है, जिनसे सरकार को लिए गए ऋणों पर ब्याज, रक्षा, अनावर्ती व्यय, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सब्सिडी और जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का भुगतान करने में मदद मिलती है। ये योजनाएं तय होती हैं और सरकार के कुल व्यय का एक हिस्सा इन पर खर्च होता है।

जमीनी हकीकत यह है कि देश के राज्यों पर कुल 104 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। देश पर भी 200.50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कुछ विशेषज्ञ इसे 225 लाख करोड़ के करीब मानते हैं। इसके बावजूद रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि आम आदमी फ्री बीज नहीं मांगता। रेवड़ियां देश के विकास के लिए खतरनाक हैं। ये अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती हैं। इन कथनों के बावजूद हर दल रेवड़ियां बांटने की होड़ में शामिल है।

जिस तमिलनाडु से याचिका शीर्ष अदालत में दी गई थी, उस राज्य पर 10.42 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। बंगाल पर 7.90 लाख करोड़ और केरल पर 5.04 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इन राज्यों में इसी साल अप्रैल के बाद चुनाव होने हैं। जानकारों की मानें तो चुनाव से पहले मुफ्त वादों की घोषणा पर लगाम लगाना जरूरी है लेकिन यह आसान नहीं है।

भारत के निर्वाचन आयोग को चुनावों के दौरान मुफ्त वाली घोषणाओं की प्रभावी निगरानी और उनके विनियमन को सुनिश्चित करने की जरूरत है। नागरिकों को भी अल्पकालिक लाभ से प्रभावित होने के स्थान पर राजनीतिक दलों के दीर्घकालिक विकास एजेंडे के आधार पर मतदान के समय देशहित में निर्णय लेने के लिए शिक्षित किए जाने की जरूरत है।

चुनाव जीतने के लिए फ्री बीज पर अत्यधिक निर्भरता के बजाय, राजनीतिक दलों को सामाजिक सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली, रोजगार सृजन और व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ताकि सामाजिक, आर्थिक असमानता के मूल कारणों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। रेवड़ी कल्चर एक चुनावी हथकंडा है जो तात्कालिक लाभ देने के बावजूद दीर्घकालिक रूप से देश की आर्थिक प्रगति में बाधा डालता है। आज राजनीतिक दलों को मुफ्त की घोषणाओं से आगे बढ़कर दीर्घकालिक विकास योजनाओं की दिशा में काम करने की जरूरत है।

लुटियंस की जगह सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा, मुर्मू ने किया अनावरण

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 'राजाजी उत्सव' की शोभा बढ़ाई और राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया कि अशोक मंडप के पास ग्रैंड ओपन सीढ़ी पर स्थित चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा ने एडविन लुटियंस की प्रतिमा का स्थान ले लिया है। यह पहल औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को मिटाने और भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, शाश्वत परंपराओं को गर्व से अपनाने तथा भारत माता की सेवा में असाधारण योगदान देने वालों को सम्मानित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम औपनिवेशिक काल की विरासत से आगे बढ़ने और देश के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रख्यात भारतीय नेताओं को मान्यता देने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राजगोपालाचारी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और विद्वान थे, जिन्होंने 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया।

प्रधानमंत्री ने राजगोपालाचारी की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण की सराहना की : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां राष्ट्रपति भवन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण की सोमवार को सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कदम औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को मिटाने और उन लोगों को सम्मानित करने के देश के संकल्प को दर्शाता है, जिन्होंने इसके भाग्य को आकार दिया।

पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का लंबी बीमारी के बाद निधन

कोलकाता, (पंजाब केसरी): पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के किसी समय सबसे भरोसेमंद सहयोगी और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का रविवार देर रात यहां एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।वह 71 वर्ष के थे और उनके परिवार में बेटा सुभ्रांशु रॉय है।

सुभ्रांशु रॉय ने बताया कि मुकुल रॉय ने सॉल्ट लेक के एक अस्पताल में देर रात करीब डेढ़ बजे अंतिम सांस ली।वह कई बीमारियों से जूझ रहे थे और पिछले दो वर्षों में कई बार अस्पताल में भर्ती रहे थे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्हें मनोभ्रंश भी हो गया था और हाल ही में वह कोमा में चले गए थे।

भगवंत मान ने किया मेरी रसोई योजना का ऐलान

चंडीगढ़, (पंजाब केसरी) : ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को 'मेरी रसोई' योजना की शुरुआत का ऐलान किया, जिसके तहत 40 लाख परिवारों को अप्रैल से तिमाही आधार पर मुफ्त फूड किट (भोजन किट) का वितरण शुरू किया जाएगा उल्लेखनीय है कि ये फूड किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले गेहूं से अलग तौर पर प्रदान की जाएंगी। इस योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार "जन कल्याण योजनाओं के लिए संसाधन जुटाना अच्छी तरह जानती है,। योजनाए पूरी ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ चलती है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि हमारा नैतिक फर्ज है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोक-हितैषी बजट में भी समाज के हर वर्ग के हितों का ख्याल रखते हुए लोक भलाई उपायों का दायरा और विस्तृत किया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री . भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पहल पंजाब के हर परिवार के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब के शानदार योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के मेहनती और जुझारू किसानों ने अथक मेहनत से यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई भी भूखा न सोए।

उन्होंने कहा कि हमारे राज्य ने देश का पेट भरने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हालांकि पंजाब में अभी कुछ परिवार ऐसे हैं, जो अपनी रोजी-रोटी के लिए रोज संघर्ष करते हैं।

भोजशाला विवाद : आपत्तियां पेश करने के लिए दो हफ्तों की मोहलत

इंदौर, (पंजाब केसरी): मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने धार के भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर जारी विवाद के मामले में सोमवार को सभी पक्षकारों को अपनी आपत्तियां, राय, सुझाव और सिफारिशें पेश करने के लिए दो हफ्तों की मोहलत दी। भोजशाला को हिंदू समुदाय वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष 11वीं सदी के इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद बताता है। यह परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित है। शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी को उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह विवादित परिसर के बारे में एएसआई द्वारा सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट खोले। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया कि यह रिपोर्ट पहले ही खोली जा चुकी है और इसकी प्रति पक्षकारों को प्रदान की भी जा चुकी है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

महिला, किसान, युवा और आदिवासी के विकास पर रहा फोकस

'विकसित छत्तीसगढ़' का रोडमैप

राज्यपाल के अभिभाषण में दिखी समृद्ध और सशक्त प्रदेश की संकल्पना

पत्रिका ब्यूरो @ रायपुर. विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने अपने 45 मिनट के अभिभाषण में 106 बिंदुओं से सरकार के कामकाज और उपलिब्धयों को बताया। उनके अभिभाषण में विकसित छत्तीसगढ़ की झलक दिखाई दी। उनके अभिभाषण के केंद्र में महिला, किसान, युवा और आदिवासियों का विकास रहा। नक्सलवाद की सफलता और बस्तर-सरगुजा के विकास का भी प्रमुखता से जिक्र किया। राज्यपाल ने रजत जयंती वर्ष की बधाई देते हुए अपने अभिभाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा, अब हमारे प्रदेश ने विकसित राज्य की ओर अपना नया सफर शुरू किया है। सामूहिक प्रयत्न और संकल्प से निश्चित रूप से हम वर्ष 2047 तक विकसित राज्य का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे राज्य का निर्माण किया। उन्होंने जिस संकल्पना को लेकर छत्तीसगढ़ बनाया, उसे पूरा होते देखकर बहुत खुशी होती है।

विकास की असीम संभावनाएं: राज्यपाल ने कहा, छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहां की सरल, सहज और मेहनतकश जनता की बदौलत मेरी सरकार इन संभावनाओं को साकार करने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है।राज यपाल ने कहा, विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब किसान मजबूत और समृद्ध होंगे। इसलिए मेरी सरकार उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने, फसल का उचित मूल्य दिलाने और बाजार तक उनकी आसान पहुंच तय करने के लिए निरंतर काम कर रही है।

45 मिनट के अभिभाषण में 106 बिंदुओं से सरकार के कामकाज-उपलिब्धयों को दर्शाया

यह रही अन्य खास बातें

- **दूध** का क्रय मूल्य 35 से बढ़ाकर 36.50 रुपए प्रति लीटर किया।
- दो वर्षों में 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है।
- लगभग 69 लाख महिलाओं के खाते में 15596 करोड़ रुपए जमा।
- 532 माओवादी न्यूट्रलाइज किए गए, 2704 ने आत्मसमर्पण तथा 2004 गिरफ्तार किए गए।
- बस्तर में 146 सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों के लिए 1109 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
- नवा रायपुर को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- विभिन्न विभागों में करीब 32 हजार पदों पर भर्ती की जा रही है।
- नई औद्योगिक नीति में 7.83 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए।
- स्वास्थ्य सेवाओं में 1639 पदों पर नियुक्ति की है व 2300 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- लालफीताशाही रोकने ई-फाइल की व्यवस्था लागू की है। बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू हुआ है।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट | प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने का संकेत

रेकॉर्ड ग्रोथ... पिछले साल के मुकाबले 10.07% बढ़ी हर छत्तीसगढ़ी की औसत आय

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

रायपुर. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट से पहले विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट पेश किया। छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में 10.07 फीसदी की वृद्धि हुई है। इससे प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 62 हजार 870 रुपए से बढ़कर 1 लाख 79 हजार 244 रुपए होने का अनुमान है। जबकि भारत के प्रति व्यक्ति 2 लाख 19 हजार 575 रुपए अनुमति है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह वृद्धि प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देती है। राज्य की जीडीपी प्रचलित भावों पर वर्ष 2024-25 में 5 लाख 65 हजार 845 करोड़ रुपए से बढ़कर 6 लाख 31 हजार 291 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वहीं स्थिर भाव में 8.11 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान है। मंत्री चौधरी ने कहा, यह दर्शाता है

631291 करोड़ हो सकती है जीएसडीपी

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश की रिपोर्ट

विधानसभा में सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करते वित्त मंत्री ओपी चौधरी व अधिकारी।

ऐसे बढ़ी प्रति व्यक्ति आय

2020-21	106117
2021-22	123493
2022-23	133798
2023-24	149781
2024-25	162848
2025-26	179244

क्षेत्रवार आंकड़े

विषय	छत्तीसगढ़	भारत
कृषि	17.80	13.80
उद्योग	49.30	30.30
सेवा	32.90	55.80

सुधारों और विकास के पथ पर अग्रसर

वित्त मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर आर्थिक प्रगति, संरचनात्मक सुधारों और समावेशी विकास के पथ पर अग्रसर है। राज्य की आर्थिक समीक्षा यह दर्शाती है कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के संतुलित विकास के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन, बुनियादी ढांचे का विस्तार और डिजिटल शासन ने विकास की गति को सुदृढ़ किया है।

12.30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे साय सरकार का बजट

बजट... ब-बेहतर, ज- जिंदगी का, ट- टारगेट

रायपुर. विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी मंगलवार को दोपहर 12.30 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 का मुख्य बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार बजट की व्याख्या बेहतर जिंदगी का टारगेट देने के हिसाब से की जाएगी। उम्मीद है कि इस बार भाजपा के संकल्प पत्र के कुछ वादें धरातल पर उतरेंगे। एक बार फिर युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और विकास के लिए बजट में अधिक धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाएगी। केंद्र सरकार के बजट के बाद राज्य सरकार भी शहरी क्षेत्रों को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए नई योजना लाने की तैयारी में है।

आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश की मजबूत, संतुलित और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में विकास के सभी प्रमुख क्षेत्र समान रूप से प्रगति कर रहे हैं। राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं।
-विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

सरकार बजट को गंभीरता से नहीं ले रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे दिन बजट रख रहे हैं। इससे राज्यपाल के अभिभाषण की गरिमा गिर रही है। थकी व झुकी सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है।
-भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

उम्मीदों की चांदी | बजट के आकार में 10 से 12 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना

बजट का बढ़ेगा आकार विकास पकड़ेगा रफ्तार

रायपुर @ पत्रिका. वित्त मंत्री ओपी चौधरी मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का मुख्य बजट पेश करेंगे। इस साल बजट के आकार में 10 से 12 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है। पिछले साल सरकार ने 165000 करोड़ का बजट पेश किया था। अनुपूरक बजट को मिलाकर कुल बजट का आकार 2 लाख करोड़ पहुंच गया था। इस बजट से आम जनता के साथ युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और व्यापारियों को सौगातें मिलने की उम्मीद हैं। सरकार भी अलग-अलग वर्गों से मिले सुझावों को बजट में शामिल कर सकती है।

आर्थिक रूप से हुए मजबूत, बढ़ता गया

वर्षवार बजट

छत्तीसगढ़ में हर साल मुख्य बजट जारी होने के बाद अनुपूरक बजट भी पेश किया जाता है। पहला अनुपूरक बजट विधानसभा के मानसून सत्र में, दूसरा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में और तीसरा विधानसभा के बजट सत्र में। पहली बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी की अगुवाई में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश नहीं हुआ। शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य के इतिहास में पहली बार 35 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ। इस बार के बजट सत्र में भी अनुपूरक बजट पेश होने की उम्मीद कम है, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत के दूसरे

बजट को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाएं लोकतंत्र की मूल जिम्मेदारी हैं और इन्हें पूरा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। सरकार अपने चुनावी घोषणा-पत्र (मैनिफेस्टो) में किए गए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में कई प्रमुख योजनाओं पर तेजी से काम किया है और आने वाले बजट में भी कल्याणकारी

योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए चलाई जा रही वेलफेयर स्कीम सामाजिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। लोकतंत्र में केवल आर्थिक विकास ही नहीं,

पहली बार ग्रीन बजट पर फोकस

छत्तीसगढ़ में पहली बार बिहार, दिल्ली व राजस्थान की तर्ज पर ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। ग्रीन बजट मतलब सरकार का ऐसा बजट, जिसमें पैसों की योजना और खर्च का ध्यान रखते हुए पर्यावरण को बचाने पर जोर दिया जाता है। साथ ही प्रदूषण कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर प्राकृतिक संसाधन छोड़ने पर फोकस रहता है। वित्त विभाग ने इसके हिसाब से विभागों से अलग-अलग जानकारी भी मांगी है।

2 लाख करोड़ तक पहुंचे

छत्तीसगढ़ में बजट की शुरुआत 5705 करोड़ रुपए से हुई थी। इसके बाद हर साल बजट का आकार बढ़ता गया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुख्य बजट का आकार 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपए था। इसके बाद 35 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हुआ। इसमें 1,937 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय तथा 33,063 करोड़ रुपए राजस्व व्यय शामिल है। छत्तीसगढ़ के कुल बजट का आंकड़ा 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

विधानसभा में लखमा को मंत्री-नेता किरण, अजय और धर्मजीत ने गले लगाया

विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत

रायपुर. विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई। इसमें जमानत पर रिहा पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी शामिल हुए। सत्र के दौरान जब राज्यपाल का इंतजार हो रहा था, उस बीच लखमा ने सत्तापक्ष के विधायकों से मुलाकात की। मंत्री रामविचार नेताम, विधायक अजय चंद्राकर, किरण सिंह देव और धर्मजीत ने लखमा को गले लगाया। लखमा ने सदन में सत्तापक्ष के अन्य विधायकों से भी मुलाकात की। बता दें कि लखमा को आबकारी घोटाला में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पिछले दिनों जमानत मिली थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष लखमा को सशर्त सदन में आने की अनुमति दी है।

वंदे मातरम् के सभी छंद का गायन

बजट सत्र के दौरान नई परंपरा की शुरुआत की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इसकी जानकारी दी। इसके बाद राज्यपाल के आगमन पर वंदे मातरम् के सभी छंद का गायन हुआ। इसके बाद जन-गण-मन और राजकीय गीत अरपा पैरी के धार.. का भी गायन हुआ।

बघेल ने कहा- अन्य नेताओं को मिले मौका

सदन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्यसभा की दावेदारी खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, पार्टी के अन्य नेताओं को मौका मिलना चाहिए। इसपर फैसला हाईकमान करेगा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा छत्तीसगढ़ से अपने ही नेता को भेजेंगे। इसके लिए सर्वसम्मति से फैसला होगा।

इस बार अभिभाषण में नहीं हुई टीका-टिप्पणी

सत्र की शुरुआत में राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण हुआ। लंबे समय बाद राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष की ओर से कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभिभाषण पर सदन के बाहर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इसमें नया कुछ भी नहीं था। थकी हारी सरकार पुरानी बातों को पढ़वा रही थी।

साहू समाज ने कांग्रेस-भाजपा से मांगी राज्यसभा सीट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. साहू समाज अब राज्यसभा में अपने हक और प्रतिनिधित्व के लिए मुखर हो गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष निरेन्द्र साहू के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत से मुलाकात कर समाज की भावनाओं से अवगत कराया। साथ ही कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से दूरभाष पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष साहू ने स्पष्ट रूप से कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास की धुरी रहने वाला साहू समाज प्रदेश में बहुसंख्यक और सामाजिक रूप से सबसे अग्रणी है। इसके बावजूद आज तक राज्यसभा में समाज के किसी भी व्यक्ति को अवसर नहीं मिलना चिंता का विषय है। समाज अब चाहता है कि उसकी आवाज दिल्ली के गलियारों में भी गूंजे। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों प्रमुख दलों के नेतृत्व से विनम्र आग्रह किया है कि सामाजिक संतुलन और न्याय की कसौटी पर साहू समाज को परखें। जो दल इस बार समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे प्रतिनिधि को राज्यसभा भेजेगा, समाज भी उस दल के प्रति अपनी पूरी निष्ठा और सहयोग समर्पित करेगा। इस दौरान प्रदेश संयुक्त सचिव प्रदीप साहू, गोपाल साहू, चुडामंडी साहू, रोबिन साहू, देवदत्त साहू आदि मौजूद थे।

जमीन के लिए बुजुर्ग महिला को फाइलों में 'मृत' बताया

मध्यप्रदेश: स्नूकर क्लब में 10वीं के छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला, 20 से अधिक

पत्रिका ब्यूरो @बेमेतरा. कल्पना कीजिए, आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और अपनों के बीच मौजूद हैं, लेकिन सरकारी तंत्र आपको तीन दशक पहले ही 'मुर्दा' घोषित कर चुका हो। बेमेतरा की 80 वर्षीया शैल शर्मा पिछले 34 वर्षों से इसी भयावह सच्चाई और व्यवस्था की मार झेल रही थीं। उनके अस्तित्व को मिटाने की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपनों ने ही रची थी। शैल शर्मा के संघर्ष की कहानी 1993 से शुरू होती है। उनके नाम पर एक फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया गया, जिसमें 26 मार्च 1993 को उनकी मौत दर्ज कर दी गई। शैल शर्मा को इस 'मौत' की खबर तब लगी, जब उन्होंने अपने पति की मेहनत से अर्जित संपत्ति के दस्तावेजों की जांच की। फाइलों में अब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। बीते एक दशक से शैल शर्मा दफ्तर-दर-दफ्तर भटकती रहीं। 2 सितंबर 2025 को वे स्वयं बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचीं। उनके कांपते हाथों में पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पेंशन खाते के दस्तावेज थे, यह जो चीख-चीख कर उनके जीवित होने की गवाही दे रहे थे। उनकी सिर्फ एक ही जिद थी,साहब, मुझे कागजों में नहीं, हकीकत में भी जिंदा माना जाए।

एक मां का दर्द: न्याय अभी बाकी है: शैल शर्मा के परिजन राकेश शर्मा बताते हैं कि उन्होंने वर्षों तक जो मानसिक प्रताड़ना झेली है, उसकी भरपाई नामुमकिन है। अपनी ही मौत का प्रमाण लेकर घूमना किसी त्रासदी से कम नहीं था। 34 साल बाद शुरू हुई यह कानूनी कार्रवाई अंतिम मंजिल तो नहीं, लेकिन उस इंसाफ की ओर पहला कदम जरूर है, जिसकी आस में एक मां की आंखें पथरा गई थीं।

आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने की

देशी कट्टा व जिंदा कारतूस बेचने की फिराक में घूम रहे एक नाबालिग

अंबिकापुर @ पत्रिका. देशी कट्टा व कारतूस बेचने की फिराक में घूम रहे स्कूटी सवार एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

जानकारी के अनुसार 22 फरवरी को कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली कि केनाबांध स्थित एक मेन्स पार्लर के पास तीन लड़के देशी कट्टा व कारतूस बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्कूटी सवार एक नाबालिग सहित आरोपी पीयुष दुबे पिता मनीष दुबे उम्र 18 वर्ष निवासी बौरीपारा व आकाश दास पिता स्व सहेन्दर दास उम्र 19 वर्ष निवासी केनाबांध बंगाली चौक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 नग देशी कट्टा व 1 जिन्दा कारतूस जब्त किया है। दोनों आरोपी देशी कट्टा व जिन्दा कारतूस बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

बस की चपेट में आए कांस्टेबल की मौत

बालोद @ पत्रिका. तेज रफ्तार यात्री बस की चपेट में आने से बालोद थाने में पदस्थ बाइक सवार सिपाही की मौत हो गई। हादसा सोमवार दोपहर सिवनी मार्ग पर हुआ। कांस्टेबल ठनेश कुमार टेमार्य (35), निवासी ग्राम सहगांव, दोपहर करीब साढ़े 12 बजे समन-वारंट लेकर सिवनी की ओर जा रहे थे। बालोद-झलमला मार्ग पर सिवनी मछली मार्केट के पास वे कांकेर बस सर्विस की यात्री बस से आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान वे बस की चपेट में आ गए। बाइक सहित बस के आगे गिरने से वे बस के पहिए के नीचे आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

तलाक निरस्त करने पत्नी की याचिका खारिज की हाईकोर्ट ने

आपसी सहमति के आधार पर दिए गए तलाक के आदेश को नहीं किया जा सकता खारिज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया कि आपसी सहमति के आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता। डिवीजन बेंच ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानूनी तौर पर अब तलाक निरस्त करना संभव नहीं है।

तलाक के बाद पति-पत्नी की मुलाकातों से रिश्तों में सुधार के बाद पति-पत्नी ने फिर साथ रहने का निर्णय लिया था। इस आधार पर आपसी सहमति के बाद पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में बताया कि हम दोनों के रिश्ते अब सामान्य हो गए हैं। हमने अपनी शादी की सालगिरह भी साथ-साथ मनाई है। साथ घुमने फिरने गए और होटल भी बुक कराया। रिश्तों में हुए सुधार और साथ रहने का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक की डिक्री को रद्द करने की मांग की। याचिका की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे, जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि तलाक पति-पत्नी की आपसी सहमति से हुआ है।

यह है मामला

बिलासपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाली महिला की शादी मोपका निवासी युवक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आई और दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया।परिवार न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर की। इस आधार पर परिवार न्यायालय ने तलाक की डिक्री पारित कर दी। कुछ समय बाद ही दोनों फिर मिलने लगे। तलाक के दो महीने बाद 11 मार्च से 15 मार्च 2025 तक उन्होंने मथुरा की यात्रा की।

भावनाओं से नहीं चलता कानून

पति पत्नी ने साथ-साथ रहने के कई कारण गिनाए। तलाक के बाद एक-दूसरे के साथ रहने, ट्रेन में यात्रा की टिकट, विवाह की वर्षगांठ मनाने की तस्वीरें भी प्रस्तुत की। सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि कानून भावनाओं से नहीं तथ्यों और प्रक्रियाओं से चलता है। कानूनी प्रावधानों का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा कि आपसी सहमति के आधार पर जब एक बार परिवार न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री पारित कर दी जाती है तब उसे रद्द नहीं किया जा सकता।

मुख्यमंत्री से भाप्रसे में नियुक्त हुए अधिकारियों ने की मुलाकात

अपने दायित्वों का संवेदनशीलता से निर्वहन करें अधिकारी: साय

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सोमवार को विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में राज्य प्रशासनिक सेवा तथा एलाइड सर्विस से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त अधिकारियों ने मुलाकात की। साय ने सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति न केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह जनसेवा के व्यापक अवसरों और जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के

साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा, शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों की सक्रिय भूमिका से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त तीर्थराज अग्रवाल, लीना कोसम, बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, सुमित अग्रवाल, संदीप कुमार अग्रवाल, आशीष कुमार टिकरिहा, ऋषभ पाराशर एवं तरुण किरण उपस्थित थे।

आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा, आरटीआई में भी थमा दिया कूटरचित दस्तावेज

पामगढ़@ पत्रिका. महिला एवं बाल विकास विभाग के पामगढ़ परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता-सहायिका भर्ती में फजीवाड़े का नया रिकार्ड बनता जा रहा है। सालभर पहले भी यहां आधा दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता-सहायिका भर्ती पर फजीवाड़ा सामने आया था जिसके दोषियों पर आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसी तरह का फर्जीवाड़ा फिर से ग्राम पंचायत झूलन के मदनपुर आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 14 में किया गया है। जहां सहायिका पद पर ऐसे आवेदिका को नियुक्ति दे दी गई, जिसका परित्यक्ता प्रमाण पत्र ही पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद की तारीख में जारी हुआ है। ग्राम पंचायत ने स्वयं इसकी पुष्टि की है और पंचायत में मौजूद पंजी रजिस्टर में भी परित्यक्ता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख है। मामले की लिखित शिकायत भी एक आवेदिका सरस्वती चौहान ने की थी मगर दावा आपत्ति को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और अधिकारियों ने नियुक्ति कर दी।

मार्केट हमेशा सही नहीं होता, लेकिन वह आपको गलत जरूर साबित कर सकता है। बाजार में भावनाएं कीमत तय करती हैं, लेकिन अंत में फैक्ट्स जीतते हैं।
कार्ल इकान अमरीकी बिजनेसमैन

पत्रिका फाइनेंस
@बिजनेस & वेल्थ

रेवेन्यू मीटर...
ये कंपनियां नकदी की राजा, इनके पास सबसे ज्यादा कैश
(सालाना फ्री कैश-फ्लो (नकदी) करोड़ रुपए में)

भारती एयरटेल	ओएनजीसी	टीसीएस	रिलायंस	इंफोसिस
58,990	50,154	45,000	41,000	33,457

शेयर बाजार सेंसेक्स 480 अंक चढ़ा, पर जेफरीज के रेटिंग डाउनग्रेड से आइटी शेयरों में गिरावट जारी

ट्रंप टैरिफ पर कोर्ट की रोक से दलाल स्ट्रीट में बहार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्रंप टैरिफ खारिज करने से भारत सहित दुनियाभर के शेयर बाजारों का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ। निवेशकों का भरोसा बढ़ा और बाजार में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 480 अंक चढ़कर 83,294 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 142 अंक चढ़ 25,713 पर बंद हुआ। बैंकिंग-फाइनेंशियल शेयरों में तेजी ने भी बाजार को सपोर्ट दिया। हालांकि, आइटी शेयरों में दबाव ने बाजार की बढ़त सीमित कर दिया। जियोजित इंवेस्टमेंट्स के विनोद नायर ने कहा, निवेशक अब ट्रंप की संशोधित रणनीति और अन्य देशों के साथ संभावित पुनः वार्ताओं के दायरे पर अधिक स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं।

आइटी शेयरों में इतनी गिरावट

कंपनी	सोमवार को	2026 में अब तक
कोफोर्ज	-3.85	-22.15
एलेक्सी	-3.27	-9.81
केपीआइटी	-2.92	-30.28
हेक्सावेयर	-3.22	-33.48
एमफैसिस	-3.11	-18.69
परसिस्टेंट	-2.40	-20.89
विप्रो	-1.89	-22.98
इंफोसिस	-1.86	-18.52
एलटीआइएम	-1.37	-21.10
टेक महिंद्रा	-1.35	-10.61
एचसीएल	-0.80	-12.82
टीसीएस	-0.45	-17.15

गिरावट के आंकडे फीसदी में

480 **अंक** चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी भी ***0.55% की बढ़त के साथ 25,713 पर बंद***

5% टूटे एचएएल के शेयर ***तेजस का एयरबेस पर ब्रेक फेल होने से***

आइटी शेयरों की रेटिंग घटाई, स्टॉक्स दबाव में

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने आइटी सेक्टर को डाउनग्रेड करते हुए कहा, एआइ से जुड़ा डिसरप्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद कई बड़े आइटी शेयर 3% फिसल गए। जेफरीज ने कहा, 2026 की शुरुआत से अब तक आइटी शेयरों में 16% गिरावट के बावजूद जोखिम खत्म नहीं हुआ है। अगर आइटी सेक्टर पर एआइ का असर ज्यादा गहरा रहा तो शेयरों में मौजूदा स्तर से 30 से 65% तक गिरावट की आशंका बन सकती है। जेफरीज ने प्रति शेयर आय (ईपीएस) अनुमान 4% तक घटा दिए और 6% रहने का अनुमान है। कई शेयरों के टारगेट प्राइस में 33% तक कटौती की है।

कमोडिटी एनएसई पर 16 मार्च से 10 ग्राम गोल्ड अनुबंध शुरू होगा

छोटे निवेशक सोने के वायदा कारोबार में उतर सकेंगे, टैरिफ से सोना-चांदी चढ़े

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) आम लोगों के लिए सोने का व्यापार आसान करने जा रहा है। इसके तहत 16 मार्च 2026 से कमोडिटी श्रेणी में 10 ग्राम सोने के वायदा अनुबंध (गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट) उपलब्ध होंगे। इस सुविधा से अब छोटे निवेशकों भी छोटे आकार के गोल्ड अनुबंध में कारोबार कर सकेंगे। इस योजना को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। इस अनुबंध में सोमवार से शुक्रवार तक कारोबार होगा, जिसका समय सुबह 9 बजे से रात 11:30 बजे तक रहेगा। इस व्यवस्था के तहत 999 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की डिलीवरी लेना पूरी तरह अनिवार्य रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे आकार का यह गोल्ड अनुबंध घरेलू बुलियन कारोबार के ज्यादा करीब है, जिससे छोटे निवेशकों और ट्रेडर्स की भागीदारी बढ़ेगी। इससे कम पूंजी वाले निवेशकों के लिए भी सोने के वायदा कारोबार में प्रवेश आसान हो जाएगा और बाजार में तरलता बढ़ने की उम्मीद है।

कीमत अहमदाबाद के भाव पर तय होगी: डिलीवरी केंद्र अहमदाबाद में तय क्लियरिंग हाउस सुविधा पर होगा। सोने की गुणवत्ता 999 शुद्धता की होगी और यह मान्यता प्राप्त सप्लायर की ओर से दिया जाएगा। अनुबंध की कीमत अहमदाबाद के भाव पर तय होगी, जिसमें सीमा शुल्क तो शामिल होगा, लेकिन जीएसटी का भुगतान अलग से करना होगा। अधिकतम ऑर्डर साइज 10 किलोग्राम तय किया गया है।

गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का ***अधिकतम ऑर्डर साइज 10 किलोग्राम तय किया गया है,*** डिलीवरी लेना अनिवार्य

हर महीने समाप्ति

एनएसई का यह नया वायदा अनुबंध हर महीने की श्रृंखला में उपलब्ध होगा। इसका कारोबारी चिन्ह 'गोल्ड10जी' तय किया गया है। हर महीने के आखिरी कैलेंडर दिन इस अनुबंध की समाप्ति होगी। अगर उस दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है, तो उससे पहले का कार्यदिवस समाप्ति तिथि माना जाएगा। पुराने अनुबंध की समाप्ति के तुरंत बाद अगले कारोबारी दिन नया अनुबंध शुरू हो जाएगा।

जोखिम प्रबंधन ऐसे होगा बाजार के जोखिम को कम करने के लिए एनएसई ने दैनिक कीमत की सीमा 6% प्रतिशत तय की है। अगर भाव में भारी बदलाव होता है तो 15 मिनट के कूलिंग-ऑफ पीरियड के बाद इसे 9% तक किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेज उतार-चढ़ाव की स्थिति में नियामकीय प्रावधानों के अनुसार सीमा को और बढ़ाया जा सकता है।

सोना 1.61 लाख पार, चांदी में तूफानी उछाल

डॉनल्ड ट्रंप की ओर से ग्लोबल टैरिफ 15% करने से ट्रेड अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे सोन-चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आई है। ग्लोबल बाजार में सोना फिर 1% से ज्यादा चढ़कर 5175 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं चांदी 87 डॉलर प्रति औंस पर रही, इससे भारतीय वायदा बाजार एमसीएक्स पर सोना 2% की तेजी के साथ 1.61 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी करीब 6% यानी 15,000 रुपए से ज्यादा चढ़कर 2.68 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई।

केंद्रीय बैंक जिम्मेदार: सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सोने की कीमतों में उछाल के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, कीमतों में तेजी इसलिए आई है क्योंकि वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। वहीं आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि सोने की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन आयात ऑर्डरों के कुल मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

डीजीएफटी

रोडटैप दरें आधी, निर्यातकों में रोष

जयपुर@ पत्रिका. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक आदेश जारी कर देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर दिए जा रहे रोडटैप (रेमीशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स) की दरों को तुरंत प्रभाव से आधी कर दी है। विदेश व्यापार महानिदेशक लव अग्रवाल की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। रोडटैप स्कीम एक जनवरी 2021 से लागू की गई थी। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश ने बताया कि इस स्कीम के माध्यम से केंद्र सरकार निर्यात होने वाले माल पर वसूले गए जीएसटी से इतर ऐसे करों और ड्यूटीज की वापसी निर्यातकों को करती है, जिनकी वास्तविक गणना संभव नहीं हो पाती है। इनमें पेट्रोल-डीजल पर वसूले गए टैक्स, मंडी टैक्स इत्यादि शामिल हैं तथा इनकी वापसी केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफरेबल स्क्रिप के माध्यम से निर्यातकों को की जाती है।

ट्रंप ने फिर दी धमकी अगर अमरीका से रद्द की ट्रेड डील, तो लगा देंगे बहुत ज्यादा टैरिफ

15% टैरिफ के बावजूद 34 अरब डॉलर निर्यात पर नहीं लगेगा शुल्क

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद डॉनल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए नए 15% टैरिफ के बावजूद भारत के 34 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात पर कोई अतिरिक्त आयात शुल्क नहीं लगेगा। यानी भारतीय निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ड्यूटी-फ्री बना रह सकता है। इन छूटों में सबसे बड़ा योगदान सिविल एविएशन (नागरिक उड्डयन) से जुड़े उत्पादों का है। सिर्फ इस सेक्टर में ही लगभग 5.77 अरब डॉलर का निर्यात शुल्क मुक्त श्रेणी में आ सकता है। अमरीकी ट्रेड एक्ट की सेक्शन 122 के तहत प्रस्तावित नए टैरिफ उपाय अमरीकी राष्ट्रपति को अधिकतम 15% तक का शुल्क 150 दिन के लिए लगाने की अनुमति देते हैं।

ट्रंप की नई धमकी

ट्रंप ने सोमवार को चेतावनी दी कि जो देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमरीका के साथ ट्रेड डील रद्द कर देंगे, वे उन देशों पर अलग ट्रेड कानूनों के तहत बहुत अधिक टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह ट्रेडिंग पार्टनर्स पर लाइसेंस फीस भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनके अगले टैरिफ कदमों को लेकर अनिश्चितता ने इकोनॉमी को जकड़ लिया है और स्टॉक्स नीचे आ गए हैं। ट्रंप ने लिखा, कोई भी देश जो सुप्रीम कोर्ट के अजीब फैसले के साथ 'गेम खेलना' चाहता है, खासकर वे जिन्होंने दशकों तक अमरीका को 'धोखा' दिया, उन्हें बहुत ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने धमकी दी कि जो देशों से हाल में ट्रेड डील पर सहमत हुए हैं, वे पीछे हटे तो उन पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे।

इन उत्पादों को मिलेगी टैरिफ-फ्री एंट्री

उत्पाद	निर्यात
फार्मास्यूटिकल्स	10.6
सिविल एविएशन	5.77
स्मार्टफोन	6.8
कम्युनिकेशन	1.8
इलेक्ट्रॉनिक्स	4.95
पेट्रोलियम प्रोडक्ट	4.2

(राशि अरब डॉलर में)

88 अरब डॉलर रहा 2024-25 में भारत से अमरीका को होने वाला वस्तुओं का कुल निर्यात

10 प्रमुख उत्पाद श्रेणियां रह सकती हैं शुल्क मुक्त

सहमति की उम्मीद

प्रस्तावित टैरिफ में दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर को पहले की तरह छूट दी गई है। सिविल एविएशन उत्पादों को भी नई छूट की सूची में शामिल किया गया है। यह छूट भारत-अमरीका व्यापार वार्ताओं का हिस्सा थीं, जिनका निष्कर्ष मार्च में निकाला जाना तय है। यानी दोनों देशों के बीच बातचीत के दौरान इन सेक्टरों को राहत देने पर सहमति बनती दिख रही है। प्रस्तावित टैरिफ ढांचे के तहत जिन उत्पादों को छूट दी गई है, उनमें टॉप 10 श्रेणियां सबसे बड़ा हिस्सा रखती हैं। ये मिलकर 24 अरब डॉलर के व्यापार का प्रतिनिधित्व करती हैं।

यूरोप और भारत का सख्त रुख

ट्रंप की ओर से सभी देशों पर 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसलों का असर दूसरे देशों पर भी दिखने लगा है। ईयू ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप की ओर बढ़ाए गए टैरिफ को मंजूरी नहीं देगा। ईयू की संसद ने अमरीका से ट्रेड डील पर वोटिंग रोक दी है। भारत ने भी अमरीका के साथ व्यापार बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। इन सब वजहों से दुनिया में व्यापार का माहौल उलझ गया है। ईयू ने कहा, अमरीका पिछले साल हुए व्यापार समझौते की शर्तों का पालन करे। अदालत के फैसले के बाद अमरीका को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह आगे क्या कदम उठाने वाला है। ईयू ने कहा, डील तो डील होता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप की ओर से घोषित 15% के नए टैरिफ क्या व्यापार समझौतों को दरकिनार कर देंगे। यदि ऐसा होता है, तो ईयू को ट्रेड डील में मिली शून्य-टैरिफ (जीरो ड्यूटी) छूट खत्म हो सकती है।

टैरिफ से होने वाली वसूली आज से बंद टैरिफ से अमरीकी सरकार को जो राजस्व मिल रहा था, वह रुक जाएगा। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने कहा, आइईईपीए के तहत हो रही टैरिफ की वसूली मंगलवार से बंद कर दी जाएगी। हालांकि सेक्शन 232 और 301 के तहत लगाए गए टैरिफ जारी रहेंगे। रिफंड को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।

भारत सहित इन देशों को हो सकता है फायदा

15% शुल्क कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए यह ट्रेड डील में तय 18% की तुलना में काफी कम और स्थिर है। टैरिफ में इस बदलाव का फायदा भारत के साथ चीन, दक्षिण कोरिया और ब्राजील जैसे देशों को मिलेगा। पर ब्रिटेन, ईयू, ऑस्ट्रेलिया व सऊदी अरब जैसे देशों को नुकसान हो सकता है, जिन्होंने अमरीका से कम शुल्क पर ट्रेड डील की है।

सोलर पैनल: अमरीका जल्द यह फैसला करेगा कि भारत, लाओस व इंडोनेशिया से आयात किए जाने वाले सोलर सेल-पैनलों पर एंटी-सब्सिडी शुल्क लगाया जाए या नहीं। अमरीका जांचेगा कि इन देशों में कंपनियों को अनुचित सब्सिडी तो नहीं मिल रही।

बीएफएसआइ

मेट्रो नहीं, छोटे शहर बने रोजगार के इंजन

मुंबई@ पत्रिका. भारत में लगभग 70 प्रतिशत नौकरियां गैर-मेट्रो यानी टियर-2 और टियर-3 शहरों में उपलब्ध हैं। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले टियर-3 शहरों में 40 प्रतिशत रोजगार है, जबकि टियर-2 शहरों में 29 प्रतिशत रोजगार मिलता है। इसके मुकाबले टियर-1 शहरों की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत है। बीएफएसआइ (बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा) और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मिलकर टियर-3 शहरों के 45 प्रतिशत से अधिक कार्यबल को रोजगार दे रहे हैं।

आइडीएफसी बैंक शेयर 16% टूटे, क्या सुरक्षित है आपका पैसा?

धोखाधड़ी ₹590 करोड़ की, पर एक दिन में ही ₹14,300 करोड़ बाजार पूंजी साफ

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. आइडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खातों में बैंक कर्मचारियों की ओर से लगभग 590 करोड़ रुपए की संदिग्ध धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद सोमवार को बैंक के शेयर 16% टूट गए। इससे एक दिन में ही बैंक के निवेशकों के 14,300 करोड़ रुपए साफ हो गए। खुदरा निवेशकों को जहां 2163 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, वहीं भारत सरकार के 1,114 करोड़ रुपए और एलआइसी के 338 करोड़ रुपए डूब गए। आइडीएफसी में सरकार की 7.75% हिस्सेदारी है। सोमवार को बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह मामला चंडीगढ़ शाखा में मौजूद हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ विशेष खातों तक सीमित है। शाखा के सभी ग्राहकों के खाते इस अनियमितता से प्रभावित नहीं हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विस्तृत आंतरिक जांच और ऑडिट की प्रक्रिया जारी है।

शेयर टूटने से किसे कितना नुकसान

निवेशक	बाजार पूंजी घटी
भारत सरकार	-1,114
एलआइसी	-338
आइसीआइसीआइ लाइफ	-299
एचडीएफसी लाइफ इंश्यो.	-318
खुदरा निवेशक	-2163

(राशि करोड़ रुपए में)

₹1114 करोड़ साफ हो गए सरकार के, आइडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरों में आई भारी गिरावट से, ***एलआइसी को भी 338 करोड़ का घाटा***

कैसे सामने आया मामला?

यह अनियमितता उस समय उजागर हुई जब हरियाणा सरकार के एक विभाग ने अपना खाता बंद कर शेष राशि किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। जब बैंक ने प्रक्रिया शुरू की तो विभाग की ओर से बताए गए बैलेंस और बैंक के रेकॉर्ड में दर्ज राशि के बीच अंतर पाया गया। इसी विसंगति ने पूरे मामले को उजागर किया। इसके बाद अन्य सरकारी विभागों ने भी अपने खातों का मिलान करना शुरू किया। जांच के दौरान पाया गया कि उसी शाखा में मौजूद कुछ अन्य सरकारी खातों में भी इसी तरह की गड़बड़ियां हैं। बैंक ने शक के आधार पर चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। लेनदेन की जांच के लिए बैंक ने एक स्वतंत्र एजेंसी को फोरेंसिक ऑडिट का जिम्मा सौंपा है।

अन्य बैंकों को भेजा रिकॉल अनुरोध बैंक ने अन्य बैंकों को रिकॉल अनुरोध भेजा है, ताकि संदिग्ध खातों में मौजूद राशि पर रोक लगा सके। बैंक के एमडी वी वैद्यनाथन ने कहा, ऐसा संकेत नहीं मिला कि देश भर में मौजूद बचत खाते, एफडी या आम ग्राहकों के खाते प्रभावित हुए हों।

सेविंग सुकन्या समृद्धि में 2.27 लाख करोड़

पोस्ट ऑफिस में भारतीयों का जमा ₹22 लाख करोड़ के पार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. पोस्ट ऑफिस सिर्फ चिट्ठियां भेजने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि देश के करोड़ों लोगों के लिए भरोसेमंद बैंकिंग विकल्प बन चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स में लोगों की कुल जमा राशि 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और पोस्ट ऑफिस खातों की संख्या लगभग 38 करोड़ है, जो दर्शाती है कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पोस्ट ऑफिस पर लोगों का भरोसा बेहद मजबूत है। सामान्य बचत ही नहीं, सरकारी योजनाओं में भी लोगों ने बड़ी रकम जमा की है। खास तौर पर सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए बनाई गई है, इसमें करीब 3.8 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और जमा राशि 2.27 लाख करोड़ रुपए है।

खर्च ज्यादा, कमाई कम

हालांकि डाक विभाग अभी भी वित्तीय संतुलन की चुनौती से जूझ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, विभाग का वार्षिक खर्च लगभग 35,000 करोड़ रुपए है, जबकि इनकम करीब 13,000 करोड़ रुपए के आसपास है। कुछ राज्यों में तो खर्च आय से कई गुना ज्यादा है। पोस्ट ऑफिस की योजनाएं सरकारी गारंटी के साथ आती हैं, इसलिए जोखिम कम माना जाता है। यही वजह है कि बुजुर्ग, ग्रामीण परिवार और छोटे निवेशक बड़े पैमाने पर यहां पैसा जमा करते हैं। देशभर में करीब 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस और लगभग 4.5 लाख कर्मचारी हैं।

फिर बदला मौसम... ओले-बारिश से फसलों को नुकसान

नई दिल्ली @ पत्रिका. बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर एवं पश्चिमी विक्षोभ के हल्के के प्रभाव से फरवरी माह में चौथी बार मौसम ने करवट ली है। इससे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ समेत राजस्थान के कुछ भागों में हल्की बारिश व बादल छाए रहने का मौसम बन गया है। सोमवार को मध्यप्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली सहित विंध्य अंचल के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। शिवपुरी व सीधी जिले के कई क्षेत्रों बारिश के साथ चने से बड़े आकार के ओले गिरे। सरसों, टमाटर और गेहूं सहित अन्य फसलों को नुकसान होने की जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले खुले में पड़ी धान की फसल को नुकसान होने की आशंका है। राजस्थान के कई जिलों में बादल छाने से तापमान में गिरावट हुई। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 26 फरवरी तक पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, केरल और यनम में बारिश की संभावना है।

इन दिनों में कुछ जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। वहीं 26 से 28 फरवरी तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी की संभावना है।

भारत दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी

नई दिल्ली @ पत्रिका. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर आएंगे। वह 26 फरवरी से 7 मार्च तक चलने वाले अपने तीन देशों के दौरे के दौरान भारत की यात्रा करेंगे। पीएम कार्नी पहले मुंबई पहुंचेंगे।

नेपाल: नदी में गिरी बस, दो विदेशी समेत 17 की मौत

काठमांडू @ पत्रिका. नेपाल के धाडिंग जिले में रविवार देर रात पोखरा से काठमांडू जा रही एक बस त्रिशूली नदी में गिर गई। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कुछ विदेशी भी हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता बिष्णु प्रसाद भट्ट ने बताया कि रात डेढ़ बजे पृथ्वी राजमार्ग पर बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। अब तक 17 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। जबकि 28 घायलों को भी निकाला गया है। मरने वालों में एक ब्रिटिश और एक न्यूजीलैंड का नागरिक भी शामिल है। मारे गए लोगों में अब तक 9 की पहचान हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट न्यूज

नीट-पीजी कट-ऑफ में कटौती पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

नई दिल्ली @ पत्रिका. सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2025-26 के लिए क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल में की गई भारी कटौती के मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कट-ऑफ घटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत इसका परीक्षण करेगी।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सबसे बड़ी चिंता शिक्षा की गुणवत्ता है और सरकार को तय करना होगा कि कट-ऑफ में कटौती से मानक प्रभावित न हों। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी कि सीटें खाली रहने के कारण निर्णय लिया गया तथा नीट-पीजी न्यूनतम क्लिनिकल दक्षता का प्रमाणन नहीं, बल्कि सीमित सीटों के लिए मेरिट सूची तैयार करने की परीक्षा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से फीस असमानता और निजी कॉलेजों की ऊंची फीस का मुद्दा भी उठाया गया। अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

पसमांदा मुस्लिमों को आरक्षण पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली @ पत्रिका. सुप्रीम कोर्ट पसमांदा मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में 10% आरक्षण देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। सीजेआइ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद वसीम सैफी की अर्जी पर प्रारंभिक सुनवाई की। याचिका में रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी में उप-वर्गीकरण कर पसमांदा मुसलमानों को अलग 10% आरक्षण देने की मांग की गई है। सीजेआइ ने सवाल किया कि क्या पसमांदा ही सांख्यिकीय रूप से सबसे पिछड़े हैं और अन्य गरीब मुसलमानों का क्या होगा।

नए लॉ कॉलेजों पर लगी रोक हटाई: बीसीआइ

नई दिल्ली @ पत्रिका. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर लगाया गया तीन साल का मोराटोरियम वापस ले लिया है। यह जानकारी बीसीआइ की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को दी गई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ व्यावसायिक शिक्षा फाउंडेशन सोसायटी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2025 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। बीसीआइ के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिका निस्तारित कर दी और याचिकाकर्ता को 2025-26 सत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी।

जेएनयू: दो गुटों में झड़प, पत्थरबाजी के आरोप

नई दिल्ली @ पत्रिका. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में रविवार देर रात एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प हुई। विवाद तब शुरू हुआ जब जेएनयू छात्र संघ ने निष्कासन और अन्य मुद्दों को लेकर स्कूलों में 'लॉकडाउन' का आह्वान किया, जिसका एबीवीपी ने विरोध किया। इस पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों, रॉड और पत्थरबाजी से हमला करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस हिंसा में कई छात्र घायल हुए हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। घटना से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इन वीडियो में कुछ नकाबपोश छात्रों को कैंपस में घूमते हुए भी देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

हादसा: रनवे पर तेजस का ब्रेक फेल

नई दिल्ली @ पत्रिका. भारतीय वायुसेना में शामिल स्वदेशी हल्के युद्धक विमान तेजस का एक अग्रिम मोर्चे के एयरबेस पर ब्रेक फेल हो गया। इस कारण विमान रनवे से आगे निकल गया। जिससे विमान को नुकसान भी हुआ है। हालांकि विमान का पायलट सुरक्षित है।

पेज एक का शेष...

महाराणा मेवाड़...

इससे पहले 20 फरवरी को कर्नल जेम्स टॉड सम्मान अमरीका की डॉ. मॉली एम्मा एटकिन, हल्दीघाटी सम्मान वरिष्ठ पत्रकार कमलेश किशोर सिंह, पर्यावरण संरक्षण के लिए महाराणा उदय सिंह सम्मान मरिमुथु योगनाथन को और पन्नाधाय सम्मान 35,000 फीट पर जेट एयरवेज में सुरक्षित प्रसव पर आठ क्रू सदस्यों को देने की घोषणा हो चुकी है।

इन प्रतिभाओं को सम्मान:

■ **महर्षि हारीत राशि सम्मान :** 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे को 50 दिन तक पूर्ण स्मरण शक्ति के आधार पर शुक्ल यजुर्वेद (माध्यंदिन शाखा) के दुर्लभ दंडक्रम विकृतिपाठ का संपादन पर।

■ **महाराणा कुंभभ सम्मान :** भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं इतिहास में योगदान के लिए उदयपुर के साहित्यकार तरुण कुमार दाधीच को।

■ **महाराणा सज्जनसिंह सम्मान :** ललित कला क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट अजय रावत को।

■ **डागर घराना सम्मान:** संगीत के क्षेत्र में प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को।

■ **राणा पूंजा सम्मान:** आदिवासी समाज के उत्थान के लिए मांडना कलाकार डिंपल चण्डात को।

■ **अरावली सम्मान (खेल):** भारतीय नौसेना के चीफ पेटी ऑफिसर एवं अल्ट्रा-मेराथन धावक राम रतन जाट और टोक्यो पैरालंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनि लेखरा को।

■ **विशेष सम्मान :** मेवाड़ की 500 वर्ष पुरानी पवित्र जल सांझी परंपरा के संरक्षण के लिए उदयपुर के राजेश वैष्णव को।

60 देशों...

यह पहल पारंपरिक कूटनीति के साथ-साथ संसदीय स्तर पर संवाद को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजे थे। अलग-अलग दलों और विचारधाराओं के नेताओं को एक साथ लाकर यह संदेश दिया गया कि देश की सुरक्षा और हितों के मामले में भारत एकजुट है। पहले चरण में जहां 60 से देशों के साथ मैत्री समूहों का गठन किया गया है, वहीं निकट भविष्य में कई अन्य देशों के साथ इन समूहों के गठन के प्रयास किए जा रहे हैं।

इन नेताओं को मिली लीडरशिप: वरिष्ठ नेताओं में रवि शंकर प्रसाद, डॉ. एम. थंबीदुरई, पी. चिदंबरम, प्रो. राम गोपाल यादव, टी.आर. बालू, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, गौरव गोगोई, कनिमोझी करुणानिधि, मनीष तिवारी, डेरेक ओ'ब्रायन, अभिषेक बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, के.सी. वेणुगोपाल, राजीव प्रताप रूडी, सुप्रिया सुले, संजय सिंह, बैजयंत पांडा, शशि थरूर, निशिकांत दुबे, अनुराग सिंह ठाकुर, भर्तृहरि महताब, डी. पुरंदेश्वरी, संजय कुमार झा, हेमा मालिनी, बिप्लब कुमार देब, डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, जगदंबिका पाल, संबित पात्रा, अपराजिता सारंगी, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, पी.वी. मिधुन रेड्डी और प्रफुल्ल पटेल सहित कई अन्य नेता शामिल हैं।

मणिपुरी फिल्म...

लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुए समारोह में यह अवॉर्ड मशहूर काल्पनिक किरदार पैडिंगटन बियर के हाथों दिलवाया गया। पुरस्कार लेते हुए लक्ष्मीप्रिया देवी ने अपने गृह राज य मणिपुर में शांति के लिए भावुक अपील भी की। फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर व रितेश सिधवानी भी समारोह में मौजूद थे। समारोह में प्रजेंटर के रूप में शामिल हुईं अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने भाषण की पहली पंक्ति हिंदी बोलते हुए दर्शकों को चौंका दिया। 'इन मेमोरियम' श्रेणी में दिवंगत हस्तियों को याद किया गया, इसमें भारतीय दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि दी गई।

'वन बैटल...' ने जीती बाजी: पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनॉदर' ने 14 नॉमिनेशंस में से 6 अवॉर्ड जीते, वहीं, 'सिनर्स' का भी दबदबा देखने को मिला। इसने 13 नॉमिनेशंस में से 3 अवॉर्ड अपने नाम किए। गुइलेर्मो डेल टोरो की 'फ्रैंकेंस्टीन' ने भी 3 अवॉर्ड जीते। बेस्ट फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनॉदर' रही, वहीं बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले और बेस्ट एक्टर एक्टर रॉबर्ट आरामयो रहे।

अमर उजाला

प्रवाह

77 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 24 फरवरी 2026

एआई महज एक उपकरण है। इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। -ओरेन एट्जियोनी

अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका समूह में शामिल होना भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। हालांकि, चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने में इसकी कामयाबी कई पहलुओं पर निर्भर करेगी।

पैक्स सिलिका और भारत

हाल ही में भारत द्वारा पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाली इस पहल में उसका औपचारिक तौर पर शामिल होना रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और तकनीक आपूर्ति शृंखला में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करना है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन ने पिछले वर्ष दिसंबर में इस समूह की शुरुआत की थी, पर प्रारंभिक सूची में भारत को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, एआई शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का यह कहना वैश्विक परिदृश्य में भारत के बढ़ते कद को ही दर्शाता है कि भारत प्रतिभा का भंडार है और इसकी इंजीनियरिंग क्षमताएं इस गठबंधन को मजबूत ही बनाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पैक्स सिलिका में भारत का प्रवेश महज प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक और आवश्यक भी है। नहीं भूलना चाहिए कि दुर्लभ खनिजों के वैश्विक उत्पादन में 90 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाला चीन पिछले कुछ वर्षों में एआई और सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला के मामले में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है, जिसे अमेरिका अपने लिए एक बड़ी चुनौती मान रहा है। गौरतलब है कि आज ये दुर्लभ खनिज कंप्यूटर चिप से लेकर कार व मिसाइल बनाने तक काम आते हैं और यही वजह है कि इस मामले में चीन पर निर्भरता को भारत समेत कई देश अपनी सामरिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय मान रहे हैं। खासकर, भारत के लिए यह भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देश के तकनीकी और आर्थिक भविष्य से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों व अवसरों का सीधा समाधान हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने चिप डिजाइन, निर्माण तथा एआई शोध को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किए हैं और इससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए काफी निवेश भी आकर्षित किया है। एक अंतरराष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा होने से भारत को अधिक निवेश, तकनीक सहयोग और संयुक्त अनुसंधान साझेदारी को आकर्षित करने में तो मदद मिलेगी ही, उसके तकनीक बुनियादी ढांचे में पूंजी लगाने पर विचार कर रही वैश्विक कंपनियों का भी भरोसा बढ़ेगा। कुल मिलाकर, यह भारत को अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय साझेदारों जैसी प्रमुख तकनीक शक्तियों से घनिष्ठता से जोड़ेगा। लिहाजा, यह कदम वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। देखने वाली बात होगी कि चीन इस पर क्या रुख अपनाता है, जिसके साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। हालांकि, ट्रंप जिस तेजी से अपनी योजनाएं बदलते रहते हैं, उसे देखते हुए पैक्स सिलिका की कामयाबी उनके रुख के साथ इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इसके साझेदार केवल बातचीत पर निर्भर न रहकर एक ठोस व सुरक्षित तकनीकी नेटवर्क के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें।

ताकि एआई दुःस्वप्न न बने

एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन से भारत को जो हासिल हुआ है और इस दौरान जो उत्साह दिखा, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एआई के संभावित खतरों के मद्देनजर इसे लेकर जागरूकता, नैतिकता और सावधानियों पर भी चर्चा होनी चाहिए।

इन दिनों देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकारी अभियानों से लेकर स्टार्टअप खड़ा करने तक, स्वास्थ्य सेवा से लेकर खेती तक, एआई को वह ताकत माना जा रहा है, जो भारत को भविष्य की ओर ले जाएगा। हाल ही में, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इसकी गति को दर्शाया गया, जिसमें नीति निर्माताओं, आंत्रप्रेन्योर्स और स्वयंसेवी संगठनों ने जोखिम और फायदों पर बहस की। मगर इस उत्साह के बीच, एक गंभीर सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और वह यह कि लाखों भारतीय इस प्रौद्योगिकी से अनजान हैं, जबकि इसका पहले से ही फायदा उठाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर पाना और उसके बारे में जागरूक होना एक जैसा नहीं है।

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

इस साल की शुरुआत में, बंगलूरू में एक 22 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर धोखाधड़ी का शिकार हो गया। उसने एक डेटिंग एप पर साइन अप किया और 'इशानी' नाम की प्रोफाइल से दोस्ती की। उसे यह नहीं पता था कि 'इशानी' एक एआई निर्मित डीपफेक तरीका था। बातचीत जब व्हाट्सएप पर होने लगी, तो धोखेबाज ने उसे वीडियो कॉल के दौरान कपड़े उतारने के लिए कहा। और उस वीडियो कॉल को चुपके से रिकॉर्ड करके पीड़ित को कई अकाउंट में 1.5 लाख रुपये भेजने के लिए ब्लैकमेल किया। पुलिस का मानना है कि धोखा करने वालों ने नकली महिला को असली दिखाने के लिए एआई से बने वीडियो का इस्तेमाल किया। पीड़ित को लगा कि वह किसी जिंदा इन्सान से बात कर रहा है। यह आकलन उसे बहुत महंगा पड़ा। यह अकेली घटना नहीं है। डेटिंग एप्स पैसों से लेकर यौन शोषण तक की धोखाधड़ी के लिए मुफीद बन गए हैं। एआई अब इन चीजों को और बढ़ा रहा है, जिससे नकली पहचान ज्यादा प्रभावी हो गई है।

बंगलूरू का मामला याद दिलाता है कि जैसे-जैसे एआई टूल्स आसानी से मिल रहे हैं, वैसे-वैसे इससे होने वाले अपराध भी बढ़ रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई लोग वीडियो कॉल पर मौजूद व्यक्ति को असली मान लेते हैं, जिससे अक्सर ऐसे अपराध होते हैं। डेटिंग एप्स से जुड़े यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए उपयोगकर्ताओं से सावधान रहने की अपील की जाती है। यह कमजोरी एक और परेशान करने वाली बात से जुड़ी है। प्यू रिसर्च सेंटर के 25 देशों में किए गए एक वैश्विक सर्वे से पता चला है कि एआई के बारे में जागरूकता के मामले में भारतीय सबसे निचले पायदान पर हैं। सिर्फ 14 प्रतिशत वयस्क भारतीयों ने कहा कि उन्होंने एआई के बारे में 'कुछ सुना या पढ़ा है', जबकि दूसरे 32 प्रतिशत ने 'थोड़ा' सुना है। कुल मिलाकर, यह 46 फीसदी जागरूकता का स्तर सर्वे किए गए सभी देशों में सबसे कम है। 18-34 साल के युवाओं में, जागरूकता सिर्फ 19 फीसदी थी, केन्या के बाद दूसरी सबसे कम। इसके उलट, जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में 90 फीसदी से ज्यादा लोग इसके बारे में जानते थे। हैरानी की बात है कि कम जागरूकता के बावजूद, लगभग 89 फीसदी भारतीयों ने अपनी सरकार की एआई को विनियमित करने की क्षमता पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया। यह 'बिना जानकारी के भरोसे' वाली बात बताती है कि नागरिक विनियमन को सरकार का काम मानते हैं, अपना नहीं। पर बिना समझ के भरोसा लोगों को छेड़छाड़ और दुरुपयोग का शिकार बना देता है।

भारत में तेजी से डिजिटल बदलाव हो रहा है। शहरी पेशेवर शायद बिना जाने रोज एआई संचालित उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को ज्यादातर पता नहीं होता कि यह तकनीक कैसे काम करती है। यह अंतर इसलिए मायने रखता है, क्योंकि धोखा खाने का मतलब सिर्फ लोगों के साथ धोखाधड़ी होना नहीं है। यह देश के एआई लक्ष्यों को कमजोर करता है। जब नागरिक एआई को पूरी तरह से समझते नहीं हैं, तो वे गोपनीयता, पूर्वाग्रह या नैतिकता के बारे में सही बहस में शामिल नहीं हो पाते। वे न तो विनियामक को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और न ही खुद को धोखे से बचा सकते हैं। ऐसे में, वे छोटे व्यवसाय, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा के लिए एआई का पूरा फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए बंगलूरू की घटना सिर्फ एक अपराध कथा नहीं है। यह एक बड़ी राष्ट्रीय कमजोरी है : कम एआई साक्षरता और अधिक भरोसा, जो खतरनाक संयोजन है।

यदि भारत एआई का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे जागरूकता बढ़ानी होगी। स्कूलों और कॉलेजों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के तहत एआई और डिजिटल साक्षरता मॉड्यूल शामिल करने चाहिए। माई जीओवी, डिजिटल इंडिया और दूरदर्शन जैसे मंचों के जरिये जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, जिनमें एआई को सरल शब्दों में समझाया जा सके। नागरिकों को पता होना चाहिए कि डीपफेक कैसे काम करते हैं, स्कैम कैसे काम करते हैं, और खुद को कैसे सुरक्षित रखें। कौशल विकास कार्यक्रम में एआई और डाटा एनालिटिक्स प्रशिक्षण को शामिल करना चाहिए, ताकि ग्रामीण युवा पीछे न रहें। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानूनों का पारदर्शी अमल और नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए। स्थानीय कार्यशाला, स्वयंसेवी संगठन और सिविल सोसाइटी समूह लोगों को धोखाधड़ी को पहचानना और टेक्नोलॉजी का सुरक्षित इस्तेमाल करना सिखाने में भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।

एआई को लेकर भारत की इच्छाएं वास्तविक हैं, लेकिन बिना जानकारी के इच्छाएं कमजोर होती हैं। बंगलूरू की घटना दर्शाती है कि भरोसे का कितनी जल्दी फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन लाखों लोगों को वास्तव में इसके बारे में बहुत कम पता है। एआई सिर्फ एल्गोरिदम और नवाचार के बारे में नहीं है। यह लोगों के बारे में है। अगर लाखों लोग गैर-जागरूक बने रहे, तो भारत की एआई क्रांति धोखाधड़ी और शोषण की वजह से पटरी से उतर सकती है। इसलिए, एआई के बारे में चर्चा के साथ-साथ पढ़ाई-लिखाई, नैतिकता और सावधानी के लिए भी गंभीर प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भविष्य का आह्वान करने वाले एक देश का उत्साह दिखा। लेकिन जब हम जोखिमों और फायदों पर बहस करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि तकनीक उतनी ही मजबूत है, जितने मजबूत लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। बंगलूरू जैसे मामले यह साबित करते हैं कि नासमझी महंगी पड़ सकती है। भारत की एआई कहानी को बढ़ा-चढ़ाकर देखने के बजाय यथार्थवादी दृष्टि से देखने की जरूरत है। इसके लिए ऐसे नागरिकों की जरूरत है, जो जानकार, सावधान और मजबूत हों। इसके बिना, एआई दुःस्वप्न बन सकता है।

जीवन धारा

लुडविग विट्गेंस्टाइन

दर्शन दृष्टिकोण देता है कि हम विचारों को संदेह की कसौटी पर कस सकें। वह हमारे विचारों की ऊसर भूमि को जोतता है, ताकि हम उसके नीचे दबे हुए अहंकार और पूर्वाग्रह बाहर ला सकें तथा सोचने के ढंग को निखार सकें।

विचारों को संदेह की कसौटी पर परखें

किसी भी कठिनाई को केवल सतह पर पहचान लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो केवल ऊपर से दिखाई देता है, वह समस्या का मात्र एक लक्षण होता है, उसका मूल नहीं। यदि हम बाधाओं को केवल सतही तौर पर समझते हैं, तो वे अपनी साधारण स्थिति में बनी रहती हैं और बार-बार लौटती हैं। उनका वास्तविक अंत तभी संभव है, जब उन्हें उनकी जड़ से खत्म किया जाए। और उन गहरी जड़ों तक पहुंचना तभी संभव होता है, जब हम उनके बारे में सोचने के अपने तरीके को बदलें। यह बदलाव एक गहन आंतरिक प्रक्रिया है, जो उतनी ही निर्णायक है, जितना कि कीमियागरी के रहस्यवाद से आधुनिक विज्ञान की तार्किक स्पष्टता की ओर बढ़ना। इस प्रक्रिया में हमारे विचार की वह आधारभूत संरचना ही बदल जाती है, जिस पर हमारा अस्तित्व टिका होता है। यही 'नया चिंतन-रूप' स्थापित करना मनुष्य के लिए सबसे कठिन साधना है, क्योंकि हम अपनी पुरानी आदतों और स्मृतियों के कारागार में बंद होते हैं।

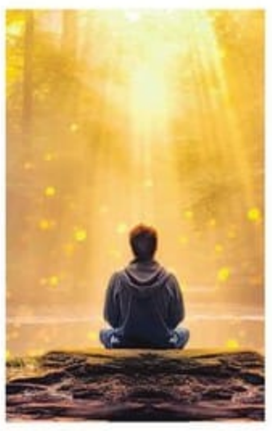

एक बार जब यह नया और निर्मल दृष्टिकोण स्थिर हो जाता है, तब पुराने प्रश्न और चिंताएं स्वयं ही विलीन होने लगती हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रश्न हमारी पुरानी अभिव्यक्ति-शैली और संकुचित सोच की उपज थे और जब अभिव्यक्ति का वह पुराना परिधान उतर जाता है, तो उससे जुड़ी समस्याएं भी स्वतः दम तोड़ देती हैं। अतः, दर्शन को केवल एक अकादमिक विषय या विशेषज्ञों की जागीर मान लेना भ्रम है। दर्शन विचारों की वह परम स्पष्टता है, जो हमारे विवेक को जागृत करती है। जो लोग इस दार्शनिक अन्वेषण और आत्म-मंथन के अभ्यास से वंचित रहते हैं, वे प्रायः उन सूक्ष्म बिंदुओं को देख ही नहीं पाते, जहां जीवन की वास्तविक चुनौतियां व सत्य छिपे होते हैं। उनकी स्थिति उस पथिक के समान होती है, जो घने वन में खड़ा तो है, पर जिसे दिव्य औषधि या दुर्लभ पुष्प (सत्य) खोजने का अभ्यास नहीं है। उसकी आंखें प्रशिक्षित नहीं होतीं, इसलिए उसे यह बोध ही नहीं होता कि सत्य की खोज में कहां ठहरना है। इसके विपरीत, एक निरंतर अभ्यास से तपा हुआ साधक भले ही सत्य को तुरंत न देख पाए, लेकिन वह भागता नहीं, बल्कि ठहरता है, धैर्य रखता है और पूर्ण समर्पण के साथ उस सत्य की खोज में लगा रहता है। यह स्वाभाविक है कि उस छिपे सत्य तक पहुंचने में समय लगे, क्योंकि उसे पाना पुरुषार्थ की मांग करता है।

दर्शन हमारे विचारों की ऊसर भूमि को जोतता है, ताकि उसके नीचे दबे हुए अहंकार और पूर्वाग्रह बाहर आ सकें। जैसे-जैसे सोचने का ढंग निखरता है, समस्याओं का स्वरूप ही बदल जाता है और वे बाधाएं नहीं, बल्कि सोपान बन जाती हैं। अंततः, यह दर्शन हमें दृष्टिकोण देता है कि हम अपने ही स्थापित विचारों को संदेह की कसौटी पर कस सकें।

समस्या की जड़ तक जाएं

सूत्र

किसी भी कठिनाई का वास्तविक समाधान तभी संभव है, जब हम उसे उसके मूल से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम उसे देखने के अपने दृष्टिकोण को बदलकर कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तो उलझनें स्वतः समाप्त होने लगती हैं। दर्शन सिखाता है कि हम अपने विचारों को परखें, पूर्वग्रहों से मुक्त हों और स्पष्टता की ओर बढ़ें।

दूसरा पहलू

'महिला मंडल काशी' बनारस की पहली महिला संस्था थी। प्रतिष्ठित परिवार की महिलाएं इसका हिस्सा थीं और नंदन साहू लेन इसका पता।

जहां सास अपनी बहुओं को सौंपती हैं नेतृत्व

महिला मंडल काशी की स्थापना 90 साल पहले रत्नेश्वरी देवी ने एक औषधालय के रूप में की थी। 1937 में बनी यह संस्था काशी की पहली महिला संस्था थी। चौखंबा के प्रतिष्ठित परिवार की महिलाएं इसका हिस्सा थीं और नंदन साहू लेन इसका पता।

1930 का दशक था। काशी के संभ्रांत परिवारों की महिलाओं ने घर की दहलीज पार कर समाज सेवा की शुरुआत की, पर ये महिलाएं परिवार की प्रतिष्ठा और मर्यादा की दुशाला ओढ़कर ही निकलतीं थीं। काशी के मशहूर मोती झील परिवार, आज प्रेस परिवार, शाह, कन्हैया अलंकार, भारतेंदु जैसे और भी प्रतिष्ठित परिवार की महिलाओं ने इसे शुरू किया। इनके जरिये महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, चित्रकला, पुस्तकालय, पत्रिका प्रकाशन के साथ-साथ काशी की पहली तैराकी की क्लास भी शुरू की गई। महिलाएं पढ़ पाएं, इसके लिए किताबें घर पर पहुंचाई जाती थीं। पर्दा प्रथा निभाते हुए घर से बाहर चादर ओढ़कर निकलना नियम था। ऐसे में, जब देश में चादर छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो मंडल की महिलाओं ने भी उसमें हिस्सा लिया। गंगा घाट पर रहने वाली महिलाएं तैरना नहीं जानती थीं। सो, उन्हें तैराकी सिखाने के लिए 'कालिंदी तैराकी शिविर' की स्थापना की गई। यह नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुज बाबू गोकुल चंद्र की पौत्री व भारतरत्न डॉ. भगवान दास की नातिन कालिंदी के नाम पर रखा गया। इसके पीछे भी कहानी है। कम उम्र में कालिंदी की मृत्यु हो गई थी। उन्हीं की याद में यह शिविर शुरू किया गया। शिविर के लिए सुबह बाकायदा गंगा किनारे तंबू गाड़ा जाता, फिर पानी में मोटे रस्सों का घेरा बनाया जाता। शुरुआत में लोगों ने इसका विरोध किया। एक समय तो दो लठैत को तैराकी शिविर के बाहर तैनात करना पड़ा। हालांकि, धीरे-धीरे विरोध खत्म हो गया और हर साल गर्मी के एक महीने तक यह शिविर कई साल चला।

उपमिता वाजपेयी

इसकी स्थापना रत्नेश्वरी देवी ने एक औषधालय के रूप में की थी। आज 100 से ज्यादा महिलाएं इस मंडल की सदस्याएं हैं।

परंपरा के मुताबिक, महिला मंडल काशी की जो महिलाएं सास बन जाती हैं, वे इसकी कमान अपनी बहुओं को सौंप देती हैं। शायद यही वजह है कि 90 साल से यह मंडल सक्रिय है।

1978 में संस्था ने अपना पहला तीज मेला आयोजित किया था। इसमें महिलाएं साड़ी से लेकर पापड़ तक बेचने व खरीदने आईं। आज भी हर साल सावन में यह मेला लगता है। फिलहाल, 100 से ज्यादा महिलाएं इस मंडल की सदस्याएं हैं। इनकी धरोहर में 4,000 किताबों वाला एक पुस्तकालय है। इनके कार्यक्रमों का हिस्सा काशी नरेश विभूति नारायण, प्रसिद्ध लेखिका शिवानी, भानु शंकर मेहता और ठुमरी साम्राज्ञी गिरिजा देवी भी बन चुकी हैं। इस मंडल की महिलाएं ऑनलाइन जूम मीटिंग भी करने लगी हैं। परंपरा के मुताबिक, मंडल की जो महिलाएं सास बन जाती हैं, वे इसकी कमान अपनी बहुओं को सौंप देती हैं। शायद यही वजह है कि 90 साल से यह मंडल सक्रिय है।

आंकड़े

एआई पर निर्भरता

चैटजीपीटी के साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 80 करोड़ को पार कर गई है। यह आंकड़ा 2025 की शुरुआत में 40 करोड़ था।

अमेरिका	17.46
भारत	9.78
ब्राजील	4.76
ब्रिटेन	4.58
जापान	3.79

आंकड़े जनवरी 2026 तक लोगों द्वारा चैटजीपीटी के इस्तेमाल के, प्रतिशत में। | स्रोत : ओपनएआई

शिवजी के वचनों से आहत होकर माता पार्वती ने अन्न को जगत से विलुप्त कर दिया। फिर लोगों की व्याकुलता देख वह मां अन्नपूर्णा के दिव्य रूप में प्रकट हुईं।

अन्नपूर्णा रूपी माता पार्वती

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा कि यह समस्त दृश्य जगत माया का विस्तार है। 'अन्न' और 'देह' भी नश्वर हैं, इनका परम सत्य के स्तर पर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। माता पार्वती आहत हुईं कि अन्न का कोई महत्व नहीं है और उन्होंने अन्न को समस्त लोक से विलुप्त करने का संकल्प ले लिया। इससे सृष्टि में अन्न का व्यापक अभाव उत्पन्न हुआ। इससे यज्ञ-क्रियाएं स्थगित हो गईं, कृषि-व्यवस्था नष्टप्राय हो गई, जीवन-चक्र गंभीर रूप से बाधित हो गया, लोक व्यवस्था डगमगाने लगी तथा देव, मनुष्य और अन्य जीव सभी व्याकुल हो उठे।

यह देख मां पार्वती करुणा से द्रवित हो उठीं और काशी में माता अन्नपूर्णा के दिव्य रूप में प्रकट हुईं। उनके करकमलों में अक्षय पात्र और अन्नपूर्ण कलश शोभित थे, जिनसे अनवरत अन्न प्रवाहित हो रहा था। उसी समय भोलेनाथ खुद भिक्षुक बनकर वहां पहुंचे और माता से विनम्रतापूर्वक अन्न की याचना की।

अंतर्यात्रा

संकलित

महादेव ने स्वीकार किया कि देहधारी जीवन में अन्न ही प्राणों का आधार है; वह पूज्य है, अनिवार्य है और करुणा का साकार रूप है। उसका लौकिक महत्व असंदिग्ध और अपरिहार्य है। अन्नपूर्णा रूपी माता पार्वती ने शिवजी को अन्न प्रदान किया और उसी क्षण से अन्नदान, सेवा और करुणा को धर्म का शाश्वत विधान प्राप्त हुआ।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 24 फरवरी, 1952

भारत नेपाल के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा

भारत नैपाल के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा

नेपाल के प्रधानमंत्री एम पी कोइराला ने कहा कि कुछ शरारती लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं कि नेपाल के घरेलू मामलों में भारत हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने आज तक नेपाल के निजी मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है।

किस करवट बैठेगा नेपाल

आगामी पांच मार्च को नेपाल में होने वाला चुनाव स्थिरता, युवाओं के आक्रोश व भारत-चीन के बीच भू-राजनीतिक संतुलन पर एक जनमत-संग्रह है।

केएस तोमर

पड़ोस

आगामी पांच मार्च को नेपाल में चुनाव होने वाले हैं, पर राष्ट्र अब भी विगत सितंबर में बड़े पैमाने पर हुए विरोध-प्रदर्शनों की उथल-पुथल से उबर रहा है। इन प्रदर्शनों को आम तौर पर 'पांचवीं क्रांति' कहा जाता है, जिसके कारण केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (सीपीएन-यूएमएल) की सरकार गिर गई थी। नए चुनावों की घोषणा से पहले हफ्तों तक अशांति, प्रशासनिक पंगुता और राजनीतिक अनिश्चितता रही। हालांकि, मतदान पूरे देश में होना है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संदेह है कि मतदान आसानी से हो पाएगा या नहीं।

यह चुनाव एक आम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ज्यादा विश्वसनीयता, सांविधानिक स्थिरता, युवाओं के आक्रोश और नेपाल के अपने दो शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच भू-राजनीतिक संतुलन पर एक जनमत-संग्रह है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच है। नेपाली कांग्रेस के लिए प्रचार मुख्यतः लोकतंत्र की बहाली और संस्थाओं में भरोसा फिर से बनाने पर केंद्रित है। पार्टी नीतिगत पूर्वानुमान, छोटे और मझोले उद्यमों को फिर से शुरू करने, भारत के साथ हाइड्रोपावर सहयोग बढ़ाने और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का वादा कर रही है, खासकर विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट शटडाउन और पुलिसिंग विवादों को देखते हुए। हालांकि, पार्टी की आंतरिक गुटबाजी उसका एक संरचनात्मक कमजोर पक्ष बना हुआ है, जो उसके चुनावी लाभ को कम कर सकता है। वहीं, कम्युनिस्ट विचारधारा एक अलग सोच पेश करती है। सीपीएन-यूएमएल अपने उथल-पुथल भरे और अस्त-व्यस्त कार्यकाल को बचाने के लिए मजबूत नेतृत्व, बुनियादी ढांचों में बढ़ोतरी और राष्ट्रवादी दावे करके हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पुष्प कमल दहल के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी केंद्र) सामाजिक न्याय, संघीय सशक्तीकरण और युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप सांविधानिक सुधारों पर जोर देकर अपनी पुनर्वितरणवादी विश्वसनीयता को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। साथ मिलकर वामपंथी दल संप्रभुता, संतुलित कूटनीति और पारंपरिक निर्भरता से आगे आर्थिक विविधीकरण पर जोर देते हैं। फिर भी, व्यापक वामपंथी धड़े के भीतर वैचारिक एकता नाजुक बनी हुई है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षाएं एकता को जटिल बनाती हैं।

चुनावी अभियान को और जटिल बनाता है घोषणा-पत्र प्रकाशन को लेकर विवाद। चुनाव लड़ रहे 68 दलों में से आधे से अधिक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने घोषणा-पत्र प्रकाशित करने में विफल रहे। चुनाव मैदान में 3,406 उम्मीदवार हैं, जिनमें लगभग 1,160 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं, जो 165 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वित्तीय अनुपालन भी असमान रहा है। ये चूकें उस समय संस्थागत अनुशासन पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं, जब सार्वजनिक विश्वास पहले ही कमजोर हो चुका है। साथ ही, पिछले चुनाव के खंडित जनादेश की यादें बनी हुई हैं और मतदाता अनिश्चित नतीजे को लेकर सावधान हैं।

भारत के लिए, नेपाल की स्थिरता का सीधा असर सुरक्षा और आर्थिक तौर पर होता है। दोनों देशों के बीच 1,700 किलोमीटर से अधिक की खुली सीमा, गहरे ऐतिहासिक रिश्ते और करीबी सैन्य सहयोग है। हाल के वर्षों में हाइड्रोपावर सहयोग, सीमा पार बिजली व्यापार और संपर्क परियोजनाओं ने रफ्तार पकड़ी है। इसे बनाए रखने के लिए काठमांडो में एक भरोसेमंद और स्थिर सरकार जरूरी है। इसके अलावा, नेपाल में राजनीतिक संकट के दौरान अक्सर घरेलू लामबंदी के औजार के तौर पर समय-समय पर भारत विरोधी बातें उठती रही हैं। नई दिल्ली की प्राथमिकता एक संप्रभु, लेकिन स्थिर नेपाल है, जिसके साथ पारंपरिक रिश्ते मजबूत किए जा सकें। पिछले दशक में नेपाल में चीन की भागीदारी काफी बढ़ी है। नेपाल के लिए, भारत और चीन के साथ संतुलन बनाना अब भी मुश्किल है। भूगोल काठमांडो को नई दिल्ली व बीजिंग, दोनों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। ऐसे में, चुनाव के नतीजे यदि एक तरफ झुकते हैं, तो यह संतुलन बिगड़ने का खतरा है।

नेपाल में चुनाव युवाओं की नाराजगी, संस्थाओं की कमजोरी और भू-राजनीतिक संवेदनशीलता की पृष्ठभूमि में हो रहे हैं। भारत और चीन, दोनों के लिए ही, इस नतीजे का रणनीतिक महत्व है। फिर भी, निर्णायक आवाज नेपाल के मतदाताओं की होगी-चाहे वे पुराने राजनीतिक ढांचे को फिर से बनाना चाहें या गणतंत्र की दिशा को फिर से तय करने की कोशिश करें। यह नेपाल की लोकतांत्रिक व सांस्थानिक मजबूती और भू-राजनीतिक संतुलन को आकार देगा।

edit@amarujala.com

एजुकेशन & कॅरिअर

सकारात्मक सोच से हर चुनौती आसान हो जाती है।

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts amarujala.com/jobs

रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन

7th सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल-1 में कई पदों पर निकली भर्ती

22195 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 02 मार्च, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : rrbapply.gov.in

ईएसआईसी, इंदौर में निकली भर्ती ■ 101 पद

प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि 02 मार्च, 2026
वेतनमान रुपये 67,700 से लेकर रुपये 1,23,100 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें esic.gov.in

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ■ 78 पद

सब इंस्पेक्टर निषेध के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी, 2026
योग्यताएं स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें bpssc.bihar.gov.in

भारत संचार निगम लिमिटेड ■ 120 पद

वरिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षु के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 07 मार्च, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : bsnl.co.in

बिहार तकनीकी सेवा आयोग ■ 68 पद

डेयरी फील्ड ऑफिसर व अन्य पदों पर नौकरी के मौके
आवेदन की अंतिम तिथि 13 मार्च, 2026
योग्यताएं बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें btsc.bihar.gov.in

आईसीएमआर में नौकरी के अवसर ■ 27 पद

वैज्ञानिक-बी के पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि 01 मार्च, 2026
वेतनमान रुपये 56,100 से लेकर रुपये 1,77,500 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें aiimsexams.ac.in

यहां भी रोजगार के अवसर ...

- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया : काउंसलर के पदों पर आवेदन आमंत्रित।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 13 मार्च, 2026
- centralbankofindia.co.in
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की : प्रोजेक्ट फेलो का पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 10 मार्च, 2026
- iitr.ac.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

आप कितने प्रभावी लीडर हैं

केवल तेजी से सीखने वाला ही होना काफी नहीं, बल्कि इंटरव्यू में यह दिखाना भी जरूरी है कि आप बदलाव के दौर में नेतृत्व कैसे करेंगे

मार्लो लियोन्स
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

आज का कार्य वातावरण तेजी से बदल रहा है। तकनीक, बाजार और कार्यशैली में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए संगठनों को ऐसे लीडर्स की जरूरत है, जो इन बदलावों के बीच भी प्रभावी नेतृत्व कर सकें। वरिष्ठ पद के साक्षात्कार में केवल उपलब्धियां और टीम विकास का अनुभव ही पर्याप्त नहीं होते। कंपनियां यह भी देखती हैं कि आप अनिश्चित परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेते हैं और बदलाव को कैसे संभालते हैं। अनुकूलनशीलता एक महत्वपूर्ण नेतृत्व कौशल है, जो नई परिस्थितियों में जल्दी ढलने और चुनौतियों के बीच भी परिणाम देने की आपकी क्षमता को दर्शाती है। इसलिए केवल तेजी से सीखने वाला कहना काफी नहीं, बल्कि ठोस उदाहरणों के साथ यह दिखाना जरूरी है कि आपने बदलाव के दौर में सफल नेतृत्व कैसे किया।

■ **कहानी के लिए पद्धति अपनाएं**

अपनी कार्यकुशलता दिखाने के लिए स्थिति, कार्य, क्रिया, परिणाम+सीख (स्टार+एल) पद्धति अपनाएं। पहले चुनौतीपूर्ण स्थिति और अपनी जिम्मेदारी बताएं, फिर समझाएं कि आपने उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए। इसके बाद मापने योग्य परिणाम साझा करें और अंत में यह स्पष्ट करें कि उस अनुभव से आपने क्या सीखा और वह आपको आज बेहतर नेता कैसे बनाता है।

■ **रणनीतिक बने रहें**

साक्षात्कार में ऐसे उदाहरण साझा करें, जहां बाजार के आंकड़ों या ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर आपको अपनी परियोजना में बदलाव करना पड़ा हो। साथ ही, सीमित संसाधनों या कम समय में परिणाम देने और नई तकनीक या प्रक्रिया को शुरुआती विरोध के बावजूद सफलतापूर्वक लागू करने के अनुभव भी बताएं। ऐसे उदाहरण आपकी लचीलापन, संसाधनशीलता और परिवर्तन प्रबंधन क्षमता को दर्शाते हैं।

Harvard Business Review

■ **नेतृत्व का प्रदर्शन करें**

साक्षात्कार में बताएं कि कठिन समय या पुनर्गठन के दौरान आपने टीम का नेतृत्व कैसे किया, उनकी चिंताओं को समझकर स्पष्ट दिशा और प्रेरणा दी। साथ ही, जरूरत पड़ने पर अपनी नेतृत्व शैली में बदलाव कर नई टीम या संस्कृति के अनुरूप कैसे काम किया। ऐसा उदाहरण भी साझा करें, जब संवाद के माध्यम से आपने टीम को बदलाव स्वीकार करने और नई प्रक्रिया अपनाने के लिए तैयार किया।

■ **काम का उल्लेख करें**

साक्षात्कार में बताएं कि नई कंपनी में शामिल होने के बाद आपने उसकी संस्कृति को कितनी जल्दी समझा और लोगों का विश्वास कैसे जीता। ऐसा उदाहरण भी साझा करें, जब महत्वपूर्ण फीडबैक या नई जानकारी के आधार पर आपको अपनी परियोजना की दिशा बदलनी पड़ी या अधूरी जानकारी में बड़ा निर्णय लेकर जोखिम का समझदारी से प्रबंधन करना पड़ा। बदलाव से जुड़े तनाव की शिकायत करने के बजाय यह स्पष्ट करें कि आपने कौन-से सकारात्मक कदम उठाए और खुद को नई परिस्थितियों के अनुसार कैसे ढाला। ठोस उदाहरणों के माध्यम से दिखाएं कि आप अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं।

खुद को परखें

1. स्पाइनोसॉरस मिराबिलिस नामक एक नए मांसाहारी डायनासोर की खोज किस रेगिस्तान में हुई थी?
   (a) गोबी रेगिस्तान
   (b) अटाकामा रेगिस्तान
   (c) सहारा रेगिस्तान
   (d) कालाहारी रेगिस्तान
2. हाल ही में खबरों में आया कानलाओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है?
   (a) इंडोनेशिया
   (b) जापान
   (c) चीन
   (d) फिलीपींस
3. सीजे-1000 किस देश द्वारा विकसित एक सड़क-चालित मिसाइल है?
   (a) चीन
   (b) रूस
   (c) जर्मनी
   (d) भारत

उत्तर-1.c, 2.d, 3.a

आवेदन आमंत्रित

मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इंटर्नशिप

मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की ओर से भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों में नामांकित स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों से इंटर्नशिप हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छह माह की इस इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को सरकारी कार्यप्रणाली तथा नियामक एवं विकासात्मक नीतियों से संबंधित मुद्दों को समझने का अवसर मिलेगा। स्नातक छात्रों को प्रतिमाह 15,000 रुपये तथा स्नातकोत्तर छात्रों को प्रतिमाह 20,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर अनुभव प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। आवेदक आधिकारिक लिंक cooperation.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से 05 मार्च, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

बोर्ड परीक्षा

केमिस्ट्री से बढ़ाएं अपना स्कोर ग्राफ

बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री के फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों भागों की संतुलित तैयारी आवश्यक है। फिजिकल केमिस्ट्री में संख्यात्मक प्रश्नों के लिए सूत्रों का अभ्यास जरूरी है। इनऑर्गेनिक में डी एवं एफ ब्लॉक तथा कोऑर्डिनेशन यौगिक महत्वपूर्ण हैं, जबकि ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन और प्रमुख परीक्षणों की स्पष्ट समझ आवश्यक है। बायोमॉलिक्यूल्स भी एक स्कोरिंग अध्याय है।

■ **मान स्पष्ट रूप से लिखें**

विद्यार्थियों को संख्यात्मक प्रश्नों में दिए गए मान स्पष्ट रूप से लिखकर, उपयुक्त सूत्र दर्शाते हुए चरणबद्ध गणना करनी चाहिए और अंतिम उत्तर सही इकाई सहित लिखना चाहिए। थ्योरी प्रश्नों के उत्तर बिंदुवार एवं स्पष्ट होने चाहिए। साफ-सुथरी प्रस्तुति, संतुलित समीकरण और क्रमबद्ध लेखन अच्छे अंक दिलाने में सहायक होते हैं।

■ **सकारात्मक बने रहें**

नियमित अभ्यास और एनसीईआरटी के गहन अध्ययन से केमिस्ट्री में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की जा सकती है। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अंत में, आत्मविश्वास बनाएं रखें और सही योजना और समझदारी भरी तैयारी से इस विषय में उत्कृष्ट अंक पाए जा सकते हैं।

-पंकज पेटवाल

एडमिट कार्ड / हुआ जारी

एमपीईएसबी आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा

- परीक्षा की तिथि : 27 फरवरी, 2026
- इस परीक्षा में ट्रेड संबंधित विषय से 75 अंकों के प्रश्न तथा विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता आदि विषयों से 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें tinyurl.com/26kzynv2

मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा-2025

- परीक्षा की तिथि : 01 मार्च, 2026
- इस परीक्षा के प्रथम प्रश्न-पत्र में शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 अंकों के 50 प्रश्न व द्वितीय प्रश्न-पत्र में चयनित विषय से 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें tinyurl.com/2a4yfbws

सामान्य ज्ञान

ऑपरेशन त्राशी-I

■ **क्या है**

यह एक बहु-दिवसीय आतंकवाद-रोधी और क्षेत्र-नियंत्रण अभियान है, जिसे भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से संचालित कर रहे हैं।

■ **चर्चा में क्यों**

भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्राशी-1 में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान-आधारित जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादियों को मार गिराया।

■ **आतंकवादी समूहों का पता लगाना**

इस अभियान का उद्देश्य किश्तवाड़ जिले के चतरू क्षेत्र के वन इलाकों में सक्रिय आतंकवादी समूहों का पता लगाना, उन्हें निष्क्रिय कर उनका विघटन करना है।

■ **रणनीतिक स्थान**

किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर और डोडा से कश्मीर घाटी की ओर जाने वाला क्षेत्र आतंकवादियों के पारंपरिक मार्गों में शामिल रहा है। साथ ही, इस अभियान में हवाई निगरानी, खोजी कुत्तों और विश्वसनीय खुफिया जानकारी का उपयोग आधुनिक आतंकवाद-रोधी रणनीति को दर्शाता है।

ऊर्जा

Life Dream Love

ब्लू माइंड थेरेपी से दूर होगा तनाव

आज हम ज्यादातर समय मोबाइल या स्क्रीन के सामने बिताते हैं। इन स्क्रीन्स से निकलने वाली किरणें इन्सान को मानसिक थकान और तनाव देती हैं। ब्लू माइंड थेरेपी इन समस्याओं से राहत पाने का एक प्रभावी उपाय है।

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव और चिंता आम समस्याएं बन चुकी हैं। सबसे अजीब बात जो देखने को मिलने रही है वह है कि तनाव, एंग्जाइटी की गिरफ्त में सिर्फ बड़े ही नहीं हैं, बल्कि बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी के चलते लोग इस पर बात करने और एक्सपर्ट की सलाह लेने से हिचकिचाते हैं। मेंटल हेल्थ को लंबे समय तक इग्नोर करना कई तरह की सेहत संबंधी परेशानियों की वजह बन सकता है। ऐसे में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। इस समस्या से राहत पाने के लिए, एक प्रभावी और प्राकृतिक तरीका है ब्लू माइंड थेरेपी। ब्लू माइंड थेरेपी की अवधारणा समुद्री जीव वैज्ञानिक वैलेस जे निकोलस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ब्लू माइंड' में प्रस्तुत की थी। उनके अनुसार, पानी के संपर्क में आने या पानी के आस-पास समय बिताने से हमारे मस्तिष्क की स्थिति शांत और संतुलित हो जाती है।

डॉ. संजय तेवतिया
वरिष्ठ चिकित्सक

■ **क्या है ब्लू माइंड थेरेपी**

ब्लू माइंड, एक ऐसी मानसिक अवस्था है, जिसमें व्यक्ति शांति, संतोष और सकारात्मकता का अनुभव करता है। इसके विपरीत रेड माइंड वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति तनाव, गुस्सा और बेचैनी महसूस करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी हमें अक्सर रेड माइंड की स्थिति में रखती है। ब्लू माइंड थेरेपी हमें इस नकारात्मक स्थिति से बाहर निकाल कर मानसिक सुकून की ओर ले जाती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पानी के पास रहने से हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन का स्तर बढ़ता है। समुद्र की लहरों की आवाज, नदी का बहाव, बारिश की बूंदें या झील का शांत दृश्य, ये सभी हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं। पानी को देखना या उसकी ध्वनि सुनना हमारे मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को सक्रिय करता है, जो ध्यान और रिलैक्सेशन की अवस्था से जुड़ी होती है। यही कारण है कि समुद्र तट या झील के किनारे बैठकर हमें स्वाभाविक शांति महसूस होती है। ब्लू माइंड थेरेपी

तनाव और चिंता पर प्रभाव

ब्लू माइंड थेरेपी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्राकृतिक और साइड इफेक्ट रहित तरीके से काम करती है। नियमित रूप से पानी के संपर्क में रहने से हृदय गति सामान्य होती है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, नकारात्मक विचार कम होते हैं। पानी के आसपास समय बिताने से व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीना सीखता है। यह माइंडफुलनेस को बढ़ावा देता है, जिससे चिंता और भविष्य की फिक्र कम होती है।

अपनाने के लिए किसी विशेष उपकरण या महंगे इलाज की जरूरत नहीं होती। इसे आप अपने दैनिक जीवन में सरल तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

■ **प्रकृति के बीच समय बिताएं**

यदि आपके आस-पास कोई नदी, झील या समुद्र है, तो वहां कुछ समय बिताएं। पानी के बहाव को देखें और उसकी आवाज को महसूस करें। तैराकी या वाटर एक्टिविटी करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी हल्का और प्रसन्न होता है। पानी में रहने से तनाव कम होता है।

■ **बारिश का आनंद लें**

हल्की बारिश में टहलना या खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदों को देखना भी मानसिक सुकून देता है। इसलिए अगर बारिश हो रही है, तो इसका लाभ जरूर उठाएं।

■ **घर में पानी का तत्व शामिल करें**

यदि बाहर जाना संभव न हो, तो घर में छोटा सा फाउंटेन लगाएं या एक्वेरियम रखें। बहते पानी की ध्वनि मन को शांत करती है।

■ **ध्यान और कल्पना**

आंख बंद करके समुद्र या झील का शांत दृश्य कल्पना करें। यह भी ब्लू माइंड की अवस्था लाने में मदद करता है।

■ **पानी की ध्वनि से लाभ**

आज हम ज्यादातर समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। इससे मानसिक थकान और तनाव बढ़ता है। ऐसे में ब्लू माइंड थेरेपी हमें डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर प्रकृति से जुड़ने का अवसर देती है। शहरी जीवन में भी इस थेरेपी को अपनाया जा सकता है। वीकेंड पर किसी झील या पार्क में जाना, छुट्टियों में समुद्र तट की यात्रा करना या रोजाना कुछ मिनट पानी की ध्वनि सुनना मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।

योग टिप्स

कमर को लचीला बनाएं

पद्मासन का नियमित अभ्यास करने से घुटनों में लचीलापन आता है और कमर के जोड़ में चिकनापन बढ़ता है। इससे शरीर सीधा और संतुलित होता है। छाती खुलती है और श्वसन बेहतर होता है। पद्मासन करने के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठें। दाएं घुटने को मोड़ते हुए पंजा बाईं जांघ पर रखें और बाएं घुटने को मोड़ते हुए पंजा दाईं जांघ पर रखें। इसी स्थिति को पद्मासन कहा जाता है। कमर के जोड़ को लचीला बनाने के लिए दंडासन में बैठकर दाएं घुटने को मोड़कर पंजा बाईं जांघ पर रखें। दाएं हाथ से दाएं घुटने के ठीक नीचे सहारा दें। बाएं हाथ से दाएं पैर के टखने और एड़ी को पकड़ें। अब दाएं घुटने को पहले दाईं ओर पीछे की तरफ ले जाएं। फिर वापस दाएं घुटने को बाईं ओर पीछे की तरफ ले जाएं। यह क्रिया अपनी क्षमता अनुसार करें। तीन बार दाईं ओर और तीन बार बाईं ओर करें। अब यही प्रक्रिया बाएं पैर से भी दोहराएं। कमर और घुटनों के लिए दूसरी क्रिया करने के लिए दाएं पैर की एड़ी नाभि के पास रखें। दोनों हाथों से दाएं घुटने को पकड़कर छाती से लगाने का प्रयास करें। 10-15 सेकंड छाती की ओर रोकें। फिर घुटने को पकड़कर जमीन की ओर लगाने का प्रयास करें और 10-15 सेकंड रोकें। इस क्रिया को तीन बार ऊपर और तीन बार नीचे करें। अब यही प्रक्रिया बाएं घुटने से भी करें। जितनी बार दाएं घुटने से किया है, उतनी ही बार बाएं घुटने से दोहराएं। कई लोग इन क्रियाओं को तेजी से करते हैं। ऐसा करने पर क्षणिक लाभ मिलता है, लेकिन धीरे और नियंत्रण के साथ करने पर ही योगिक क्रियाओं का पूर्ण लाभ मिलता है।

ढाकाराम
योगाचार्य

24 फरवरी, 1868
आज का दिन

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन पर महाभियोग चलाने के लिए वोट किया था। जॉनसन अमेरिकी इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति थे।

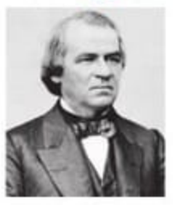

- **1739:** मुगल शासक मुहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच करनाल की लड़ाई हुई थी।
- **1955:** अमेरिकी व्यवसायी स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ था।
- **1976:** फिदेल कास्त्रो के शासन ने क्यूबा के संविधान को अपना लिया था।
- **2020:** अमेरिकी गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी/अष्टमी।
कल : लट्ठमार होली बरसाना, वसंत ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले। **राहुकाल :** दिन में 12.00 से 13.30 तक।

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 06 फाल्गुन मास शक 1947, फाल्गुन मास 14 प्रविष्टे, 07 रमजान हिजरी 1447, फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी 26.40 तक उपरांत दशमी, रोहिणी नक्षत्र 13.38 तक उपरांत मृगशिरा नक्षत्र, विष्कुम्भ योग 25.28 तक उपरांत प्रीति योग, बालव करण 15.45 तक उपरांत कौलव करण, चंद्रमा मिथुन राशि में 24.54 बजे।

■ सूर्योदय : 06.54
■ सूर्यास्त : 18.14
(भारतीय मानक समयानुसार)

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें। व्यवसाय में लाभ होगा।

वृष : नौकरी में उन्नति के संकेत मिलेंगे। व्यय पर नियंत्रण रखें। व्यवसाय में लाभ होगा। घर में आनंद रहेगा।

मिथुन : परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा। नौकरी में सम्मान बना रहेगा। व्यवसाय में स्वश्रम से लाभ होगा।

कर्क : भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा।

सिंह : सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में वर्चस्व बढ़ेगा। राजकाज में सफलता मिल सकती है।

कन्या : पूर्व नियोजित कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी में कार्यकुशलता बनी रहेगी। अधूरे कार्य पूरे होंगे।

तुला : दिनमान अनुकूल रहेगा। नौकरी में नए प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। आय-व्यय में संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक : स्वविवेक से योजना सफल होगी। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी। व्यवसाय में धन लाभ होगा। तनाव से बचें।

धनु : कैरिअर में सफलता मिल सकती है। न्याय क्षेत्र में विजय मिलेगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी।

मकर : मानसिक उथल-पुथल बनी रहेगी। नौकरी में कार्यभार अधिक रहेगा। योजना में सफलता मिलेगी।

कुंभ : शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी। व्यवसाय में धन लाभ होगा। तनाव से बचें।

मीन : रचनात्मक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में सचेत रहें। व्यवसाय में लाभ होगा।

जन्मदिन

पूजा भट्ट, अभिनेत्री

आज जन्मे जातक संवेदनशील, मानवतावादी एवं सहयोगी भावना प्रधान होते हैं। इस वर्ष मान प्रतिष्ठा को नया आकार मिलेगा। भौतिक सुख साधनों पर व्यय होगा। बेरोजगारी से मुक्ति के प्रयास सफल होंगे। वर्ष मध्य में आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें। आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।

सुडोकू

				3				1
	6		1				5	
	5	9						4
					6			7
		8				2		
4			5					
2						6	7	
	9				4		3	
8				2				

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

7	8	2	4	3	5	9	6	1
3	6	4	1	9	2	7	5	8
1	5	9	8	6	7	3	2	4
9	1	3	2	4	6	5	8	7
5	7	8	9	1	3	2	4	6
4	2	6	5	7	8	1	9	3
2	4	5	3	8	1	6	7	9
6	9	1	7	5	4	8	3	2
8	3	7	6	2	9	4	1	5

डेली हेल्थ कैप्सूल

चावल के आटे की रोटी खाने के फायदे

चावल के आटे की रोटी गेहूं की रोटी से अधिक फायदेमंद होती है। यह सुपाच्य होने के साथ पौष्टिक भी होती है।

आम तौर पर घरों में गेहूं के आटे की रोटियां बनाई जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी चावल के आटे की रोटी खाई है? चावल के आटे में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कई स्वास्थ्य लाभ देते हैं। चावल की रोटी हल्की होती है और आसानी से पच जाती है।

इस आटे में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो सुबह पेट को साफ होने में मदद करता है। इससे कब्ज दूर होती है। इस रोटी में कैलोरी कम होती है, इसकी वजह से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। इससे बार-बार खाने की इच्छा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और वजन संतुलित रहता है। इस आटे में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिन्स त्वचा को अंदर से पोषण देकर चेहरे पर निखार लाते हैं। इससे मुंहासे को कम करने में मदद मिलती है। चावल के आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस रोटी के सेवन से थकान कम होती है और आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। चावल का आटा ग्लूटेनफ्री होता है। जिन लोगों को गेहूं से एलर्जी है, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

चावल के आटे की रोटी के अधिक सेवन से वजन और रक्त शर्करा अचानक बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसमें गेहूं की तुलना में फाइबर कम मात्रा में होता है, इसलिए इसका सेवन सावधानी से करें।

-पायल शर्मा, आहार विशेषज्ञ

इस साल 9.1 फीसदी बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन, जीसीसी में सर्वाधिक वृद्धि

ईवाई की रिपोर्ट...अब कौशल आधारित वेतन ढांचे व बेहतर प्रदर्शन पर जोर दे रहीं कंपनियां

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय कंपनियां इस साल वेतन में औसतन 9.1 फीसदी की वृद्धि कर सकती हैं। हालांकि, यह 2025 के 9.3 फीसदी की अनुमानित वृद्धि से थोड़ा कम है। ईवाई ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा, कंपनियां कौशल आधारित वेतन ढांचे और बेहतर प्रदर्शन पर जोर दे रही हैं। कंपनियां वेतन वृद्धि के लिए इन मानकों को ही आधार बना रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में सबसे ज्यादा 10.4 फीसदी वेतन वृद्धि की उम्मीद है। वित्तीय सेवा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन करीब 10 फीसदी बढ़ सकता है। ई-कॉमर्स में 9.9 फीसदी और लाइफसाइंसेज एवं फार्मास्यूटिकल्स में 9.7 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 45-50 फीसदी भारतीय कंपनियां कौशल आधारित वेतन ढांचे पर जोर दे रही हैं। एआई, जेनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग और इंजीनियरिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी भूमिकाओं में 40 फीसदी तक वेतन वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि **उच्च और औसत प्रदर्शन के बीच का अंतर बढ़ गया है।** उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के वेतन में करीब 120-150 फीसदी और औसत प्रदर्शन वाले कर्मियों के वेतन में 60-80 फीसदी की वृद्धि देखी जा रही है।

10.4% बढ़ा सकते हैं वेतन वैश्विक क्षमता केंद्र

वित्तीय सेवा क्षेत्र में 10 फीसदी और ई-कॉमर्स में 9.9 फीसदी वृद्धि संभव

15 फीसदी तक बढ़ रहा सीईओ का वेतन

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में निफ्टी की शीर्ष-200 कंपनियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) का औसत कंपनसेशन (मुआवजा) बढ़कर 7-9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह सालाना आधार पर 12-15 फीसदी की बढ़ोतरी को दिखाता है। ईवाई के मुताबिक, इसमें से फिक्स्ड वेतन कुल सीईओ कंपनसेशन का 25-30 फीसदी है। शॉर्ट-टर्म इंसेंटिव (प्रोत्साहन) की हिस्सेदारी 25-30 फीसदी है, जबकि लॉन्ग-टर्म प्रोत्साहन का 45-50 फीसदी योगदान है।

- *एनएसई-200 कंपनियों में से करीब 75 फीसदी लॉन्ग-टर्म प्रोत्साहन देती हैं, जो सीईओ के कंपनसेशन का एक मानक हिस्सा बन जाता है।*

नौकरी छोड़ने की दर में गिरावट

रिपोर्ट के मुताबिक, नौकरी छोड़ने की दर (एट्रिशन रेट) 2025 में घटकर 16.4 फीसदी रह गई, जो एक साल पहले 17.5 फीसदी रही थी। यह गिरावट श्रम बाजार में सुस्ती के चलते आई है, जहां कर्मचारियों की जोखिम लेने की क्षमता कम हो गई है।

- 80 फीसदी ज्यादा कर्मचारी मर्जी से नौकरी छोड़ रहे हैं। ज्यादातर एट्रिशन कर्मचारी और अवसर आधारित हैं, न कि पुनर्गठन की वजह से।
- वित्तीय सेवा क्षेत्र में नौकरी छोड़ने की दर सबसे ज्यादा 24 फीसदी रही। खासकर सेल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और डिजिटल भूमिकाओं में।
- पेशेवरों सेवाओं में एट्रिशन रेट 21.3 फीसदी रही, जबकि हाई-टेक और आईटी क्षेत्र में नौकरी छोड़ने की दर 20.5 फीसदी रही। **वैश्विक क्षमता केंद्रों यानी जीसीसी में एट्रिशन रेट सबसे कम 14.1 फीसदी रही।**

वेतन का भविष्य सिर्फ सालाना इंक्रीमेंट पर निर्भर नहीं

ईवाई इंडिया के पार्टनर एवं लीडर अभिषेक सेन ने कहा, भारत में वेतन का भविष्य अब सिर्फ सालाना इंक्रीमेंट के साइज से तय नहीं होता। कंपनियां अब तय कर रही हैं कि किस कौशल में निवेश करना है और किन नतीजों को प्रोत्साहित करना है। रिवॉर्ड रणनीति ज्यादा सोच-समझकर बनाई जा रही हैं, जिसमें फैसले लेने के लिए डाटा का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है।

सुरक्षित निवेश मांग से चांदी और सोने के दाम 8,000 रुपये तक बढ़े

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने-चांदी की कीमतों में तीन फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैश्विक व्यापार अनिश्चितताएं बढ़ने के बीच मजबूत सुरक्षित निवेश की मांग कारण सोने-चांदी की कीमतों में तेजी आई।

मजबूत निवेश मांग के दम पर चांदी 8,000 रुपये या 3.03 फीसदी बढ़कर 2,72,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पहुंच गई। सोने की कीमत भी 3,300 रुपये या 2.06 फीसदी बढ़कर 1,62,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को चांदी 2,64,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई थी, जबकि सोना 1,59,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव रहा था।

ट्रंप टैरिफ को लेकर व्यापार अनिश्चितताएं बढ़ने से बहुमूल्य धातुओं में आई तेजी

सराफा कारोबारियों ने कहा, चांदी और सोने में सोमवार को तेजी की रफ्तार बनी रही। दोनों बहुमूल्य धातुएं तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रही थीं, जिससे अनिश्चितताओं के बीच नए सिरे से सुरक्षित निवेश की मांग वृद्धि को समर्थन मिला। टैरिफ को लेकर अनिश्चितताओं का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखने को मिला। हाजिर चांदी 2.2 फीसदी बढ़कर 86.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। सोना लगभग एक फीसदी बढ़कर 5,151 डॉलर प्रति औंस रहा।

न्यूज डायरी

455 लाख करोड़ पहुंचेगा मैनेज्ड फंड उद्योग का एयूएम

मुंबई। देश के मैनेज्ड फंड उद्योग की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) मार्च, 2030 तक बढ़कर 455 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकती हैं। यह मौजूदा स्तर से दोगुने से भी ज्यादा है। क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक, मैनेज्ड फंड उद्योग का कुल एयूएम मार्च 2025 तक 212 लाख करोड़ रुपये था, जो जीडीपी का करीब 64 फीसदी है। इसमें म्यूचुअल फंड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी शामिल हैं। एजेंसी

डॉलर के मुकाबले रुपये में पांच पैसे की मजबूती

मुंबई। डॉलर के मुकाबले रुपया सोमवार को पांच पैसे की बढ़त के साथ 90.89 पर बंद हुआ। वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से रुपये को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 90.76 के स्तर पर खुला। दिन के कारोबार में यह 90.67 से 90.90 के दायरे में रहा। पिछले सत्र में रुपया 90.94 पर बंद हुआ था। एजेंसी

खोजे गए छोटे क्षेत्रों के लिए बोली लगाने का समय बढ़ा

नई दिल्ली। सरकार ने विशेष कोल-बेड मीथेन (सीबीएम) और खोजे गए छोटे क्षेत्रों के लिए बोली लगाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के अनुसार, विशेष सीबीएम बोली दौर में कोयले की परत के नीचे से निकलने वाली संभावित गैस के लिए प्रस्तावित 13 ब्लॉक या क्षेत्रों की बोलियां तीन मार्च को बंद होंगी। ये ब्लॉक झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत सात राज्यों में हैं। एजेंसी

तीन कंपनियों ने 4.12 करोड़ में निपटाया मामला

नई दिल्ली। कल्याणी स्टील्स लि. (केएसएल) समेत तीन कंपनियों ने सोमवार को 4.12 करोड़ में सेबी के साथ डिस्क्लोजर और रिलेटेड-पार्टी ट्रांजेक्शन नियमों के कथित उल्लंघन का मामला सुलझा लिया। सेबी का आदेश तब आया, जब आवेदक (कल्याणी स्टील्स लि., बीएफ यूटिलिटीज और दीप्ति आर पुराणिक) ने शुरू की गई कार्रवाई को तथ्यों और कानून के नतीजों को माने या नकारे बिना निपटाने का प्रस्ताव दिया। एजेंसी

एनबीएफसी में 20,000 करोड़ डालेगी एयरटेल

नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने सोमवार को अपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) एयरटेल मनी के लिए बड़े विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि कुछ वर्षों में इसमें 20,000 करोड़ की पूंजी डाली जाएगी। इस पूंजी में 70 फीसदी का योगदान एयरटेल करेगी, जबकि शेष 30 फीसदी हिस्सा प्रवर्तक समूह भारती एंटरप्राइजेज की तरफ से आएगा। एजेंसी

वित्त मंत्री की बैंकों को चेतावनी...कहा, जमा जुटाने और कर्ज देने पर बढ़ाएं फोकस

गलत तरीके से बीमा और अन्य वित्तीय उत्पाद बेचना अपराध, मुख्य कारोबार पर ध्यान दें बैंक

अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बीमा सहित अन्य वित्तीय उत्पाद गलत तरीके से बेचना भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध है। इसलिए, बैंक ऐसे कार्यों की जगह अपने मुख्य कारोबार यानी जमा जुटाने और कर्ज देने पर ध्यान केंद्रित करें।

वित्त मंत्री ने सोमवार को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को बजट के बाद संबोधन में कहा, मैंने हमेशा से इस बात पर आपत्ति जताई है कि आप (बैंक) उस बीमा को बेचने में अधिक समय लगा रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। यह मामला आरबीआई और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के बीच फंसा है।

आरबीआई ने इससे पहले ग्राहक को भ्रामक जानकारी देकर बीमा एवं अन्य वित्तीय उत्पादों की बिक्री पर दिशानिर्देशों का मसौदा 11 फरवरी को जारी किया था। इसके मुताबिक, अगर कोई बैंक किसी ग्राहक को गलत तरीके से उत्पाद या सेवाएं बेचता है, तो उसे ग्राहक की ओर से चुकाई गई पूरी रकम वापस करनी होगी। साथ ही, स्वीकृत नियमों के अनुसार हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। उत्पादों एवं सेवाओं की गलत बिक्री से जुड़े ये सख्त नियम एक जुलाई, 2026 से लागू होंगे, जिन पर चार मार्च तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई हैं। सीतारमण ने कहा, मुझे खुशी है कि आरबीआई बैंकों को स्पष्ट एवं सख्त मार्गदर्शन दे रहा है कि गलत तरीके से बिक्री क्यों बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैंकों तक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि आप गलत बिक्री नहीं कर सकते।

आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गवर्नर संजय मल्होत्रा।

नियामकीय अंतर के कारण ग्राहकों को उठाना पड़ा नुकसान

वित्त मंत्री ने कहा, बैंक ग्राहकों को बीमा उत्पाद खरीदने के लिए कहते हैं, जबकि उनके पास पहले से जरूरी बीमा होता है। आरबीआई यह सोचकर ऐसे मामलों की निगरानी नहीं कर रहा था कि यह इरडा के दायरे में आता है, जबकि बीमा नियामक का मानना था कि बैंक उसके प्रत्यक्ष नियमन में नहीं आते। इस नियामकीय अंतर के कारण ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ा।

- सीतारमण ने उदाहरण देते हुए कहा, **जब कोई व्यक्ति संपत्ति गिरवी रखकर होम लोन लेता है, तो उससे अतिरिक्त बीमा लेने को क्यों कहा जाता है, जबकि जोखिम पहले से कवर होता है।**

अमेरिकी टैरिफ में बदलाव के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर टिप्पणी करना जल्दबाजी

वित्त मंत्री ने कहा, अमेरिकी टैरिफ में बदलावों का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। वाणिज्य मंत्रालय इस स्थिति की समीक्षा कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल को यह तय करना होगा कि आगे की वार्ताओं के लिए वे कब जाएंगे। वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव दर्पण जैन इस समझौते के लिए भारत के मुख्य वार्ताकार हैं।

- सीतारमण ने कहा, भारत व्यापार समझौतों के प्रति स्पष्ट रुख रखता है। हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन से समझौते कर चुका है। **इसलिए, अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करने का हमारा प्रयास जारी रहेगा।**
- भारत चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर व्यापार करने और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने का लाभ मिले।

नकदी उपलब्धता के लिए हर कदम उठाएंगे : गवर्नर

आरबीआई गवर्नर ने बाजार को आश्वस्त करते हुए कहा, केंद्रीय बैंक सभी बाजार सेगमेंट को पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। सरकारी बॉन्ड की द्वितीयक अदला-बदली पर कहा, यह ऋण प्रबंधन का एक जरिया है, न कि बाजार में नकदी को नियंत्रित करने का तरीका। उन्होंने बताया, 2025-26 में सरकार ने 1.13 लाख करोड़ के बॉन्ड की अदला-बदली की। इसमें 12 फरवरी को 2026-27 में पूरे होने वाले 75,504 करोड़ रुपये के बॉन्ड भी शामिल थे।

आश्वासन

- **ई-रुपया नकद या यूपीआई का विकल्प नहीं :** गवर्नर ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पर कहा, ई-रुपया वर्तमान में नकद या यूपीआई का विकल्प नहीं है। यह मौजूदा भुगतान प्रणालियों को और मजबूत करने का साधन है। इसे बड़े पैमाने पर तभी लागू किया जाएगा, जब इसके सभी फीचर का पूरा तरह परीक्षण और मूल्यांकन कर लिया जाएगा।

जल्द लौटाई जाएगी 7.11 लाख निष्क्रिय पीएफ खातों में पड़ी राशि

- श्रम मंत्रालय का फैसला, बंद होंगे 31.86 लाख निष्क्रिय खाते

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 7.11 लाख निष्क्रिय खातों में फंसे 30.52 करोड़ रुपये जल्द संबंधित खाताधारकों या उनके कानूनी वारिसों को लौटाए जाएंगे। श्रम मंत्रालय का यह फैसला ऐसे 31.86 लाख खातों को बंद करने की पहल का हिस्सा है, जो मौजूदा समय में निष्क्रिय पड़े हैं। मंत्रालय के मुताबिक इनमें कुछ खाते 20 साल तक पुराने हैं, जिनमें तीन साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ।

मंत्रालय ने बताया कि निष्क्रिय खातों को बंद करने के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी ऐसे सात लाख खातों को चुना गया है, जिनमें शून्य से 1,000 रुपये तक राशि जमा है और ये आधार से जुड़े हैं। लिहाजा, ईपीएफओ सीधे उनके खाते में यह पैसे ट्रांसफर कर देगा। इन खातों में 30.52 करोड़ रुपये जमा हैं। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर बाकी खातों में भी इसी तरह से पैसे लौटा दिए जाएंगे।

निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भविष्य निधि एक अनिवार्य सरकारी योजना है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन का 12 फीसदी हिस्सा डालता है, जबकि नियोक्ता की ओर से भी उतना ही योगदान दिया जाता है। लेकिन, जब खाते में तीन साल तक कोई लेनदेन नहीं होता तो यह निष्क्रिय खाते में तब्दील हो जाता है। श्रम मंत्रालय अब ऐसे खातों को अब बंद करने की ओर बढ़ रहा है।

30.52 करोड़ रुपये फंसे हैं सात लाख निष्क्रिय खातों में

कुल 10,903 करोड़ जमा

ईपीएफओ में करीब 31.86 लाख निष्क्रिय पीएफ खाते हैं, जिनमें कुल 10,903 करोड़ रुपये जमा हैं। सरकार के मुताबिक ईपीएफओ सदस्य अपना पैसा निकालने के लिए अब आसानी से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन, यह भी देखने में आया है कि जिन खातों में पैसे कम हैं, वहां सदस्य आने-जाने के झंझट से बचने के लिए उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं।

छोटी राशि बड़ी परेशानी

पीएफ की छोटी-छोटी धनराशि बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि इस तरह से हजारों करोड़ रुपये निष्क्रिय खातों में पड़े हैं। लोग इन्हें निकालना नहीं चाहते और मंत्रालय के लिए पैसे की जवाबदेही बनी हुई है। इससे आधिकारिक दिशानिर्देश और तय समय पर काम करने की योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं।

सरकारी संपत्तियों से 16.72 लाख करोड़ जुटाएगा केंद्र

वित्त मंत्री ने लक्ष्य पाने के लिए पेश किया राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन का दूसरा चरण

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र ने अगले पांच वर्षों में सरकारी संपत्तियों को पट्टे पर देकर कुल 16.72 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को आसानी से हासिल करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन का दूसरा चरण (एनएमपी) 2.0 पेश किया।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, एनएमपी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के जरिये वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2029-30 के दौरान कुल 16.72 लाख करोड़ रुपये जुटाने की संभावित क्षमता का आकलन किया गया है। इसमें 5.8 लाख करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के निवेश के रूप में शामिल हैं। नीति आयोग ने एनएमपी 1.0 को 2021 में 2022-25 की अवधि के लिए शुरू किया था। इसमें चालू सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। इस चरण में 5.3 लाख करोड़ जुटाए जा चुके हैं, जो लक्ष्य का करीब 89 फीसदी है।

एनएमपी 2.0 को पेश करतीं निर्मला सीतारमण।

एनएमपी 2.0 विकसित भारत लक्ष्य के अनुरूप

सीतारमण ने कहा, एनएमपी 2.0 विकसित भारत लक्ष्य के अनुरूप है और बुनियादी ढांचा विकास को गति देकर आर्थिक वृद्धि को समर्थन देगी। इसके लिए मंत्रालय प्रक्रिया सरलीकरण और मानकीकरण पर ध्यान दें, ताकि परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण निर्बाध एवं समयबद्ध तरीके से हो सके।

राजमार्ग से 4.42 लाख करोड़ जुटाने की तैयारी

क्षेत्रवार लक्ष्यों के तहत राजमार्ग से 4.42 लाख करोड़, बिजली से 2.77 लाख करोड़, बंदरगाह से 2.64 लाख करोड़ और रेलवे से 2.62 लाख करोड़ जुटाने का अनुमान है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नागर विमानन, गोदाम, शहरी बुनियादी ढांचे, कोयला, दूरसंचार और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी परिसंपत्तियों को भी शामिल किया गया है। मौद्रीकरण से मिलने वाली राशि को नए पूंजीगत व्यय में पुनर्निवेश किया जाएगा, जिससे बजटीय बोझ कम होगा।

चुनौतियों के बाद भी कपड़ा निर्यात 1.6 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली। वैश्विक चुनौतियों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी बाधाओं के बावजूद भारत के कपड़ा निर्यात में 2025-26 की अप्रैल-जनवरी अवधि में 1.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन ए. शक्तिवेल ने कहा, इटली में भारतीय कपड़ों का निर्यात 16 फीसदी बढ़ा है। ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन सहित कई खास बाजारों में निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। एजेंसी

सेंसेक्स 480 अंक चढ़ा, 2.07 लाख करोड़ बढ़ी पूंजी

टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद बाजार में तेजी, निफ्टी में 142 अंक की तेजी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिका में टैरिफ आदेश रद्द होने से उपजी सकारात्मक धारणा के बीच सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वाहन और वित्तीय शेयरों में खरीदारी से घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 480 अंक चढ़ गया, जबकि निफ्टी में 142 अंक की तेजी दर्ज की गई।

विश्लेषकों ने कहा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले साल जारी व्यापक टैरिफ आदेशों को अवैध घोषित किए जाने के बाद निवेशक धारणा में सुधार देखा गया। सेंसेक्स 479.95 अंक चढ़कर 83,294.66 पर बंद हुआ। दिन में एक समय यह 671.44 अंक उछलकर 83,486.15 तक पहुंच गया था। निफ्टी भी 141.75 अंक बढ़कर 25,713 पर बंद हुआ। दिन में एक समय यह 200.2 अंक चढ़कर 25,771.45 के स्तर पर पहुंच गया था। बाजार में तेजी से बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी 2.07 लाख करोड़ बढ़कर 469.19 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर बढ़त में रहे। अदाणी पोर्ट्स सर्वाधिक 2.98 फीसदी लाभ में बंद हुआ। 10 कंपनियों के शेयरों में गिरावट रहे। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने घरेलू बाजार में शुद्ध रूप से 3,483.70 करोड़ रुपये की खरीदारी की। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,292.24 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की। बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 0.41 फीसदी बढ़त में रहा।

10 करोड़ मूल्य वाले लग्जरी मकानों की बिक्री में गुरुग्राम ने मुंबई को पीछे छोड़ा

गुरुग्राम ने 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक कीमत वाले लग्जरी मकानों की बिक्री मूल्य के मामले में मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। रियल्टी सलाहकार इंडिया सॉथबीज इंटरनेशनल रियल्टी एवं सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दो साल में लग्जरी सेगमेंट 10 गुना बढ़ा है। यह मजबूत पूंजी प्रवाह और अत्यधिक अमीरों की बढ़ती संख्या का संकेत है। ब्यूरो

ऐसे आगे निकला गुरुग्राम

24,120 करोड़ रुपये के लग्जरी मकान बिके गुरुग्राम में 2025 में

21,902 करोड़ के लग्जरी मकान बिके मुंबई में बीते साल

मूल्य के हिसाब से सालाना आधार पर 80% की बढ़ोतरी

बिक्री में उछाल

1,494 लग्जरी मकान बिके गुरुग्राम में 2025 में

सालाना आधार पर करीब तीन गुना की बढ़ोतरी

13,384 करोड़ के 519 लग्जरी मकान बिके थे 2024 में

गुरुग्राम में इसलिए बढ़ रही मांग

इंडिया सॉथबीज इंटरनेशनल रियल्टी की निदेशक (एरिया) टीना तलवार ने कहा, गुरुग्राम में वृद्धि अब सिर्फ पुराने प्रतिष्ठित इलाकों तक सीमित नहीं है।

द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसे उभरते बाजार सामूहिक रूप से संरचनात्मक विस्तार को गति दे रहे हैं।

निर्यातकों को मिलने वाले शुल्क लाभ दर में 50 फीसदी की कटौती

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को निर्यात सहायता योजना (आरओडीटीईपी) के तहत निर्यातकों को दिए जाने वाले शुल्क लाभ की दरों में 50 फीसदी की कटौती की है। निर्यातक समुदाय ने सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के मुताबिक, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क व करों की वापसी (आरओडीटीईपी) योजना के तहत लागू दरें और मूल्य-सीमा तत्काल प्रभाव से मौजूदा दरों के 50 फीसदी तक सीमित रहेंगी। योजना के तहत अब तक 0.3 फीसदी से लेकर 3.9 फीसदी तक कर एवं शुल्क की वापसी दी जाती थी। सरकार के इस कदम पर निर्यातक संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष एससी रल्हन ने कहा कि दरों और मूल्य सीमा में 50 फीसदी की कटौती ऐसे समय में की गई है, जब भारतीय निर्यात वैश्विक मांग में सुस्ती, अनिश्चितता और संरक्षणवादी नीतियों जैसी चुनौतियों का पहले से ही सामना कर रहे हैं। हम सरकार से इस पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हैं। सरकार ने निर्यातकों के लिए 2021 में यह योजना शुरू की थी। एजेंसी

निर्यातक समुदाय ने सरकार से आरओडीटीईपी फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की

कैट का दावा | देशभर के व्यापारियों की होली को लेकर खास तैयारियां...पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान का बाजारों में दिख रहा असर

होली पर 80,000 करोड़ से अधिक की होगी खरीद-बिक्री, स्वदेशी उत्पादों की मांग

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। रंगों के त्योहार होली के अवसर पर देशभर में 80,000 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष होली पर हुए 60,000 करोड़ के कारोबार की तुलना में 25 फीसदी अधिक है।

कन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के मुताबिक, देशभर के व्यापारियों ने होली को लेकर खास तैयारियां की हैं। होली से जुड़ी वस्तुओं के अलावा मिठाइयों, ड्राई फ्रूट्स, गिफ्ट आइटम, फूल-फल, कपड़े, फर्निशिंग फैब्रिक, किराना, एफएमसीजी उत्पादों और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की भी भारी मांग है। होली खेलने के लिए सफेद टी-शर्ट, कुर्ता-पायजामा, सलवार-सूट और हैप्पी होली लिखे टी-शर्ट भी खूब बिक रहे हैं।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान का व्यापक प्रभाव बाजारों में दिखाई दे रहा है। स्वदेशी निर्मित हर्बल गुलाल, प्राकृतिक रंग, पिचकारियां, गुब्बारे, पूजन सामग्री, परिधान और अन्य उत्पादों की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है, जबकि 2021 से पहले होली पर बाजारों में चीनी सामान का दबदबा रहता था।

25% बढ़ेगा कारोबार इस साल होली पर

पिछले साल 60,000 करोड़ की हुई थी खरीद-बिक्री

दिल्ली में 15,000 करोड़ रुपये का होगा कारोबार

कैट के अनुमान के मुताबिक, होली के त्योहार पर सिर्फ दिल्ली में ही करीब 15,000 करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है। शहर के थोक और खुदरा बाजार रंग-बिरंगे गुलाल, आकर्षक पिचकारियों, गुझिया की मालाओं और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट से सजे हुए हैं। मिठाई की दुकानों पर भी विशेष रूप से होली की पारंपरिक मिठाई गुझिया की बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है।

होली मिलन समारोह के लिए बुक हो चुके हैं बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस और होटल

खंडेलवाल ने बताया, देशभर में होली मिलन समारोह बड़े स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। **दिल्ली में ही विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों की ओर से 3000 से अधिक होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।** इसके चलते बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक पार्क लगभग बुक हो चुके हैं। **खास बात है कि लोग केमिकल रंगों की बजाय हर्बल और प्राकृतिक रंगों को अधिक पसंद कर रहे हैं।**

खुदरा विक्रेताओं और एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण त्योहार

कैट ने कहा, होली जैसे त्योहार सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव ही नहीं होते, बल्कि वे आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार देते हैं। इस वर्ष की होली खुदरा विक्रेताओं, छोटे व्यापारियों, कुटीर उद्योगों और एमएसएमई क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। **स्वदेशी व्यापार को और मजबूती प्रदान करेगी।**

प्रेरणा

हर कोशिश कामयाब नहीं होती, लेकिन हर कोशिश जरूरी होती है। -थॉमस एडिसन

संपादकीय

आर्थिक असमानता बढ़ने के कारणों को समझना होगा

भारत की वर्तमान विकास-दिशा को अर्थशास्त्री लीप फ्रॉग अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बगैर औद्योगिक विकास किए यानी कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को निकाले बिना सेवा-क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ा दी गई है। लिहाजा एक तरफ उच्च वेतन वाला इंजीनियर और कम वेतन वाला डिलीवरी बॉय या कैब ड्राइवर है और दूसरी ओर डिजिटल डिवाइड का शिकार बेहद गरीब, अकुशल खेतिहर मजदूर। बजट में भी हाई-टेक ग्रोथ पर ही सरकार का जोर रहा है, जबकि भारत के आम आदमी का घर चीन-निर्मित सामानों से भरा है। इससे गरीब-अमीर की खाई बढ़ी है। नोबेल विजेता लेविस के विकास मॉडल को 70 साल पहले अमेरिका और यूरोप और फिर 1980 के बाद चीन ने अपनाया और सफल रहे। यह मॉडल था- करोड़ों श्रमिकों को बेहतर आय के लिए कृषि से मैन्युफैक्चरिंग और फिर सेवा क्षेत्र में लाना। इसकी शर्त थी कृषि का मशीनीकरण करके उसे लाभप्रद बनाना और उसमें से बाहर हुए युवाओं को स्किल देकर मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर पगार पर लाना। फिर औद्योगिक श्रमिकों की अगली पीढ़ी को बेहतर तकनीकी शिक्षा से लैस कर टेक और सेवा क्षेत्र में और बेहतर वेतन पर ले जाना। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में सरकारों ने सेवा क्षेत्र को व्यापक विस्तार दिया, जिससे उद्योग पीछे छूट गया। लीप फ्रॉग इकोनॉमी में आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

अपने काम से प्रेम करिए तो कर्म बोझ नहीं लगेगा

आजकल ट्रांसफरेबल स्किल्स का जमाना है। इसे सीधी भाषा में कहें तो किसी एक काम में दूसरे काम के कौशल को उतारना। जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, समय प्रबंधन, डेटा विश्लेषण। एक ही काम में इन सबको जोड़ना पड़ेगा। यह प्रबंधन के ढंग हैं। अब इसी में अगर अध्यात्म का सहारा लें तो ऋषि-मुनियों ने शास्त्रों में एक स्किल और बताई है, और वो है प्रेम। ये हर जगह काम आएगी। काकभुशुंडि जी ने जब गरुड़ जी को कथा सुनानी शुरू की तो तुलसीदास जी ने लिखा- प्रथमहिं अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेसि बखानी। भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा और फिर आगे कथा बढ़ाई। यह बात शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं। कथा में बोलते समय उन्होंने प्रेम उतारा। वक्तव्य में प्रेम हो तो मिठास, अपनापन, वाणी की गरिमा अपने आप आ जाती है। जो भी काम करें, प्रेम से करें और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने काम से प्रेम करिए तो आपका कर्म आपको बोझ नहीं लगेगा।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

दूरदृष्टि • सोना खरीदने वाले विश्वास बनाए रखें

सोने के दामों में तेजी से आई चमक का रहस्य क्या है?

गोल्ड रश

रुचिर शर्मा
ग्लोबल इन्वेस्टर व लेखक
breakoutnations@gmail.com

वर्षों तक उछाल के बाद सोने की कीमतें अब ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं, जहां अब 'स्टोरीटेलिंग' उसकी दिशा तय कर रही है। सोने के दाम उन बुनियादी शक्तियों से मुक्त हो चुके हैं, जो लंबे समय तक उसके उतार-चढ़ाव के नियम तय करती रही थीं। अब वह वैश्विक जोखिम और अनिश्चितता की कहानियों के सहारे ऊपर बढ़ रहा है। विश्लेषकों को तो यह दौर 1970 के दशक के 'गोल्ड रश' जैसा लगने लगा है।

सोना लंबे समय से सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता रहा है, क्योंकि उसकी कीमतें सदियों तक मुद्रास्फीति की दर के साथ कदम मिलाती रही हैं। हालांकि बीच-बीच में उसमें भी गिरावट और उछाल आते रहे हैं। उछाल आम तौर पर उस कालखंड में आते थे, जब वास्तविक ब्याज दरें घटती थीं। जब बचत खातों या बॉन्ड्स में रखे धन पर रिटर्न कम होता था तो लोग अपनी संपत्ति सोने में स्थानांतरित करने लगते थे।

यह पैटर्न 2023 में बदलना शुरू हुआ। ब्याज दरें अतीत की तुलना में ऊंची थीं और बढ़ रही थीं, फिर भी सोने की कीमतें चढ़ने लगीं। इसका प्रमुख कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीद में वृद्धि थी, जो अपनी होल्डिंग्स को डॉलर से हटाना चाहते थे। यह वही डॉलर है, जिसे अमेरिका ने रूस पर लगाए प्रतिबंधों में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। तब से सोने की कीमतें आसमान छू चुकी हैं। किंतु जिसे मैंने कभी विदेशी केंद्रीय बैंकों के नेतृत्व में डॉलर-विरोधी क्रांति कहा था, वह अब इसकी व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

पिछले एक वर्ष में केंद्रीय बैंकों की खरीद की गति धीमी पड़ गई है। ऊंची कीमतों के चलते उपभोक्ताओं की हिचकिचाहट से गहनों की मांग में गिरावट आई है। इसके विपरीत, भारत से लेकर चीन और अमेरिका से लेकर यूके तक सभी प्रमुख बाजारों में निवेशकों की मांग विस्फोटक रूप से बढ़ी है। पिछले वर्ष वैश्विक स्तर पर सोने की कुल खरीद में निवेशकों की हिस्सेदारी दोगुनी होकर 35% तक पहुंच गई। सोने के सभी निवेश योग्य रूपों- बिस्किट और सिक्कों से लेकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स तक- में निवेश का तेज प्रवाह नजर आने लगा।

विशेषकर भारतीयों को सोने के प्रति विशेष लगाव के लिए जाना जाता है। आकलनों के अनुसार भारतीय घरों में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है : 28,000 टन, जो कुल वैश्विक भंडार का 14% है। किंतु पिछले वर्ष भारतीयों ने भी सोने के आभूषणों पर कम और सोने से जुड़े निवेश उत्पादों पर अधिक व्यय किया।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि भारत में गोल्ड ईटीएफ का असाधारण उछाल नए उत्पाद प्रस्तावों की एक श्रृंखला को प्रेरित कर रहा है, जो इस वर्ष भी इस तेजी को बनाए रखने में सहायक हो सकता है।

संक्षेप में, सोना अब मुख्यतः वित्तीय मांग से संचालित हो रहा है और यह बदलाव उसके मूल्यांकन की पारम्परिक समझ को उलट रहा है। सोने की कीमत को समझाने के लिए लंबे समय से प्रयुक्त मॉडल- जिनमें वास्तविक बॉन्ड यील्ड्स और मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं शामिल थीं- अब निष्प्रभावी हो चुके हैं।

सोने में तेजी के पक्षधर यह तर्क दे रहे हैं कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य अतीत की गोल्ड सुपर-साइकिल्स की पृष्ठभूमि जैसा है- यानी 2000 के दशक और विशेष रूप से 1970 के दशक जैसे लंबे और प्रबल तेजी के दौर। किंतु आज की मुद्रास्फीति जिमी कार्टर के दौर के डबल-डिजिट स्तरों के आसपास भी नहीं है। और यह तर्क देना कठिन है कि ट्रम्प, टैरिफ और यूक्रेन जैसी अनिश्चितताएं आज उतनी ही अधिक विचलित करने वाली हैं, जितनी उस समय तेल प्रतिबंध, वियतनाम युद्ध और ईरान बंधक संकट थे।

एक अन्य तर्क यह है कि सोना डॉलर के अवमूल्यन

सोने के प्रबल समर्थक कहते हैं कि इस पीली धातु में अभी और ऊपर जाने की पर्याप्त गुंजाइश है। पिछले दस वर्षों में यह तीन गुना से अधिक बढ़ चुका है। किंतु 1970 के दशक की बारह गुना वृद्धि की तुलना में यह बहुत आवक नहीं है।

से बचाव के साधन के रूप में फल-फूल रहा है। किंतु यदि ऐसा है तो डॉलर के अन्य विकल्प जैसे बिटकॉइन क्यों गिरावट में हैं और अमेरिकी शेयरों तथा बॉन्ड जैसे अन्य डॉलर-आधारित एसेट्स क्यों टिके हुए हैं?

यही कारण है कि सोने के प्रबल समर्थक कहते हैं कि इस पीली धातु में अभी और ऊपर जाने की पर्याप्त गुंजाइश है। और वे सही भी हो सकते हैं। पिछले दस वर्षों में यह तीन गुना से अधिक बढ़ चुका है। किंतु 1970 के दशक की बारह गुना वृद्धि की तुलना में यह बहुत अधिक नहीं है। उस समय तो मात्र दो महीनों में सोने की कीमतें दोगुनी हो गई थीं।

मैं कई वर्षों से सोने के प्रति सकारात्मक रुख रखता रहा हूं, लेकिन अब मैं अधिक तटस्थ हूं। अनियमित कथानकों से संचालित होने वाले बाजार में यह जान पाना कठिन होता है कि कौन-सा नैरेटिव वास्तविक है और टिकेगा। यदि आप और सोना खरीदना चाहते हैं, तो आपको बस विश्वास बनाए रखना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मुद्दा • सांसद निधि के औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं

सांसदों को अपने फंड का बेहतर उपयोग सीखना होगा

विकास

संजय कुमार
प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार
sanjay@csds.in

हाल में कुछ सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लैड निधि के उपयोग-दुरुपयोग का मामला सामने आया है। संसद के दोनों सदनों में भी सांसद निधि के औचित्य पर सवाल उठाए गए। पहली बार यह मुद्दा तब उठा था, जब राजस्थान में झुंझुनूं के सांसद ने 25 लाख रुपए, चूरू सांसद ने 50 लाख रुपए और भरतपुर सांसद ने 45 लाख रुपए अपनी-अपनी सांसद निधि से हरियाणा के कैथल जिले में विकास कार्यों के लिए आवंटित करने की सिफारिश की। मामला तब फिर गरमाया, जब जम्मू-कश्मीर से भाजपा के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने भी अपने राज्य के बजाय यूपी के लिए बड़ी राशि आवंटित कर दी।

जब राजस्थान के कांग्रेस सांसदों ने अपने राज्य के बजाय हरियाणा में विकास कार्यों के लिए राशि दी तो भाजपा ने आरोप लगाया कि यह एमपी लैड के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। इस योजना का मकसद ही सांसद के अपने क्षेत्र में विकास जरूरतों को पूरा करना है। फिर राज्य के बाहर पैसा खर्च करने का क्या औचित्य? भाजपा ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि कैथल रणदीप सुरजेवाला के पुत्र का विधानसभा क्षेत्र है। उधर खटाना द्वारा भी यूपी में धनराशि के इस्तेमाल करने की पीडीपी प्रवक्ता ने आलोचना की।

झुंझुनूं सांसद बृजेन्द्र सिंह ओला ने कहा कि आवंटन एमपी लैड गाइडलाइन और सरकारी आदेशों के तहत ही किया गया है। नियमों के अनुसार 50 लाख रुपए तक अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के कार्यों में दिए जा सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में 1 करोड़ रुपए तक की अनुशंसा भी अनुमत है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भाजपा सांसद भी आपत्तिजनक उद्देश्यों के लिए एमपी लैड राशि इस्तेमाल कर चुके हैं। इधर खटाना ने कहा कि वे मनोनीत सांसद हैं तो नियमानुसार देश के किसी भी हिस्से में विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

यदि सांसदों ने अपने राज्य के बाहर विकास के लिए राशि आवंटित की है तो उन्होंने ऐसा नियमों के तहत ही किया होगा। लेकिन चूंकि यह धारणा है कि सांसद अपनी निधि का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये घटनाएं हमें इस बड़े सवाल पर चर्चा का अवसर देती हैं कि आखिर एमपी लैड राशि को बरकरार रखने का औचित्य क्या है? इस पर दो समानांतर तर्क सामने आते हैं। पहला, यह निधि खत्म होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में सांसद विकास कार्यों के लिए पूरी राशि का उपयोग नहीं कर पाते। इसका विरोधी तर्क यह है कि सांसदों को विकास कार्यों के लिए ऐसी निधि की आवश्यकता है, इसलिए यह बरकरार रहनी चाहिए।

एमपी लैड योजना में हर सांसद कुछेक अपवादों को छोड़ प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों की सिफारिश कर सकता है। 17वीं लोकसभा के दौरान लगभग 4837.87 करोड़ रुपए एमपी लैड के लिए आवंटित किए गए थे, जिनमें से कथित तौर पर 3639.53 करोड़ रुपए खर्च हुए। कुल 96211 कार्यों की सिफारिश की गई, जिनमें से 41143 कार्य पूरे हुए।

हालांकि यह आंकड़ा बताता है कि लगभग आधे कार्य पूरे नहीं हो सके, लेकिन कुल आवंटित बजट का लगभग 75% विकास कार्यों पर खर्च हो गया। वर्तमान लोकसभा में अब तक 5486 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं, जिनमें से 1453.69 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और कई विकास कार्य अभी प्रगति पर हैं।

यह सही है कि एमपी लैड पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार 17वीं लोकसभा (2019-2024) के दौरान कुल आवंटित बजट का 16.24% हिस्सा खर्च नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा मुख्यत: कोविड के कारण हुआ, जब विकास परियोजनाएं स्थगित कर दी गई थीं।

हो सकता है कि कुछ सांसद अपनी निधि का पूरा उपयोग नहीं कर पाए हों, लेकिन इसे व्यापक चलन नहीं कहा जा सकता। ऐसे कई उल्लेखनीय उदाहरण भी हमारे सामने हैं, जहां सांसदों ने अपने पूरे आवंटित कोश का इस्तेमाल किया।

लेकिन पिछली कुछ लोकसभाओं के दौरान एमपी लैड निधि का इस्तेमाल अपेक्षाकृत बेहतर हुआ है।

16वीं लोकसभा (2014-2019) में केवल 8.7% निधि खर्च नहीं हो पाई, 15वीं (2009-2014) में यह आंकड़ा 3.47% था। 14वीं (2004-2009) में तो यह और भी कम मात्र 0.99% ही रहा था। हो सकता है कुछ सांसद अपनी निधि का पूरा उपयोग नहीं कर पाए हों, लेकिन इसे व्यापक चलन नहीं कहा जा सकता। बेहतर यह होगा कि छोटी कार्यशालाओं और विशेषज्ञों के जरिए सांसदों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाए कि वे विकास कार्यों में सांसद निधि का सबसे बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

दैनिक भास्कर
अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

अभियान

एआई कंपनियां चुनाव में करोड़ों रुपए लगाएंगी

थ्योडोर स्कलीफर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री अमेरिका में होने वाले संसद के मध्यावधि चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च करने वाली है। 2025 में एआई कंपनियों और उनके बड़े अधिकारियों ने चुनाव अभियानों और चुनाव समितियों को 750 करोड़ रुपए दिए थे। टेक कंपनी मेटा ने राज्य स्तर पर 590 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। अब मध्यावधि चुनावों के लिए डोनेशन जारी है।

चुनावी चंदे से ज्यादा फायदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी को होगा। रिपब्लिकन नेता इंडस्ट्री के बड़े समर्थक हैं। वे कठोर एआई नियमन के खिलाफ हैं। वैसे विश्लेषण से पता लगा है कि टेक इंडस्ट्री से लंबे समय से रिश्ते रखने वाले कुछ डेमोक्रेटिक राजनेताओं को भी एआई कंपनियों से काफी कैश मिलेगा। रिपब्लिकन्स के दो सबसे बड़े डोनर ओपन एआई के को-फाउंडर ग्रेग ब्रॉकमैन और उनकी पत्नी एना हैं। दोनों ने 12 सितंबर 2025 तक 113-113 करोड़ रुपए दिए हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि एआई इंडस्ट्री और उसके सहयोगी इस वर्ष चुनावों में कितना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन चुनाव के लिए बहुत धन आने वाला है। एआई सुपर पीएसी लीडिंग द फ्यूचर का कहना है कि वर्ष की पहली तिमाही में उसे ब्रॉकमैन और वेंचर कैपिटल फर्म एंड्रीसन होरोविट्ज से 450 करोड़ रुपए मिलेंगे।

© The New York Times

टेक्नोलॉजी फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए यूरोप में भारी खर्च कर रही हैं

सोशल मीडिया पर रोक के खिलाफ टेक कंपनियों की मुहिम, सांसदों की लॉबिंग पर 1615 करोड़ रुपए खर्च

विविएन वाल्ट

फेसबुक और गूगल सहित अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के सामने एक नई तरह की चुनौती आ रही है। कई देशों की सरकारें टीनएजर्स के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर रोक लगा रही हैं। वे एप्स को लत लगाने वाला और नुकसानदेह बता रही हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी कंपनियां ने जवाबी मुहिम छेड़ दी है। यूरोपियन यूनियन (ईयू) में अमेरिकी कंपनियों ने पिछले साल बड़े होर्डिंग लगाने, राजनेताओं को लुभाने और अपनी लॉबिंग लॉबी मजबूत करने पर भारी खर्च किया है।

दरअसल, यूरोपीय संसद में टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं। 720 सदस्यीय संसद में सोशल मीडिया पर बैन के विधेयकों को आसानी से रोका जा सकता है। बड़ी टेक कंपनियों ने ईयू के सांसदों की लॉबिंग पर पिछले वर्ष 1615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कॉरपोरेट यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी और लॉबी कंट्रोल संगठन के अनुसार 2021 से 2025 के बीच फैसलों को इंडस्ट्री के पक्ष में करने के लिए चली मुहिम में 55% से अधिक इजाफा हुआ है। सबसे अधिक खर्च फेसबुक की कंपनी मेटा ने किया है। इसके बाद गूगल है। इन कंपनियों के खिलाफ याचिका दायर करने वालों ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब को डिजिटल कैसिनो कहा है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों का आरोप है कि प्लेटफॉर्म के अनंत स्क्रॉलिंग जैसे फीचर युवा यूजरों को आदी बनाते हैं।

टेक कंपनियां मानती हैं कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में लागू होने वाले नए कानून से दुनिया भर में उनके कामकाज पर असर पड़ेगा। इसलिए यूरोपीय राजनेताओं को मनाने पर ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। वे प्रतिबंध के विकल्प के लिए तगड़ी मुहिम चला रही हैं। यूरोपीय सांसदों से चर्चा में मेटा ने टीन अकाउंट्स का प्रस्ताव दिया है। 2024 में पेश इन अकाउंट्स में 16 साल से कम आयु के यूजर्स के अकाउंट पर पैरेंट्स का नियंत्रण रहता है। कुछ कंपनियां ने 15, 16 साल से कम आयु के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी करने का प्रस्ताव दिया है।

यूरोपीय आयोग इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमत हो गया है। यूरोप के प्रारूप प्रस्ताव डिजिटल फेयरनेस एक्ट पर ब्रसेल्स में इस साल मतदान हो सकता है।

सांसदों को प्रभावित करने के लिए 890 लॉबिस्ट सक्रिय

ब्रसेल्स में 890 फुलटाइम लॉबिस्ट काम कर रहे हैं। यह यूरोपीय संसद के सदस्यों की संख्या से अधिक है। ये लॉबिस्ट सोशल मीडिया बैन के खिलाफ अभियान चलाने के साथ यूरोप के एआई कानून और डेटा प्राइवेसी नियमों को बेअसर करना चाहते हैं। टेक कंपनियां धुर दक्षिणपंथी सांसदों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। अकेले मेटा ने जुलाई 2024 और दिसंबर 2025 के बीच सांसदों के साथ 38 बैठकें की हैं।

रेलवे स्टेशनों पर होर्डिंग से लेकर बड़े-बड़े विज्ञापन तक छप रहे

वाशिंगटन के ट्रेड ग्रुप- कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ब्रसेल्स में रेलवे स्टेशनों पर होर्डिंग लगाए हैं। इनमें ईयू से सोशल मीडिया प्रतिबंधों को रद्द करने की अपील की गई है। विज्ञापनों में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक जोहान्स गुटेनबर्ग, रेडियो बनाने वाले गुग्लिमो मार्कोनी जैसे यूरोपियन आईकन दिखाए गए हैं। पिछले साल नवंबर में मेटा ने यूरोप के अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन दिया।

अमेरिका के आठ राज्यों सहित कई देशों में पहल

पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ने किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क का कहना है कि वे जल्द अपनी नीति की घोषणा करेंगे। अमेरिका के 8 राज्यों में भी किशोरों को सोशल मीडिया से अलग रखने के विधेयक पेश किए गए हैं।

© The New York Times

इस हफ्ते चर्चा में...

अमेरिका व चीन के बीच कारोबार में गिरावट आई

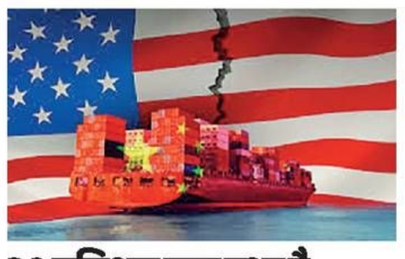

30 प्रतिशत कम हुआ है
अमेरिका में चीनी वस्तुओं का आयात 2025 में। अमेरिका के चीन को निर्यात की भी यही स्थिति है।

65934 करोड़ रुपए
चुकाएगी जर्मन केमिकल और दवा कंपनी बेयर। उसकी कीटनाशक दवा से कैंसर होने के दावे वाले मुकदमों को निपटाने के लिए।

एक करोड़ दस लाख
पर्यटक कम आए हैं अमेरिका में पिछले साल। यह 2024 के मुकाबले 6 प्रतिशत की गिरावट है।

बिजनेस टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 के अन्य प्रावधानों के प्रयोग की तैयारी

ट्रम्प प्रशासन फिर भारी टैरिफ लगा सकता है

टॉनी रोम, एलन रेपेपोर्ट, एना स्वांसन

अमेरिकी सरकार ने रविवार को संकेत दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए कुछ भारी टैरिफ फिर से लागू कर सकती है। शनिवार को ट्रम्प ने 15 प्रतिशत का नया टैरिफ लगाकर जताया है कि कानूनी आघात से कारोबार के संबंध में उसके मनमाने रवैये पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर ने रविवार को एबीसी टीवी पर कहा कि राष्ट्रपति टैरिफ के लिए अभियान चलाते रहे हैं। यह नीति नहीं बदली है। ट्रम्प ने सभी देशों पर 15 प्रतिशत टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 के तहत लगाया है। ट्रम्प प्रशासन इसी कानून के एक अन्य प्रावधान (धारा 301) के मुताबिक अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं की जांच करने की योजना बना रहा है।

व्यापार समझौते कायम रहने का दावा

वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को सीएनएन पर कहा कि टैरिफ से इस साल होने वाली आय में बदलाव नहीं किया गया है। अमेरिका के साथ कारोबार करने वाले देशों ने उन्हें बताया है कि अमेरिका से किए व्यापार समझौते कायम रहेंगे। बेसेंट ने 15 फीसदी ग्लोबल टैरिफ को इस साल बाद में लागू होने वाले टैरिफ के लिए एक पुल करार दिया है।

ग्रीयर ने कहा कि वे कुछ बिंदुओं पर जांच शुरू करेंगे। इसका फोकस अधिक औद्योगिक क्षमता, जबरिया काम कराने, दवाइयों के मूल्यों, अमेरिकी टेक कंपनियों के खिलाफ भेदभाव, सीफूड, चावल और अन्य प्रोडक्ट पर रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया के अधिकतर देशों पर टैरिफ लग सकता है। ग्रीयर ने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो अपना मकसद हासिल करने के लिए व्यापार प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि वह धारा 301 के तहत चीन और ब्राजील की जांच जारी रखेगा। अपने पहले कार्यकाल में ट्रम्प ने चीन से आयात पर टैरिफ लगाने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल किया था।

एक तरफ व्हाइट हाउस ने बेफिक्री दिखाई है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका की व्यापार नीति में परिवर्तन को देखते हुए अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। © The New York Times

खुलासा महारानी एंड्रयू को हमेशा बचाती रहीं

एपस्टीन कांड में फंसे एंड्रयू के खिलाफ किंग चार्ल्स का रवैया हमेशा सख्त रहा

सारा लायल

जेफ्री एपस्टीन सेक्स कांड में फंसे पूर्व प्रिंस एंड्रयू के प्रति ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का रुख नरम रहा है। लेकिन एंड्रयू के बड़े भाई किंग चार्ल्स का रवैया अपनी मां से एकदम अलग है। एपस्टीन से रिश्तों का खुलासा होने के बाद मार्च 2022 में एंड्रयू को शाही कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था। उनकी सैनिक उपाधियां छीन ली गई थीं। किंग चार्ल्स तृतीय ने हर नए खुलासे के बाद अपने भाई से अलग बर्ताव किया है। उस साल बाद में जब एलिजाबेथ की मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार में चार्ल्स ने उन्हें सैनिक यूनिफार्म पहनने से रोक दिया था।

कभी अच्छे नहीं रहे दोनों के रिश्ते

चार्ल्स और एंड्रयू के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इतिहासकार एंड्रयू लाउनी ने लिखा है कि, मिलिटरी सर्विस खत्म होने के बाद जब एंड्रयू को महारानी ने ब्रिटेन का विशेष व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया था, तब चार्ल्स ने इस नियुक्ति को रोकने की कोशिश की थी।

गुरुवार को जब पूर्व प्रिंस को सार्वजनिक पद पर गलत आचरण के संदेह में गिरफ्तार किया गया तब चार्ल्स ने कहा, मैंने गहरी चिंता के साथ एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के बारे में आई खबरों को जाना है। अधिकारियों को हमारा पूरा सहयोग और समर्थन है। © The New York Times

इकोनॉमी

धीमी पड़ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार

बेन कैसलमैन

2025 के अंत में अमेरिका अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, कंज्यूमर खर्च और एआई इनवेस्टमेंट में उछाल की वजह से टैरिफ और सरकारी शटडाउन के बावजूद पिछले साल विकास दर पटरी पर बनी रही। वाणिज्य विभाग ने बताया कि पिछले साल के अंतिम तीन महीनों में जीडीपी 1.4 फीसदी की सालाना दर से बढ़ी। यह तीसरी तिमाही के 4.4 फीसदी से काफी कम है। लंबा शटडाउन इसका मुख्य कारण है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने चुनाव अभियान में वादा किया था कि चुने जाने के बाद वे पहले दिन महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन 2025 में महंगाई अधिक रही। दिसंबर में कंज्यूमर मूल्य 2.9 प्रतिशत बढ़ गया। वस्तुओं में व्यापार घाटा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब कम हो गए। 2025 में जीडीपी में 2.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जबकि 2024 में यह 2.3 प्रतिशत थी।

© The New York Times

बिज़नेस भास्कर

Business Standard और TheEconomist की ख़बरों के साथ

नई दिल्ली, मंगलवार 24 फरवरी, 2026

लग्जरी हाउसिंग • गुरुग्राम में बीते साल रिकॉर्ड 24,120 करोड़ के घर बिके; स्टार्टअप फाउंडर्स, कंपनी प्रमोटरों की पहली पसंद बने नए ग्रोथ कॉरिडोर, 2 साल में 6 गुना बढ़ी मांग

रियल एस्टेट में पावर शिफ्टः 10 करोड़+ वाले घरों की रेस में गुरुग्राम ने मुंबई को पछाड़ा

भास्कर न्यूज | मुंबई

रियल एस्टेट में 2025 में नया रिकॉर्ड बना। गुरुग्राम ने ₹24,120 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री के साथ ₹10 करोड़ से महंगे घरों के बाजार में मुंबई को पछाड़ दिया। इंडिया सोदबी इंटरनेशनल और सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ 2 साल में इस सेगमेंट में छह गुना बढ़त ने गुरुग्राम को भारत का अल्ट्रा-लग्जरी रेजिडेंशियल हब बना दिया। मुंबई में 21,902 करोड़ के अल्ट्रा-लग्जरी घर बिके।

अल्ट्रा-लग्जरी घरः 2023 की तुलना में 10 गुना उछाल, नोएडा तीसरे नंबर पर

अल्ट्रा लग्जरी घरों की बिक्री 2023 की तुलना में करीब 10 गुना बढ़ी, जब केवल 155 ऐसे घर बिके थे। यह बढ़त धनाढ्य परिवारों की बढ़ती तादाद दर्शाती है। 2023 में इस कैटेगरी के घर ₹4,004 करोड़ के बिके थे। 2025 में ऐसे घरों के सौदे ₹24,000 करोड़ तक पहुंच गए।

आंकड़े करोड़ रुपए में

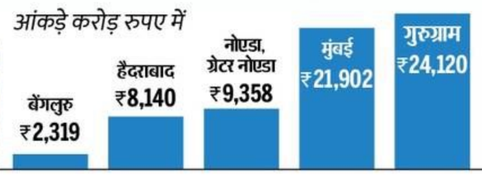

आखिर गुरुग्राम, नोएडा में नए ग्रोथ कॉरिडोर ने पुरानी जगहों को पीछे क्यों छोड़ा?

इसकी सबसे बड़ी वजह नए लग्जरी कॉरिडोर का उदय है। द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसे माइक्रो-मार्केट ने इस विस्तार को गति दी।

द्वारका एक्सप्रेसवेः यहां लेनदेन मूल्य में 2,079 फीसदी का उछाल देखा गया। साल 2024 में 383 करोड़ से बढ़कर 2025 में 8,347 रुपए करोड़ तक पहुंच गया।

गोल्फ कोर्स रोडः यहां बिक्री मूल्य में 379 फीसदी वृद्धि हुई। इसके साथ ही कीमतों में भी उछाल आया। औसत कीमत 24,855 रुपए से बढ़कर 37,899 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई।

नया धनाढ्य वर्ग उभराः 2025 में 103 कंपनियों ने आईपीओ से रिकॉर्ड ₹1.77 लाख करोड़ जुटाए। संस्थापकों, प्रमोटरों का एक नया वर्ग तैयार हुआ जो महंगे घर खरीद रहा है।

8,000 वर्ग फुट से बड़े घरों का कुल खरीद मूल्य में 22 फीसदी योगदान

गुरुग्राम के कुल हाउसिंग मार्केट में कुल बिक्री में अल्ट्रा-लग्जरी घरों की हिस्सेदारी 2025 में 24 फीसदी रही। यहां हर अल्ट्रा लग्जरी घर का औसत आकार लगभग 5,000 वर्ग फुट है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल बिक्री में 8,000 वर्ग फुट से बड़े घरों की हिस्सेदारी 22 फीसदी रही। यह दर्शाता है कि खरीदार प्राइवेसी और एक्सक्लूसिविटी के लिए प्रीमियम चुकाने को तैयार हैं। साथ ही लग्जरी सेगमेंट में भी बड़े आकार के मकानों की डिमांड ज्यादा देखी जा रही है।

भास्कर इन्फो

UPIः विदेश में 15 लाख लेनदेन, 1 साल में दोगुना

मुंबई | भारतीय पेमेंट सिस्टम यूपीआई ने देश के बाहर नया इतिहास रचा है। दिसंबर 2025 तक इसके जरिये अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पहली बार 10 लाख पार कर 14.8 लाख तक पहुंच गया। यह पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े 7.5 लाख से करीब दो गुना है।

इन 8 देशों में यूपीआई

भूटान, फ्रांस, मॉरीशस,नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई। **अपकमिंग मार्केटः** जापान और मलेशिया में भी जल्द शुरू होगा।

20 लाख से ज्यादा

अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों को अपने नेटवर्क से जोड़ चुकी है एनपीसीआई।

कुल ट्रांजैक्शन सिर्फ दो साल में 39 गुना

23-24	37,600
24-25	7,55,445
25-26	14,86,537

कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 साल में 17 गुना हुई

23-24	19.70 cr
24-25	258.53 cr
25-26	330.43 cr

आंकड़े दिसंबर, 2025 तक के, स्रोतः राज्यसभा

भास्कर एनालिसिस मीडिया, ऑटो की कायापलट, अब ग्रोथ निगेटिव से पॉजिटिव

इन्फ्रा, गहने, कच्चा तेल, केमिकल्स कंपनियों का मुनाफा 78% तक बढ़ा

भास्कर न्यूज | मुंबई

कॉरपोरेट सेक्टर की सेहत सुधरी है। अक्टूबर-दिसंबर में 3,488 भारतीय कंपनियों की बिक्री 8.5% बढ़कर 35.8 लाख करोड़ रुपए हो गई। इनका शुद्ध मुनाफा भी 11.5% बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। एक साल पहले इनकी बिक्री 5.8% और मुनाफा 10.2% बढ़ा था।

बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, बीती तिमाही इन्फ्रास्ट्रक्चर, हीरे-गहने, कच्चा तेल और केमिकल्स कंपनियों के मुनाफे में सबसे ज्यादा 78% तक बढ़ोतरी हुई। ऑटोमोबाइल और मीडिया-एंटरटेनमेंट सेक्टर का मुनाफा क्रमशः 19% और 10% बढ़ा। एक साल पहले इनके मुनाफे में 19% तक गिरावट आई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स में राहत, जीएसटी कटौती और कम ब्याज दरों पर लोन से मांग को सहारा मिला। हालांकि टेक्सटाइल जैसी निर्यातक कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इससे मुनाफे में लगातार गिरावट आई।

अक्टूबर-दिसंबर में 3,488 कंपनियों के नतीजे ऐसे समझें

सुधारः वॉल्यूम पर फोकस, मुनाफे के मुकाबले बिक्री वृद्धि ज्यादा तेज रही

साल	शुद्ध बिक्री	शुद्ध मुनाफा
2023	31,20,759	3,16,314
2024	33,00,284	3,48,606
2025	35,79,556	3,88,736
बढ़ोतरी		
2024	5.8%	10.2%
2025	8.5%	11.5%

(बीती तिमाही कंपनियों की शुद्ध बिक्री और मुनाफा करोड़ रुपए में)

कंपनियों के नतीजों से एक बात तो साफ है। बजट से लेकर जीएसटी-2.0 तक, सालभर में किए गए नीतिगत सुधारों ने सीधे उपभोक्ताओं से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया है। रिटेलिंग कंपनियों का मुनाफा फाइनेंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों से भी ज्यादा बढ़ना यही संकेत देता है। कमाई में सुधार आगामी तिमाहियों में जारी रह सकता है।
– मदन सबनवीस, चीफ इकोनॉमिस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा

शानदार इन सेक्टरों की कंपनियों का मुनाफा सबसे ज्यादा बढ़ा

बिजनेस सेक्टर	बिक्री बढ़ी 2024	बिक्री बढ़ी 2025	मुनाफा बढ़ा 2024	मुनाफा बढ़ा 2025
इन्फ्रास्ट्रक्चर	5.9%	5.7%	7.8%	78.4%
डायमंड, ज्वैलरी	36.3%	33.5%	29.6%	67.7%
केमिकल्स	9.5%	7.3%	31.6%	44.5%
रिटेलिंग	9.2%	15.6%	10.3%	20.7%

टर्नअराउंड इन सेक्टरों की हालत 1 साल में पूरी तरह बदल गई

सेक्टर	2024	2025	2024	2025
एग्रीकल्चर	1.0%	7.6%	-31%	68.8%
क्रूड ऑयल	-2.8%	4.8%	-14.5%	53.5%
ऑटोमोबाइल	5.8%	19.3%	-16.4%	19%
मीडिया, एंटर.	2.2%	3.8%	-18.8%	10.3%

स्टेबल इन सेक्टरों की स्थिति पहले से मजबूत या स्थिर

सेक्टर	2024	2025	2024	2025
फाइनेंस	19%	16.5%	18%	20%
हॉस्पिटलिटी	7.5%	9.5%	23.7%	19.5%
बैंक	11%	3.2%	19.7%	10.7%
इंश्योरेंस	-0.7%	15%	15%	11%

मुश्किल इन सेक्टरों की स्थिति पहले से भी कमजोर हुई

सेक्टर	2024	2025	2024	2025
टेक्सटाइल	6.6%	-1.0%	-57.7%	-21.7%
हेल्थकेयर	13.5%	5.8%	35.2%	-13%
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स	13%	8.6%	17%	-3%
एफएमसीजी	11.4%	9.7%	10.5%	1.3%

मार्केट • सुप्रीम कोर्ट में ट्रम्प टैरिफ रद्द होने से बैंकिंग, फार्मा शेयर चढ़े

बाजार में रिकवरी, सेंसेक्स फिर 83,000 पार, आईटी इंडेक्स इस साल 15% टूटे

भास्कर न्यूज | मुंबई

सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ रद्द होने से शेयर बाजार का माहौल सुधर गया। बैंकिंग, पावर, फार्मा शेयरों में खरीदारी बढ़ी। इसके चलते सेंसेक्स 480 अंक चढ़कर 83,295 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 142 अंकों की तेजी के साथ 25,713 पर पहुंच गया। निफ्टी बैंक और सरकारी बैंकों के इंडेक्स चढ़े, जबकि आईटी सेक्टर दबाव में रहा। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, 'अब निवेशक ट्रम्प की संशोधित रणनीति और अन्य देशों के साथ संभावित नए टैरिफ की सीमा को लेकर अधिक स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। कमजोर अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड की घटती यील्ड वैश्विक बाजार में निकट अवधि में सतर्कता का माहौल बना सकती हैं।'

...पर बाजार का सेंटीमेंट अब भी कमजोर, 54% शेयर गिरे

बीएसई पर शेयर ट्रेडिंग	4,497
गिरावटः	2,435
तेजीः	1,894
स्थिरताः	168
52 हफ्तों का निचला स्तर	238
52 हफ्तों का ऊंचा स्तर	124

आईडीएफसी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 16% तक टूटे

आईडीएफसी बैंक के शेयर 16% और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर 5.3% गिर गए। इन शेयरों में बिकवाली 590 करोड़ के कथित फ्रॉड के बाद बढ़ा, जो हरियाणा सरकार के खातों से संबंधित है।

इन दो घटनाओं ने सीमित रखी बाजार की तेजी...

जेफरीज ने आईटी कंपनियों की कमाई का अनुमान घटाया

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इन्फोसिस, टीसीएस समेत सभी भारतीय आईटी कंपनियों की रेटिंग और कमाई का अनुमान 4% तक घटा दिया है। इससे आईटी शेयरों में बिकवाली बढ़ी। 2026 में अब तक आईटी इंडेक्स 15% गिर चुका है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में नए सिरे से अनिश्चितता बढ़ी

मूडीज एनालिटिक्स के गौरव गांगूली ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रम्प के टैरिफ रद्द होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई अनिश्चितता बढ़ी है। अमेरिका वैकल्पिक शुल्क बढ़ा सकता है और कंपनियां भुगतान वापसी विवाद में पड़ सकती हैं।

1991 की जर्जर बुगाटी का मेकओवर, 25 करोड़ में बिकेगी

लंदन| 1991 की मशहूर हाइपर कार बुगाटी ईबी110 की कहानी फिल्मी है। 2005 में कुवैत के शाही परिवार ने इसे खरीदकर गैरेज में खड़ा कर दिया, जहां 17 साल तक धूल फांकती रही। 2023 में जर्जर हालत में बाहर निकली। इंजन जाम था और पुर्जे गल चुके थे। लॉन्चिंग के वक्त इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए थी। लक्जमबर्ग के विशेषज्ञों ने इसे नया जीवन दिया। एक-एक पुर्जे को मूल स्पेसिफिकेशन के साथ नया जैसा बनाया। अब यह सड़क पर उतरने के लिए तैयार और बिक्री के लिए उपलब्ध है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी कीमत 25 करोड़ रुपए से ऊपर जा सकती है।

बिजनेस ब्रीफ

इनविटः 5,565 करोड़ का मुनाफा निवेशकों में बांटा

मुंबई | लिस्टेड इनविट सेक्टर ने दिसंबर तिमाही में निवेशकों को 5,565 करोड़ रुपए का मुनाफा बांटा है। भारत इनविट एसोसिएशन (बीआईओ) के आंकड़ों के मुताबिक इस सेक्टर में अब तक कुल 83,770 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है। वर्तमान में 26 लिस्टेड इनविट सक्रिय हैं, जो सड़क, बिजली ट्रांसमिशन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हैं। इस सेक्टर का कुल एयूएम 7 लाख करोड़ पार हो गया है।

पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विस नियमों की समीक्षा होगी

मुंबई | बाजार नियामक सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विस (पीएमएस) रेगुलेशंस की व्यापक समीक्षा करने की योजना बना रहा है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नियम समय के साथ प्रभावी, लचीले और बाजार के बदलते हालात के अनुरूप बने रहें। इससे संकेत मिलता है कि इस सेक्टर में निगरानी और गवर्नेंस मानक और कड़े हो सकते हैं।

मौका • 3,100 करोड़ का इश्यू 25 को बंद होगा

क्लीनमैक्स आईपीओः पहले ही दिन क्यूआईबी हिस्सा पूरा भरा

भास्कर न्यूज | मुंबई

अक्षय ऊर्जा कंपनी क्लीनमैक्स एनर्जी सॉल्युशंस के आईपीओ को पहले ही दिन संस्थागत निवेशकों का जोरदार समर्थन मिला। 3,100 करोड़ रुपए का यह पब्लिक इश्यू सोमवार को खुला। कुछ ही घंटों में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) का रिजर्व हिस्सा पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। इसे बाजार में भरोसे का संकेत माना जा रहा है। यह आईपीओ 25 फरवरी को बंद होगा। इसमें 1,200 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 1,900 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है। प्राइस बैंड 1,000-1,053 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है।

उचित वैल्युएशन, मजबूत प्रबंधन और कमर्शियल इंडस्ट्रियल रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर में क्लीनमैक्स की अग्रणी स्थिति को निवेशकों के तगड़े समर्थन की वजह माना जा रहा है। इसी महीने ₹1,500 करोड़ के प्री-आईपीओ निवेश में टेमासेक और बेन कैपिटल जैसे बड़े निवेशकों की भागीदारी कंपनी पर भरोसे को पुख्ता करती है। एंकर निवेशकों से कंपनी को पहले ही ₹921 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है। नोमुरा एसेट मैनेजमेंट, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इनमें शामिल है।

गूगल, अमेजन, एपल जैसी कंपनियों को सप्लाई

वित्तीय प्रदर्शन भी मजबूत रहा है। पिछले तीन साल कंपनी का एबिटा (कामकाजी लाभ) 58% कम्पाउंडेड रेट से बढ़ा है। कुल अनुबंधित क्षमता का 43% हिस्सा गूगल, अमेजन और एपल जैसी कंपनियों से जुड़ा है। क्लीनमैक्स एनर्जी सॉल्युशंस कर्नाटक और गुजरात में प्रमुख खिलाड़ी है। कई बड़ी कंपनियों को ग्रीन एनर्जी सप्लाई करती है। कंपनी के संस्थापक व प्रबंध निदेशक कुलदीप जैन के नेतृत्व में कंपनी ने अच्छा खासा विस्तार किया है।

बैंकों के मर्जर का रोडमैप नहीं: सीतारमन

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

केंद्र के पास फिलहाल सरकारी बैंकों को आपस में मिलाने (मर्जर) की कोई रूपरेखा नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को कहा कि सरकार ने इस संबंध में कोई योजना नहीं तैयार की है। बैंक मर्जर बजट से पहले या बाद में चर्चा का विषय नहीं रहा। उन्होंने बताया कि बजट 2026-27 में प्रस्तावित 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति' पूरे बैंकिंग सेक्टर की समीक्षा करेगी। यह समिति बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के उपाय सुझाएगी। इस बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंकों के पास 4-5 साल तक लोन की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त कैश है।

बुलियन • टैरिफ और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर

दो दिन में चांदी 13% महंगी, 2.64 लाख रुपए प्रति किलो पहुंचे दाम, सोना भी 3 हफ्तों के ऊंचे स्तर पर

भास्कर न्यूज | मुंबई

बड़े देशों के आपसी तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच जंग की नौबत ने सोने-चांदी की मांग फिर बढ़ा दी है। आईबीजेए के आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू सराफा बाजार में सोमवार को चांदी 13,761 रुपए महंगी होकर 2,64,075 रुपए प्रति किलो हो गई। शुक्रवार को चांदी 2,50,314 रुपए प्रति किलो थी। इससे एक दिन पहले गुरुवार को चांदी 2,34,380 रुपए थी। यानी दो कारोबारी सत्र में ही चांदी के दाम 29,695 रुपए (13%) बढ़ गए हैं। हालांकि 29 जनवरी को चांदी 3,79,988 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर थी। अब भी इस रिकॉर्ड स्तर से 1,15,913 रुपए (30%) नीचे है।

वहीं, 24 कैरेट सोना 3,154 रुपए महंगा होकर 1,58,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। 29 जनवरी के रिकॉर्ड स्तर 1,75,340 रुपए प्रति 10 ग्राम से फिलहाल 10% नीचे है।

टैरिफ की अनिश्चितता के चलते तेजी बनी रहेगी

कोटक सिक्युरिटीज की एवीपी कमोडिटी रिसर्च कायनात चैनवाला ने कहा कि व्यापारिक तनाव और भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से कॉमेक्स पर सोना 1% बढ़कर 5,198 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। सोने में यह तीन हफ्तों का सबसे ऊंचा स्तर है। बुलियन की कीमतों में तेजी रह सकती है, क्योंकि टैरिफ पर हालिया घटनाक्रम ने वैश्विक बाजारों में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है।

संकट • इंडस्ट्री की फैसला वापस लेने की मांग

भारतीय निर्यातकों को दी जाने वाली छूट अब आधी

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने सोमवार को निर्यातकों को मिलने वाली शुल्कों और टैक्स छूट की दरें तत्काल प्रभाव से 50% घटा दी हैं। इस योजना के तहत उत्पादों पर 0.3% से लेकर 3.9% तक का रिफंड मिलता था। उदाहरण के लिए कच्चे कपास के निर्यात पर जहां पहले प्रति किलो 1.60 रुपए का रिफंड मिलता था, वह अब घटकर 80 पैसे रह जाएगा। निर्यातकों का मानना है कि रिफंड आधा होने से विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय माल महंगा हो जाएगा। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष एससी रल्हन ने कहा, 'यह कटौती ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में आई है जब भारतीय निर्यात पहले से ही कमजोर मांग और वैश्विक अनिश्चितता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। हम सरकार से इस फैसले को वापस लेने का अनुरोध करते हैं।' बता दें कि जब कोई निर्यातक माल बनाता है, तो वह ईंधन पर टैक्स, बिजली शुल्क और मंडी शुल्क जैसे कई स्थानीय टैक्स चुकाता है। माल विदेश भेजने पर सरकार आरओडीटीईपी योजना के साथ इन करों को रिफंड कर देती है ताकि भारतीय सामान दुनिया में सस्ता रहे।

भारतीय कंपनियां विदेशी ऑर्डर गंवा सकती हैं

थिंक टैंक जीटीआरआई का मानना है कि यह कटौती गलत समय पर की गई है। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश कम लागत पर माल बेच रहे हैं। ऐसे में भारतीय निर्यातकों के लिए 1-2% की बढ़त भी विदेशी ऑर्डर गंवाने का कारण बन सकती है। लागत बढ़ने से निर्यातकों का मार्जिन (मुनाफा) सिकुड़ जाएगा, जिससे छोटे व्यापारी ग्लोबल मार्केट से बाहर हो सकते हैं।

बिजनेस एंकर फिलिप नवरतिल के नेतृत्व में नेस्ले ने शुरू किया 'ऑपरेशन क्लीन-अप', फोकस मुनाफे वाले मुख्य सेगमेंट पर

आइसक्रीम से वैश्विक कंपनियों का मोहभंग, नेस्ले ने भी समेटा ये कारोबार

बिजनेस संवाददाता | लंदन/ज्यूरिख

दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय कंपनी नेस्ले आइसक्रीम के कारोबार को 'ठंडे बस्ते' में डालने जा रही है। दरअसल वैश्विक एफएमसीजी सेक्टर में कुछ समय से एक ट्रेंड देखा जा रहा है। दिग्गज कंपनियों का आइसक्रीम बिजनेस से मोहभंग हो रहा है। नेस्ले ने पुष्टि की है कि वह अपने शेष आइसक्रीम पोर्टफोलियो को संयुक्त उद्यम साझेदार 'फ्रोनेरी' को बेचने के लिए बातचीत कर रही है। इस सौदे में हागेन-डाज और ड्रमस्टिक जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 1.3 बिलियन डॉलर (करीब 11,800 करोड़ रुपए) आंकी गई है।

... आखिर आइसक्रीम बिजनेस से किनारा क्यों

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि जटिल कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स, बिजली की भारी खपत और सीजन पर निर्भरता ने आइसक्रीम को एक 'मुश्किल बिजनेस' बना दिया है।

कम मार्जिनः आइसक्रीम की बिक्री मौसम पर निर्भर है; गर्मी में मांग चरम पर होती है। सर्दियों और मानसून में बिक्री सुस्त रहती है। वास्तविक मुनाफा कम बचता है। ब्यूटी और पर्सनल केयर के 20-25% मार्जिन की तुलना में आइसक्रीम का 10-14% मार्जिन निवेशकों के लिए कम आकर्षक है।

शुगर टैक्स और अनहेल्दी प्रोडक्ट पर सख्ती लोग अब चीनी और कैलोरी के सेवन को लेकर अधिक सतर्क हो रहे हैं। कई देशों में बढ़ते 'शुगर टैक्स' और 'अनहेल्दी' उत्पादों के प्रति सख्त नियमों के कारण कंपनियां अब प्लांट-बेस्ड और पोषण-आधारित उत्पादों की ओर रुख कर रही हैं।

कॉर्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य बड़ी चुनौती

उत्पादन से लेकर ग्राहक तक पहुंचने तक आइसक्रीम माइनस 18सी या उससे कम तापमान की जरूरत होती है। विशेष फ्रीजर ट्रकों, गोदामों के रखरखाव की लागत अन्य प्रोडक्ट्स से अधिक है। बढ़ते बिजली खर्च और कार्बन उत्सर्जन कम करने के वैश्विक दबाव ने इस सप्लाई चेन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

नेस्ले के नए सीईओ फिलिप नवरतिल ने पद संभालते ही कंपनी के बिखरे हुए साम्राज्य को समेटने का फैसला किया है। नवरतिल के मुताबिक, आइसक्रीम ब्रांड अब कंपनी के मुख्य बिजनेस के लिए एक भटकाव बन गए थे। कंपनी अब अपना पूरा ध्यान उन 4 सेगमेंट पर लगाएगी, जहां उसका दबदबा सबसे ज्यादा है- कॉफी, पेट केयर, न्यूट्रिशन और स्नैक्स। नवरतिल ने स्पष्ट किया, 'हम इन ब्रांड्स को उस गति से आगे नहीं बढ़ा सकते, जिस तरह फ्रोनेरी जैसी विशेषज्ञ कंपनियां बढ़ा सकती हैं।' नेस्ले जैसा दिग्गज अब लागत कम करने के लिए एआई और ऑटोमेशन का सहारा ले रहा है और दुनियाभर में 16,000 नौकरियां घटाने की योजना बना रहा है। ऐसे में कंपनी उन सेक्टर में पूंजी लगाना चाहती है जहां मार्जिन अधिक और स्थिर है।

नेस्ले अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो जमी हुई मिठास से दूरी बना रही है। यह पूरी दुनिया में एफएमसीजी और डेयरी दिग्गजों के बीच एक 'स्ट्रक्चरल शिफ्ट' है। यूनिलीवर ने बीते दिसंबर में प्रसिद्ध आइसक्रीम डिवीजन मैग्नम को अलग कर दिया। अमेरिकी दिग्गज कंपनी जनरल मिल्स ने अपनी आइसक्रीम यूनिट को पहले ही लैक्टालिस को बेच चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी निर्यातक कंपनी फोंटेरा भी अपने ग्लोबल कंज्यूमर और आइसक्रीम बिजनेस को बेचने की प्रक्रिया में है। इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी लैक्टालिस ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की भारी-भरकम बोली लगाई है।

भारत में एपल ने पांच साल में 2.5 लाख नौकरियां पैदा कीं, 70 फीसदी महिलाएं

नई दिल्ली | एपल 5 साल में भारत में ब्लू-कॉलर नौकरियां पैदा करने वाले सबसे बड़े केंद्रों में से एक रही है। 2021 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरू हुई पीएलआई योजना के बाद से कंपनी ने 2.5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। यह योजना इस साल मार्च में खत्म होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपे गए आंकड़ों के मुताबिक, इन कर्मचारियों में 70% से अधिक महिलाएं हैं। इनमें से अधिकांश की उम्र 19-24 वर्ष है। सरकार ने 5 वर्षों में सभी पात्र प्रतिभागियों के लिए कुल 2 लाख नई डायरेक्ट नौकरियों का लक्ष्य रखा था।

प्रेरणा

हर कोशिश कामयाब नहीं होती, लेकिन हर कोशिश जरूरी होती है। -थॉमस एडिसन

संपादकीय

आर्थिक असमानता बढ़ने के कारणों को समझना होगा

भारत की वर्तमान विकास-दिशा को अर्थशास्त्री लीप फ्रॉग अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बगैर औद्योगिक विकास किए यानी कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को निकाले बिना सेवा-क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ा दी गई है। लिहाजा एक तरफ उच्च वेतन वाला इंजीनियर और कम वेतन वाला डिलीवरी बॉय या कैब ड्राइवर है और दूसरी ओर डिजिटल डिवाइड का शिकार बेहद गरीब, अकुशल खेतिहर मजदूर। बजट में भी हाई-टेक ग्रोथ पर ही सरकार का जोर रहा है, जबकि भारत के आम आदमी का घर चीन-निर्मित सामानों से भरा है। इससे गरीब-अमीर की खाई बढ़ी है। नोबेल विजेता लेविस के विकास मॉडल को 70 साल पहले अमेरिका और यूरोप और फिर 1980 के बाद चीन ने अपनाया और सफल रहे। यह मॉडल था- करोड़ों श्रमिकों को बेहतर आय के लिए कृषि से मैन्युफैक्चरिंग और फिर सेवा क्षेत्र में लाना। इसकी शर्त थी कृषि का मशीनीकरण करके उसे लाभप्रद बनाना और उसमें से बाहर हुए युवाओं को स्किल देकर मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर पगार पर लाना। फिर औद्योगिक श्रमिकों की अगली पीढ़ी को बेहतर तकनीकी शिक्षा से लैस कर टेक और सेवा क्षेत्र में और बेहतर वेतन पर ले जाना। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में सरकारों ने सेवा क्षेत्र को व्यापक विस्तार दिया, जिससे उद्योग पीछे छूट गया। लीप फ्रॉग इकोनॉमी में आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

अपने काम से प्रेम करिए तो कर्म बोझ नहीं लगेगा

आजकल ट्रांसफरेबल स्किल्स का जमाना है। इसे सीधी भाषा में कहें तो किसी एक काम में दूसरे काम के कौशल को उतारना। जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, समय प्रबंधन, डेटा विश्लेषण। एक ही काम में इन सबको जोड़ना पड़ेगा। यह प्रबंधन के ढंग हैं। अब इसी में अगर अध्यात्म का सहारा लें तो ऋषि-मुनियों ने शास्त्रों में एक स्किल और बताई है, और वो है प्रेम। ये हर जगह काम आएगी। काकभुशुंडि जी ने जब गरुड़ जी को कथा सुनानी शुरू की तो तुलसीदास जी ने लिखा- प्रथमहिं अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेसि बखानी। भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा और फिर आगे कथा बढ़ाई। यह बात शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं। कथा में बोलते समय उन्होंने प्रेम उतारा। वक्तव्य में प्रेम हो तो मिठास, अपनापन, वाणी की गरिमा अपने आप आ जाती है। जो भी काम करें, प्रेम से करें और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने काम से प्रेम करिए तो आपका कर्म आपको बोझ नहीं लगेगा।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

दूरदृष्टि • सोना खरीदने वाले विश्वास बनाए रखें

सोने के दामों में तेजी से आई चमक का रहस्य क्या है?

गोल्ड रश

रुचिर शर्मा

ग्लोबल इन्वेस्टर व लेखक

breakoutnations@gmail.com

वर्षों तक उछाल के बाद सोने की कीमतें अब ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं, जहां अब 'स्टोरीटेलिंग' उसकी दिशा तय कर रही है। सोने के दाम उन बुनियादी शक्तियों से मुक्त हो चुके हैं, जो लंबे समय तक उसके उतार-चढ़ाव के नियम तय करती रही थीं। अब वह वैश्विक जोखिम और अनिश्चितता की कहानियों के सहारे ऊपर बढ़ रहा है। विश्लेषकों को तो यह दौर 1970 के दशक के 'गोल्ड रश' जैसा लगने लगा है।

सोना लंबे समय से सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता रहा है, क्योंकि उसकी कीमतें सदियों तक मुद्रास्फीति की दर के साथ कदम मिलाती रही हैं। हालांकि बीच-बीच में उसमें भी गिरावट और उछाल आते रहे हैं। उछाल आम तौर पर उस कालखंड में आते थे, जब वास्तविक ब्याज दरें घटती थीं। जब बचत खातों या बॉन्ड्स में रखे धन पर रिटर्न कम होता था तो लोग अपनी संपत्ति सोने में स्थानांतरित करने लगते थे।

यह पैटर्न 2023 में बदलना शुरू हुआ। ब्याज दरें अतीत की तुलना में ऊंची थीं और बढ़ रही थीं, फिर भी सोने की कीमतें चढ़ने लगीं। इसका प्रमुख कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीद में वृद्धि थी, जो अपनी होल्डिंग्स को डॉलर से हटाना चाहते थे। यह वही डॉलर है, जिसे अमेरिका ने रूस पर लगाए प्रतिबंधों में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। तब से सोने की कीमतें आसमान छू चुकी हैं। किंतु जिसे मैंने कभी विदेशी केंद्रीय बैंकों के नेतृत्व में डॉलर-विरोधी क्रांति कहा था, वह अब इसकी व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

पिछले एक वर्ष में केंद्रीय बैंकों की खरीद की गति धीमी पड़ गई है। ऊंची कीमतों के चलते उपभोक्ताओं की हिचकिचाहट से गहनों की मांग में गिरावट आई है। इसके विपरीत, भारत से लेकर चीन और अमेरिका से लेकर यूके तक सभी प्रमुख बाजारों में निवेशकों की मांग विस्फोटक रूप से बढ़ी है। पिछले वर्ष वैश्विक स्तर पर सोने की कुल खरीद में निवेशकों की हिस्सेदारी दोगुनी होकर 35% तक पहुंच गई। सोने के सभी निवेश योग्य रूपों- बिस्किट और सिक्कों से लेकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स तक- में निवेश का तेज प्रवाह नजर आने लगा।

विशेषकर भारतीयों को सोने के प्रति विशेष लगाव के लिए जाना जाता है। आकलनों के अनुसार भारतीय घरों में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है : 28,000 टन, जो कुल वैश्विक भंडार का 14% है। किंतु पिछले वर्ष भारतीयों ने भी सोने के आभूषणों पर कम और सोने से जुड़े निवेश उत्पादों पर अधिक व्यय किया।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि भारत में गोल्ड ईटीएफ का असाधारण उछाल नए उत्पाद प्रस्तावों की एक श्रृंखला को प्रेरित कर रहा है, जो इस वर्ष भी इस तेजी को बनाए रखने में सहायक हो सकता है।

संक्षेप में, सोना अब मुख्यतः वित्तीय मांग से संचालित हो रहा है और यह बदलाव उसके मूल्यांकन की पारम्परिक समझ को उलट रहा है। सोने की कीमत को समझाने के लिए लंबे समय से प्रयुक्त मॉडल- जिनमें वास्तविक बॉन्ड यील्ड्स और मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं शामिल थीं- अब निष्प्रभावी हो चुके हैं।

सोने में तेजी के पक्षधर यह तर्क दे रहे हैं कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य अतीत की गोल्ड सुपर-साइकिल्स की पृष्ठभूमि जैसा है- यानी 2000 के दशक और विशेष रूप से 1970 के दशक जैसे लंबे और प्रबल तेजी के दौर। किंतु आज की मुद्रास्फीति जिमी कार्टर के दौर के डबल-डिजिट स्तरों के आसपास भी नहीं है। और यह तर्क देना कठिन है कि ट्रम्प, टैरिफ और यूक्रेन जैसी अनिश्चितताएं आज उतनी ही अधिक विचलित करने वाली हैं, जितनी उस समय तेल प्रतिबंध, वियतनाम युद्ध और ईरान बंधक संकट थे।

एक अन्य तर्क यह है कि सोना डॉलर के अवमूल्यन

सोने के प्रबल समर्थक कहते हैं कि इस पीली धातु में अभी और ऊपर जाने की पर्याप्त गुंजाइश है। पिछले दस वर्षों में यह तीन गुना से अधिक बढ़ चुका है। किंतु 1970 के दशक की बारह गुना वृद्धि की तुलना में यह बहुत आवक नहीं है।

से बचाव के साधन के रूप में फल-फूल रहा है। किंतु यदि ऐसा है तो डॉलर के अन्य विकल्प जैसे बिटकॉइन क्यों गिरावट में हैं और अमेरिकी शेयरों तथा बॉन्ड जैसे अन्य डॉलर-आधारित एसेट्स क्यों टिके हुए हैं?

यही कारण है कि सोने के प्रबल समर्थक कहते हैं कि इस पीली धातु में अभी और ऊपर जाने की पर्याप्त गुंजाइश है। और वे सही भी हो सकते हैं। पिछले दस वर्षों में यह तीन गुना से अधिक बढ़ चुका है। किंतु 1970 के दशक की बारह गुना वृद्धि की तुलना में यह बहुत अधिक नहीं है। उस समय तो मात्र दो महीनों में सोने की कीमतें दोगुनी हो गई थीं।

मैं कई वर्षों से सोने के प्रति सकारात्मक रुख रखता रहा हूं, लेकिन अब मैं अधिक तटस्थ हूं। अनियमित कथानकों से संचालित होने वाले बाजार में यह जान पाना कठिन होता है कि कौन-सा नैरेटिव वास्तविक है और टिकेगा। यदि आप और सोना खरीदना चाहते हैं, तो आपको बस विश्वास बनाए रखना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मुद्दा • सांसद निधि के औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं

सांसदों को अपने फंड का बेहतर उपयोग सीखना होगा

विकास

संजय कुमार

प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार

sanjay@csds.in

हाल में कुछ सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लैड निधि के उपयोग-दुरुपयोग का मामला सामने आया है। संसद के दोनों सदनों में भी सांसद निधि के औचित्य पर सवाल उठाए गए। पहली बार यह मुद्दा तब उठा था, जब राजस्थान में झुंझुनूं के सांसद ने 25 लाख रुपए, चूरू सांसद ने 50 लाख रुपए और भरतपुर सांसद ने 45 लाख रुपए अपनी-अपनी सांसद निधि से हरियाणा के कैथल जिले में विकास कार्यों के लिए आवंटित करने की सिफारिश की। मामला तब फिर गरमाया, जब जम्मू-कश्मीर से भाजपा के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने भी अपने राज्य के बजाय यूपी के लिए बड़ी राशि आवंटित कर दी।

जब राजस्थान के कांग्रेस सांसदों ने अपने राज्य के बजाय हरियाणा में विकास कार्यों के लिए राशि दी तो भाजपा ने आरोप लगाया कि यह एमपी लैड के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। इस योजना का मकसद ही सांसद के अपने क्षेत्र में विकास जरूरतों को पूरा करना है। फिर राज्य के बाहर पैसा खर्च करने का क्या औचित्य? भाजपा ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि कैथल रणदीप सुरजेवाला के पुत्र का विधानसभा क्षेत्र है। उधर खटाना द्वारा भी यूपी में धनराशि के इस्तेमाल करने की पीडीपी प्रवक्ता ने आलोचना की।

झुंझुनूं सांसद बृजेन्द्र सिंह ओला ने कहा कि आवंटन एमपी लैड गाइडलाइन और सरकारी आदेशों के तहत ही किया गया है। नियमों के अनुसार 50 लाख रुपए तक अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के कार्यों में दिए जा सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में 1 करोड़ रुपए तक की अनुशंसा भी अनुमत है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भाजपा सांसद भी आपत्तिजनक उद्देश्यों के लिए एमपी लैड राशि इस्तेमाल कर चुके हैं। इधर खटाना ने कहा कि वे मनोनीत सांसद हैं तो नियमानुसार देश के किसी भी हिस्से में विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

यदि सांसदों ने अपने राज्य के बाहर विकास के लिए राशि आवंटित की है तो उन्होंने ऐसा नियमों के तहत ही किया होगा। लेकिन चूंकि यह धारणा है कि सांसद अपनी निधि का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये घटनाएं हमें इस बड़े सवाल पर चर्चा का अवसर देती हैं कि आखिर एमपी लैड राशि को बरकरार रखने का औचित्य क्या है? इस पर दो समानांतर तर्क सामने आते हैं। पहला, यह निधि खत्म होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में सांसद विकास कार्यों के लिए पूरी राशि का उपयोग नहीं कर पाते। इसका विरोधी तर्क यह है कि सांसदों को विकास कार्यों के लिए ऐसी निधि की आवश्यकता है, इसलिए यह बरकरार रहनी चाहिए।

एमपी लैड योजना में हर सांसद कुछेक अपवादों को छोड़ प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों की सिफारिश कर सकता है। 17वीं लोकसभा के दौरान लगभग 4837.87 करोड़ रुपए एमपी लैड के लिए आवंटित किए गए थे, जिनमें से कथित तौर पर 3639.53 करोड़ रुपए खर्च हुए। कुल 96211 कार्यों की सिफारिश की गई, जिनमें से 41143 कार्य पूरे हुए।

हालांकि यह आंकड़ा बताता है कि लगभग आधे कार्य पूरे नहीं हो सके, लेकिन कुल आवंटित बजट का लगभग 75% विकास कार्यों पर खर्च हो गया। वर्तमान लोकसभा में अब तक 5486 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं, जिनमें से 1453.69 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और कई विकास कार्य अभी प्रगति पर हैं।

यह सही है कि एमपी लैड पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार 17वीं लोकसभा (2019-2024) के दौरान कुल आवंटित बजट का 16.24% हिस्सा खर्च नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा मुख्यत: कोविड के कारण हुआ, जब विकास परियोजनाएं स्थगित कर दी गई थीं।

हो सकता है कि कुछ सांसद अपनी निधि का पूरा उपयोग नहीं कर पाए हों, लेकिन इसे व्यापक चलन नहीं कहा जा सकता। ऐसे कई उल्लेखनीय उदाहरण भी हमारे सामने हैं, जहां सांसदों ने अपने पूरे आवंटित कोश का इस्तेमाल किया।

लेकिन पिछली कुछ लोकसभाओं के दौरान एमपी लैड निधि का इस्तेमाल अपेक्षाकृत बेहतर हुआ है।

16वीं लोकसभा (2014-2019) में केवल 8.7% निधि खर्च नहीं हो पाई, 15वीं (2009-2014) में यह आंकड़ा 3.47% था। 14वीं (2004-2009) में तो यह और भी कम मात्र 0.99% ही रहा था। हो सकता है कुछ सांसद अपनी निधि का पूरा उपयोग नहीं कर पाए हों, लेकिन इसे व्यापक चलन नहीं कहा जा सकता। बेहतर यह होगा कि छोटी कार्यशालाओं और विशेषज्ञों के जरिए सांसदों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाए कि वे विकास कार्यों में सांसद निधि का सबसे बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

अभियान

एआई कंपनियां चुनाव में करोड़ों रुपए लगाएंगी

थ्योडोर स्कलीफर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री अमेरिका में होने वाले संसद के मध्यावधि चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च करने वाली है। 2025 में एआई कंपनियों और उनके बड़े अधिकारियों ने चुनाव अभियानों और चुनाव समितियों को 750 करोड़ रुपए दिए थे। टेक कंपनी मेटा ने राज्य स्तर पर 590 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। अब मध्यावधि चुनावों के लिए डोनेशन जारी है।

चुनावी चंदे से ज्यादा फायदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी को होगा। रिपब्लिकन नेता इंडस्ट्री के बड़े समर्थक हैं। वे कठोर एआई नियमन के खिलाफ हैं। वैसे विश्लेषण से पता लगा है कि टेक इंडस्ट्री से लंबे समय से रिश्ते रखने वाले कुछ डेमोक्रेटिक राजनेताओं को भी एआई कंपनियों से काफी कैश मिलेगा। रिपब्लिकन्स के दो सबसे बड़े डोनर ओपन एआई के को-फाउंडर ग्रेग ब्रॉकमैन और उनकी पत्नी एना हैं। दोनों ने 12 सितंबर 2025 तक 113-113 करोड़ रुपए दिए हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि एआई इंडस्ट्री और उसके सहयोगी इस वर्ष चुनावों में कितना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन चुनाव के लिए बहुत धन आने वाला है। एआई सुपर पीएसी लीडिंग द फ्यूचर का कहना है कि वर्ष की पहली तिमाही में उसे ब्रॉकमैन और वेंचर कैपिटल फर्म एंड्रीसन होरोविट्ज से 450 करोड़ रुपए मिलेंगे।

© The New York Times

टेक्नोलॉजी — फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए यूरोप में भारी खर्च कर रही हैं

सोशल मीडिया पर रोक के खिलाफ टेक कंपनियों की मुहिम, सांसदों की लॉबिंग पर 1615 करोड़ रुपए खर्च

विविएन वाल्ट

फेसबुक और गूगल सहित अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के सामने एक नई तरह की चुनौती आ रही है। कई देशों की सरकारें टीनएजर्स के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर रोक लगा रही हैं। वे एप्स को लत लगाने वाला और नुकसानदेह बता रही हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी कंपनियां ने जवाबी मुहिम छेड़ दी है। यूरोपियन यूनियन (ईयू) में अमेरिकी कंपनियों ने पिछले साल बड़े होर्डिंग लगाने, राजनेताओं को लुभाने और अपनी लॉबिंग लॉबी मजबूत करने पर भारी खर्च किया है।

दरअसल, यूरोपीय संसद में टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं। 720 सदस्यीय संसद में सोशल मीडिया पर बैन के विधेयकों को आसानी से रोका जा सकता है। बड़ी टेक कंपनियों ने ईयू के सांसदों की लॉबिंग पर पिछले वर्ष 1615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कॉरपोरेट यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी और लॉबी कंट्रोल संगठन के अनुसार 2021 से 2025 के बीच फैसलों को इंडस्ट्री के पक्ष में करने के लिए चली मुहिम में 55% से अधिक इजाफा हुआ है। सबसे अधिक खर्च फेसबुक की कंपनी मेटा ने किया है। इसके बाद गूगल है। इन कंपनियों के खिलाफ याचिका दायर करने वालों ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब को डिजिटल कैसिनो कहा है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों का आरोप है कि प्लेटफॉर्म के अनंत स्क्रॉलिंग जैसे फीचर युवा यूजरों को आदी बनाते हैं।

टेक कंपनियां मानती हैं कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में लागू होने वाले नए कानून से दुनिया भर में उनके कामकाज पर असर पड़ेगा। इसलिए यूरोपीय राजनेताओं को मनाने पर ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। वे प्रतिबंध के विकल्प के लिए तगड़ी मुहिम चला रही हैं। यूरोपीय सांसदों से चर्चा में मेटा ने टीन अकाउंट्स का प्रस्ताव दिया है। 2024 में पेश इन अकाउंट्स में 16 साल से कम आयु के यूजर्स के अकाउंट पर पैरेंट्स का नियंत्रण रहता है। कुछ कंपनियां ने 15, 16 साल से कम आयु के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी करने का प्रस्ताव दिया है।

यूरोपीय आयोग इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमत हो गया है। यूरोप के प्रारूप प्रस्ताव डिजिटल फेयरनेस एक्ट पर ब्रसेल्स में इस साल मतदान हो सकता है।

सांसदों को प्रभावित करने के लिए 890 लॉबिस्ट सक्रिय

ब्रसेल्स में 890 फुलटाइम लॉबिस्ट काम कर रहे हैं। यह यूरोपीय संसद के सदस्यों की संख्या से अधिक है। ये लॉबिस्ट सोशल मीडिया बैन के खिलाफ अभियान चलाने के साथ यूरोप के एआई कानून और डेटा प्राइवेसी नियमों को बेअसर करना चाहते हैं। टेक कंपनियां धुर दक्षिणपंथी सांसदों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। अकेले मेटा ने जुलाई 2024 और दिसंबर 2025 के बीच सांसदों के साथ 38 बैठकें की हैं।

रेलवे स्टेशनों पर होर्डिंग से लेकर बड़े-बड़े विज्ञापन तक छप रहे

वाशिंगटन के ट्रेड ग्रुप- कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ब्रसेल्स में रेलवे स्टेशनों पर होर्डिंग लगाए हैं। इनमें ईयू से सोशल मीडिया प्रतिबंधों को रद्द करने की अपील की गई है। विज्ञापनों में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक जोहान्स गुटेनबर्ग, रेडियो बनाने वाले गुग्लिमो मार्कोनी जैसे यूरोपियन आईकन दिखाए गए हैं। पिछले साल नवंबर में मेटा ने यूरोप के अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन दिया।

अमेरिका के आठ राज्यों सहित कई देशों में पहल

पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ने किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क का कहना है कि वे जल्द अपनी नीति की घोषणा करेंगे। अमेरिका के 8 राज्यों में भी किशोरों को सोशल मीडिया से अलग रखने के विधेयक पेश किए गए हैं।

© The New York Times

इस हफ्ते चर्चा में...

अमेरिका व चीन के बीच कारोबार में गिरावट आई

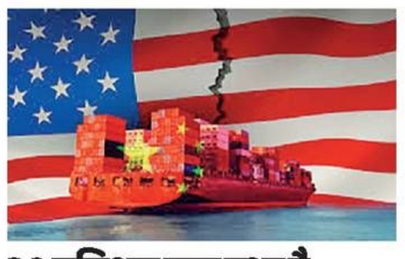

30 प्रतिशत कम हुआ है

अमेरिका में चीनी वस्तुओं का आयात 2025 में। अमेरिका के चीन को निर्यात की भी यही स्थिति है।

65934 करोड़ रुपए

चुकाएगी जर्मन केमिकल और दवा कंपनी बेयर। उसकी कीटनाशक दवा से कैंसर होने के दावे वाले मुकदमों को निपटाने के लिए।

एक करोड़ दस लाख

पर्यटक कम आए हैं अमेरिका में पिछले साल। यह 2024 के मुकाबले 6 प्रतिशत की गिरावट है।

इकोनॉमी

धीमी पड़ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार

बेन कैसलमैन

2025 के अंत में अमेरिका अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, कंज्यूमर खर्च और एआई इनवेस्टमेंट में उछाल की वजह से टैरिफ और सरकारी शटडाउन के बावजूद पिछले साल विकास दर पटरी पर बनी रही। वाणिज्य विभाग ने बताया कि पिछले साल के अंतिम तीन महीनों में जीडीपी 1.4 फीसदी की सालाना दर से बढ़ी। यह तीसरी तिमाही के 4.4 फीसदी से काफी कम है। लंबा शटडाउन इसका मुख्य कारण है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने चुनाव अभियान में वादा किया था कि चुने जाने के बाद वे पहले दिन महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन 2025 में महंगाई अधिक रही। दिसंबर में कंज्यूमर मूल्य 2.9 प्रतिशत बढ़ गया। वस्तुओं में व्यापार घाटा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब कम हो गए। 2025 में जीडीपी में 2.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जबकि 2024 में यह 2.3 प्रतिशत थी।

© The New York Times

बिजनेस — टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 के अन्य प्रावधानों के प्रयोग की तैयारी

ट्रम्प प्रशासन फिर भारी टैरिफ लगा सकता है

टॉनी रोम, एलन रेपेपोर्ट, एना स्वांसन

अमेरिकी सरकार ने रविवार को संकेत दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए कुछ भारी टैरिफ फिर से लागू कर सकती है। शनिवार को ट्रम्प ने 15 प्रतिशत का नया टैरिफ लगाकर जताया है कि कानूनी आघात से कारोबार के संबंध में उसके मनमाने रवैये पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर ने रविवार को एबीसी टीवी पर कहा कि राष्ट्रपति टैरिफ के लिए अभियान चलाते रहे हैं। यह नीति नहीं बदली है। ट्रम्प ने सभी देशों पर 15 प्रतिशत टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 के तहत लगाया है। ट्रम्प प्रशासन इसी कानून के एक अन्य प्रावधान (धारा 301) के मुताबिक अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं की जांच करने की योजना बना रहा है।

व्यापार समझौते कायम रहने का दावा

वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को सीएनएन पर कहा कि टैरिफ से इस साल होने वाली आय में बदलाव नहीं किया गया है। अमेरिका के साथ कारोबार करने वाले देशों ने उन्हें बताया है कि अमेरिका से किए व्यापार समझौते कायम रहेंगे। बेसेंट ने 15 फीसदी ग्लोबल टैरिफ को इस साल बाद में लागू होने वाले टैरिफ के लिए एक पुल करार दिया है।

ग्रीयर ने कहा कि वे कुछ बिंदुओं पर जांच शुरू करेंगे। इसका फोकस अधिक औद्योगिक क्षमता, जबरिया काम कराने, दवाइयों के मूल्यों, अमेरिकी टेक कंपनियों के खिलाफ भेदभाव, सीफूड, चावल और अन्य प्रोडक्ट पर रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया के अधिकतर देशों पर टैरिफ लग सकता है। ग्रीयर ने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो अपना मकसद हासिल करने के लिए व्यापार प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि वह धारा 301 के तहत चीन और ब्राजील की जांच जारी रखेगा। अपने पहले कार्यकाल में ट्रम्प ने चीन से आयात पर टैरिफ लगाने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल किया था।

एक तरफ व्हाइट हाउस ने बेफिक्री दिखाई है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका की व्यापार नीति में परिवर्तन को देखते हुए अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। © The New York Times

खुलासा — महारानी एंड्रयू को हमेशा बचाती रहीं

एपस्टीन कांड में फंसे एंड्रयू के खिलाफ किंग चार्ल्स का रवैया हमेशा सख्त रहा

सारा लायल

जेफ्री एपस्टीन सेक्स कांड में फंसे पूर्व प्रिंस एंड्रयू के प्रति ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का रुख नरम रहा है। लेकिन एंड्रयू के बड़े भाई किंग चार्ल्स का रवैया अपनी मां से एकदम अलग है। एपस्टीन से रिश्तों का खुलासा होने के बाद मार्च 2022 में एंड्रयू को शाही कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था। उनकी सैनिक उपाधियां छीन ली गई थीं। किंग चार्ल्स तृतीय ने हर नए खुलासे के बाद अपने भाई से अलग बर्ताव किया है। उस साल बाद में जब एलिजाबेथ की मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार में चार्ल्स ने उन्हें सैनिक यूनिफार्म पहनने से रोक दिया था।

कभी अच्छे नहीं रहे दोनों के रिश्ते

चार्ल्स और एंड्रयू के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इतिहासकार एंड्रयू लाउनी ने लिखा है कि, मिलिटरी सर्विस खत्म होने के बाद जब एंड्रयू को महारानी ने ब्रिटेन का विशेष व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया था, तब चार्ल्स ने इस नियुक्ति को रोकने की कोशिश की थी।

गुरुवार को जब पूर्व प्रिंस को सार्वजनिक पद पर गलत आचरण के संदेह में गिरफ्तार किया गया तब चार्ल्स ने कहा, मैंने गहरी चिंता के साथ एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के बारे में आई खबरों को जाना है। अधिकारियों को हमारा पूरा सहयोग और समर्थन है। © The New York Times

सहयोग के मोर्चे

मौजूदा दौर में दुनिया भर में भू-राजनीति के स्वरूप में जिस तेजी से उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं, उसमें सभी देशों के सामने अपने भविष्य और विकास की राह सुरक्षित करने की चुनौती दिख रही है। खासतौर पर जिन कारकों पर आने वाले वर्षों में विकास की दिशा निर्भर करेगी, उसके मद्देनजर अलग-अलग देशों के बीच साझेदारी के नए अध्याय तैयार हो रहे हैं, विकल्प की राह खोजी जा रही है। भारत और ब्राजील के बीच हुए समझौते को इसी की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से उन बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें सहयोग के क्षेत्र में विकल्प के नए रास्ते तैयार हों। आज दुनिया भर में यह चिंता सतह पर देखी जा रही है कि आने वाले वर्षों में विकास का आधार बनने वाले अहम कारकों को लेकर कैसे एक नई आपूर्ति शृंखला बनाई जाए। भारत-ब्राजील के बीच हुआ समझौता इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि इसके जरिए दोनों को अन्य मजबूत देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि इस समझौते में अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बीस अरब डालर से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे एक मजबूत आपूर्ति शृंखला बनाने की दिशा में काफी महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते में सबसे अहम सहमति दुर्लभ खनिजों और भू-धातुओं को लेकर बनी है, जो आने वाले वर्षों में समूची दुनिया में विकास के सबसे अहम कारक बनने वाले हैं। इससे तकनीक के क्षेत्र में आदान-प्रदान, नई संभावनाओं की खोज, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह जगजाहिर तथ्य है कि आज लीथियम और कोबाल्ट जैसे अन्य दुर्लभ खनिज तथा भू-धातु विकास के संचालक तत्त्व बन रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जिस तरह इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा क्षेत्र, आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण और रोबोटिक्स उत्पादन के क्षेत्र में सभी देश अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं और इस संबंध में ज्यादा बेहतर अवसरों की तलाश में हैं। ऐसे में दुर्लभ खनिजों की मांग में काफी तेजी आने की उम्मीद है।

फिलहाल वैश्विक स्तर पर दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण के सबसे बड़े हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। भारत-ब्राजील के बीच हुए समझौते का एक मुख्य उद्देश्य आधुनिक उद्योग और तकनीक के लिए आवश्यक सामग्री की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना है और साथ ही इस क्षेत्र के प्रमुख आपूर्तिकर्ता और खासतौर पर चीन पर निर्भरता को कम करना है। भारत के लिए यह समझौता इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि ब्राजील को चीन के बाद दुर्लभ खनिजों से समृद्ध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। ब्राजील के साथ नए करार के बाद भारत को इन खनिजों को सीधे हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को लेकर एक सहमति बनी है। इसका असर छोटे कारोबारियों पर भी पड़ेगा और उन्हें नई तकनीकों के साथ-साथ ब्राजील के बाजार और उसकी नीतियों के अनुकूल अपना रुख तय करने का मौका मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल क्षेत्र में विकास के अन्य अहम बिंदुओं पर भी सहयोग के नए आयाम खुले हैं। दोनों देशों के बीच साझेदारी ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका व्यापार समझौते में भारत के सामने अपने फायदे में शर्तें सामने रख रहा है। हालांकि यह ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुध्रुवीय विश्व में अगर कोई विकसित देश अपने हित में विकासशील देशों पर दबाव को औजार बनाता है, तो आज एक बेहतर कूटनीति विकल्प की राह तैयार कर सकती है।

उपेक्षा का सिलसिला

हरियाणा के रोहतक जिले में पिछले साल बास्केटबाल का खंभा गिरने से एक युवा राष्ट्रीय खिलाड़ी की मौत ने शासकीय लापरवाही और भ्रष्टाचार की कई परतें भी खोल दी थीं। तब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने इसकी हर पहलू से जांच करने और जरूरत के मुताबिक सुधार के कदम उठाने की बात कही थी। घटना के बाद एक जांच समिति भी गठित की गई थी, मगर हालत यह है कि अब तक उस समिति की विस्तृत रपट नहीं पेश की गई। यही वजह है कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने खिलाड़ी की मौत पर चिंता जताते हुए इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया है। गौरतलब है कि रोहतक के उपायुक्त की ओर से जो रपट भेजी गई, उसमें घटना के वास्तविक कारणों और सुरक्षा मानकों का ठोस ब्योरा तक नहीं है। इसमें केवल बास्केटबाल स्टेडियम बनाने के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने का जिक्र है। आयोग ने इसे संज्ञान में लिया है और अब पूरे मामले पर सरकार से रपट मांगी है।

यह दुखद है कि खेलों के लिए पर्याप्त राशि खर्च किए जाने पर भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिलता और खेल सुविधाओं में गुणवत्ता नहीं दिखती। बास्केटबाल मैदान में अगर खंभे में जंग लगी थी और वह कमजोर होने के कारण गिरने की स्थिति में था, तो वहां किसी खिलाड़ी को अभ्यास करने या खेलने से रोकना और खंभा तुरंत बदलना किसकी जिम्मेदारी थी? अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बार-बार की शिकायत के बावजूद उस खंभे की न मरम्मत की गई और न उसे हटाया गया। सच यह है कि खेल के मैदान में नियमित रखरखाव होता, तो अभ्यास के दौरान बास्केटबाल खिलाड़ी की जान नहीं जाती। आयोग ने साफ तौर कहा है कि यह संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही और उनके कर्तव्यों में चूक है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और चिंता का कारण बनने के बावजूद इस मसले पर राज्य सरकार की उदासीनता और अनदेखी एक अघोषित नीति है! वरना जांच रपट में देरी न करना और इस मसले पर जरूरी कदम उठाना उसकी नजर में प्राथमिक दायित्व होता।

तकनीक के दुरुपयोग का फैलता दायरा

देश में डिजिटल माध्यम से वित्तीय लेन-देन का चलन बढ़ा है और इसके साथ ही साइबर धोखाधड़ी का दायरा भी फैलता जा रहा है। नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा में सेंध लगाने के इस संकट से निपटना अब अत्यंत जरूरी हो गया है।

रवि शंकर

हाल के वर्षों में भारत ने विभिन्न सेवाओं के डिजिटलीकरण में खासी प्रगति की है। देश में नब्बे करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हो गए हैं, जिससे डिजिटल माध्यम से पैसे के लेन-देन और अन्य कार्यों को पूरा करने का चलन भी बढ़ा है। इसी की बदौलत भारत ने दुनिया के सबसे बड़े 'रियल-टाइम' भुगतान बाजार के रूप में खुद को परिवर्तित किया है। वर्ष 2017 और 2023 के बीच 'रिटेल डिजिटल भुगतान' में 50.8 फीसद की तेज वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 में यह देश की जीडीपी का 4.5 फीसद हिस्सा था और 2026 के अंत तक इसके बीस फीसद तक पहुंचने का अनुमान है। मगर डिजिटल तकनीक के तेजी से हो रहे प्रसार के साथ कई साइबर संबंधी समस्याएं भी सामने आई हैं। आज अक्सर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां लोग साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। भले ही डिजिटल समावेशन का सपना अब देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंच चुका है, लेकिन इस उपलब्धि के साथ कई तरह की चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं। तकनीक का दुरुपयोग सुरक्षा में सेंध लगा रहा है और इस तरह के अपराध पर लगाम लगाना सुरक्षा एजंसियों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 के बाद से देश में साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं में करीब चार सौ फीसद की वृद्धि हुई है। अब ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्र डिजिटल ठगी के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। कुछ शहरों में साइबर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण वहां इस तरह के अपराध तेजी से बढ़े हैं। ग्रामीण इलाकों में भी साइबर अपराध का बढ़ना कोई संयोग नहीं, बल्कि यह सामाजिक और तकनीकी बदलाव का नतीजा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने डिजिटल पहुंच तो बढ़ा दी है, लेकिन लोगों में डिजिटल समझ नहीं बढ़ी है। सट्टेबाजी और आनलाइन खेल ऐप, जो मनोरंजन के रूप में पेश किए जाते हैं, वे साइबर ठगी के आसान जरिया बन गए हैं। यही वजह है कि पिछले छह साल में आनलाइन धोखाधड़ी के कारण भारतीयों को 52 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। यह जानकारी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ताजा आंकड़ों से सामने आई है।

समन्वय केंद्र की रपट में कहा गया है कि वर्ष 2025 में देश के नागरिकों ने करीब 19,813 करोड़ रुपए साइबर धोखाधड़ी में गंवाए हैं। इस दौरान 21 लाख से ज्यादा शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज हुईं। इससे पहले वर्ष 2024 में 22,849 करोड़ रुपए का नुकसान और लगभग 19 लाख शिकायतें सामने आईं। आज जब ज्यादातर चीजें मोबाइल और इंटरनेट पर सुलभ हैं, वहीं साइबर अपराधी भी हर उस चूक का इंतजार करते हैं, जो आम लोग अनजाने में कर बैठते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि लोग खुद को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित और सतर्क बनाएं। समस्या इसलिए भी जटिल होती जा रही है कि साइबर अपराधी ठगी के लिए नए-नए तरीके अपनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी देश भर में बढ़ रहे डिजिटल अपराध से निपटने के लिए सरकार को उचित एवं प्रभावी कदम उठाने को कहा। शीर्ष अदालत के मुताबिक, डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों

और संबंधित अधिकारियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर ठगी के मामलों में पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक राहत मुहैया कराने की मांग भी उठ रही है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि आरबीआइ एक नया नियम बना सकता है, जिसके तहत साइबर ठगी के छोटे मामलों में पीड़ित को पच्चीस हजार रुपए की आर्थिक मदद मिल सकती है। मगर यह तभी संभव होगा, जब पीड़ित व्यक्ति समय पर बैंक को इस तरह की धोखाधड़ी की जानकारी देगा।

> सरकार ने साइबर ठगी को रोकने के लिए कानून जरूर बनाए हैं, लेकिन आज भी इनका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन, तथ्य जांच और वास्तविक समय में निगरानी जैसी प्रणालियां बहुत धीमी गति से काम करती हैं। जाहिर है, किसी एक एजंसी पर जिम्मेदारी डालने से साइबर अपराध पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। इसके लिए केंद्र-राज्य सरकारें, बैंकिंग-वित्तीय संस्थान, टेक कंपनियां और आम नागरिक, सभी को एकजुट होकर रणनीति के तहत काम करना होगा। दरअसल, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ डिजिटल धोखाधड़ी का दायरा भी बढ़ रहा है।

साइबर अपराध बढ़ने से आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालात ये हैं कि साइबर अपराध अब केवल तकनीकी चूक का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यक्तिगत गोपनीयता और समग्र डिजिटल व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। आज साइबर ठगी केवल ई-मेल या फोन काल तक सीमित नहीं रह गई है। 'एआइ वायस क्लोनिंग', 'डीपफेक वीडियो', नकली ऐप और सोशल मीडिया पर बनाए गए फर्जी प्रोफाइल के जरिए अपराधी आम लोगों पर मानसिक दबाव बनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। कई मामलों में जालसाज खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस अफसर, आयकर अधिकारी या किसी करीबी रिश्तेदार के रूप में पेश कर तत्काल भुगतान की मांग करते हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा अब महज पैसों के नुकसान से बचाने का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। एक रपट के मुताबिक, भारत में डिजिटल तरीके से वित्तीय लेन-देन अब बड़े पैमाने पर होने लगा है। इसलिए साइबर सुरक्षा अब सिर्फ तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि डिजिटल व्यवस्था में नागरिकों के भरोसे को कायम रखने के लिए भी जरूरी है।

सरकार ने साइबर ठगी को रोकने के लिए कानून जरूर बनाए हैं, लेकिन आज भी इनका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन, तथ्य जांच और वास्तविक समय में निगरानी जैसी प्रणालियां बहुत धीमी गति से काम करती हैं। जाहिर है, किसी एक एजंसी पर जिम्मेदारी डालने से साइबर अपराध पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। इसके लिए केंद्र-राज्य सरकारें, बैंकिंग-वित्तीय संस्थान, टेक कंपनियां और आम नागरिक, सभी को एकजुट होकर एक रणनीति के साथ काम करना होगा। इसमें दोराय नहीं कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ डिजिटल धोखाधड़ी का दायरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में संदिग्धों का पंजीकरण इस तरह के मामलों से निपटने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, लेकिन यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना और नागरिकों में सतर्कता एवं जागरूकता को प्रोत्साहित करना भी उतना ही अहम है। नीति निर्माताओं को नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा को केंद्र में रखना होगा।

आज भारत एक डिजिटल समाज बनने की ओर अग्रसर है, मगर अब भी बड़ी संख्या में लोग डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं। अगर साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो निकट भविष्य में इसके भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। यह विफलता हमारे समाज को नकदी-आधारित प्रणालियों की ओर फिर से रुख करने के लिए मजबूर कर सकती है। मगर हम नवाचार, संस्थागत सहयोग और नैतिक प्रारूप के सही संयोजन के साथ सुरक्षात्मक उपाय तलाशेंगे, तो न केवल देश में इस खतरे को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर भी मिसाल कायम कर सकते हैं। इसलिए तेजी से बदलते डिजिटल दौर में खुद को आगे रखने के लिए सरकार, प्रौद्योगिकी क्षेत्र और समाज के बीच एक समन्वित एवं सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही सतर्कता, डिजिटल अनुशासन और विशेषज्ञों की ओर से सुझाए गए व्यावहारिक उपायों के जरिए इस खतरे को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

बिखरना और संवरना

महेश परिमल

जिस तरह से जीवन के साथ मृत्यु का संबंध है, ठीक उसी तरह जीवन में टूटने, बिखरने, समेटने और संवरने का भी संबंध है। इंसान हमेशा जीवन से मृत्यु की ओर खिसकता रहता है, वैसे ही उसके जीवन में बार-बार टूटने की स्थिति आती है। जब इंसान टूटेगा, तो निश्चित तौर पर बिखरेगा भी। बिखरने के बाद उसे समेटना भी जरूरी है। जब ये तीनों क्रियाएं हो जाती हैं, उसके बाद जो कुछ भी होता है, वह संवरता है। हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें, तो पता चलेगा कि हालात बद से बदतर होते रहे। हम कई बार टूटे, बिखरे, फिर स्वयं को समेटा और आखिर स्तर पर पहुंचते-पहुंचते एक बार फिर संवरने लगे।

हर किसी के जीवन में ये चार चक्र आते ही हैं। टूटने से शुरू होकर यह क्रिया संवरने तक चलती है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार टूट गए, तो फिर यह क्रम समाप्त हो जाएगा। वास्तव में हम जीवन में जब भी टूटे हैं, तभी एक नया जीवन शुरू हुआ है। टूटने का आशय अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। इंसान जब भी टूटा है, तो समझना चाहिए कि वह फिर से संवरने के लिए टूटा है। इसलिए टूटने की इस क्रिया को कभी गलत नहीं समझना चाहिए। दरअसल, संवरने की सलाहियत हासिल करने की की पहली सीढ़ी है किन्हीं वजहों से टूटना। यानी जुड़ने के लिए होने वाला पहला उपक्रम। जो टूटा है, वह जुड़ेगा ही, बशर्ते जुड़ने का हौसला बना रहे। जुड़ता वही है, जो टूटता है।

इंसान जिंदगी भर जीने का ही उपक्रम करता रहता है। जीना यानी पल-पल सांस लेने की प्रक्रिया से गुजरते हुए जीवन संगीत में रम जाना। यही रमने में क्रिया जब सघन हो जाती है, तो इसे 'डूबना' कहते हैं। यहां डूबने से आशय अपने मनचाहे काम को पूरी तल्लीनता से करना भी है। हर किसी के लिए डूबना अलग-अलग हो सकता है। संगीत वाले जब डूबकर गाते या बजाते हैं, तो हर किसी के मुंह से वाह-वाह निकल आता है।

संगीत हो या कोई भी अन्य रचनात्मक क्षेत्र, 'डूबना' सार्थक होता है। सभी कहते हैं कि टूटे हुए साज की आवाज को हर कोई नहीं समझ सकता। इसी तरह टूटे हुए दिल की बात भी हर कोई नहीं समझ पाता है। इसे वही समझ सकता है, जो कभी टूटा हो। टूटने को नकारात्मक भाव से नहीं लेना चाहिए। यह आगे बढ़ने की पहली प्रक्रिया है। जीवन का ककहरा इसी टूटने से शुरू होता है। बाइबल में जीसस ने कहा है- मांगोगे, तभी पाओगे। पाने के लिए मांगना ही पड़ता है। हम अगर स्वाभिमान की बात करते हुए यह कह सकते हैं कि हम हाथ नहीं फैलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर यहां हाथ फैलाने की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है दिल में कुछ पाने की चाहत हो, तो वह चीज मिल जाती है।

अगर हमें अनायास कोई चीज मिल जाए, तो हम उसकी कद्र नहीं करते। जिसे प्राप्त करने के लिए हम बार-बार टूटते हैं या कह लें कि मरते हैं, वह जब मिल जाती है, तो हमें सुकून की वह दौलत मिल जाती है, जिसके लिए अच्छे-अच्छे तरस जाते हैं। पर वह मंजिल नहीं होती। जीवन में टूटने का यह क्रम बार-बार आता है। पर इसी में छिपा है बिखरना। बिखरने में होता यह है कि हमारे आसपास पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। हाथ को हाथ नहीं सूझता, अंधेरा इतना गहन होता है कि जिसे हम अपना कहते नहीं थकते, वह भी हमारा हाथ छोड़कर चल देता है। इस अंधेरे का लाभ हर कोई उठाता है। एक-एक करके सभी निकल जाते हैं। जब थोड़ी-सी उजास को हम अपने करीब पाते हैं, तब समझ में आता है कि जिसे हमने अपना सबसे बड़ा संबल माना था, वही हमसे दूर चला गया है। तब कोई नहीं होता। यही होता है बिखरना। हमारे अपने कहे जाने वाले लोग गहन विश्वास का एक-एक टुकड़ा लेकर दूर हो जाते हैं। हम उस वक्त अकेले होते हैं। कई बार इतने अकेले कि हमारी छाया भी नहीं होती। अंधेरे में भला छाया किसके साथ होती है? हमें समझ में आ जाता है कि किस-किस ने हमारा साथ दिया। ऐसे लोग गिनती के ही होंगे। बहुत कम लोग। यही लोग अपने होते हैं। इन्हें हम अपना कह सकते हैं। यही चंद लोग हमें समेटने के काम में आते हैं।

कुछ इधर से कुछ उधर से लोग आते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिखरे हुए सच को सामने लाते हैं। हम मान सकते हैं कि यह क्रिया समेटने की है। यह प्रक्रिया बहुत धीमे होती है। बरसों लग जाते हैं सब कुछ समेटने में। जब सब कुछ समेट लिया जाता है, तब लगता है कि हम बहुत ही कठिन रास्तों से गुजरकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यह पल बहुत ही आह्लादित करने वाला होता है कि हमने खुद को समेट लिया। परीक्षा की एक घड़ी को पार कर लिया। अपनों को पहचान लिया।

अब शुरू होती है संवरने की प्रक्रिया। संवरना, यानी सब कुछ धीरे-धीरे व्यवस्थित होना। जिंदगी को यह लगे कि अब आराम के पल हमारे साथ हैं, तो यहीं से शुरू होता संवरना। इन पलों में हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। हमारा परिवार हमारे साथ होता है, हम अपनों के साथ होते हैं। हम खुशी से भर उठते हैं। खुशियां हमारा इंतजार करती होती हैं। चारों ओर से शुभ समाचार मिलने लगते हैं। सही मायने में जिंदगी ठहर जाती है। इस ठहरी हुई जिंदगी को गहरी सांस लेकर जी लेना चाहिए, क्योंकि अगले ही पल फिर शुरू हो सकती है टूटने की प्रक्रिया... जिसके लिए शायद हम तैयार न हों!

दुनिया मेरे आगे

> अगर हमें अनायास कोई चीज मिल जाए, तो हम उसकी कद्र नहीं करते। जिसे प्राप्त करने के लिए हम बार-बार टूटते हैं, अगर वह मिल जाए, तो हमें सुकून की एक दौलत मिल जाती है, जिसके लिए अच्छे-अच्छे तरस जाते हैं। यह मंजिल नहीं होती। जीवन में टूटने का क्रम बार-बार आता है, पर इसी में छिपा है बिखरना।

समझौता और संतुलन

अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और द्विपक्षीय व्यापार हाल के वर्षों में लगातार बढ़ा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता निर्यात, निवेश और तकनीकी सहयोग के नए अवसर खोलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों को इससे विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं भारत के लिए यह एक रणनीतिक अवसर भी है। हालांकि, इस समझौते के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। बौद्धिक संपदा नियमों और कृषि मानकों को लेकर दबाव बढ़ सकता है। इससे घरेलू उद्योगों, खासकर लघु और मध्यम उद्यमों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव पड़ेगा। किसानों और डेटा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित नीति बनाना सरकार के लिए बड़ी परीक्षा होगी। इसके बावजूद यह समझौता भारत के निर्यात, निवेश और तकनीकी सहयोग को गति देकर वैश्विक मंच पर उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है। आपूर्ति शृंखला में भारत की भूमिका बढ़ने से रोजगार और विनिर्माण क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। आवश्यक है कि भारत किसी भी समझौते में अपने दीर्घकालिक आर्थिक हितों, आत्मनिर्भरता और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दे।

– ऐश यादव, जम्मू

विश्वास की डोर

'न्याय की गरिमा' (संपादकीय, 16 फरवरी) पढ़ा। न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे मजबूत और विश्वसनीय स्तंभ माना जाता है। जब उसी स्तंभ पर प्रश्नचिह्न लगने लगे, तो आम नागरिकों का विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। शिकायतों का यह अर्थ नहीं है कि पूरी न्यायपालिका ही संदिग्ध है, बल्कि संकेत यह है कि व्यवस्था में कुछ कमियां जरूर हैं- जैसे, मुकदमों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब, व्यवहार संबंधी शिकायतें या निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। न्याय में देरी को भी अन्याय के समान माना जाता है। समाधान के रूप में न्यायिक अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण, कार्य प्रणाली की निगरानी के लिए स्वतंत्र तंत्र और शिकायतों के त्वरित तथा निष्पक्ष निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे महत्त्वपूर्ण है जवाबदेही की स्पष्ट प्रणाली, ताकि ईमानदार अधिकारियों का मनोबल बढ़े। विश्वास ही न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति है।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

नागरिक भागीदारी

पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा घर के बगल में कूड़ेदान व सार्वजनिक शौचालय होने को गरिमा पूर्ण जीवन के अधिकार का हनन करने वाला मानना बिल्कुल सही है। यह उन लोगों के हित में है जो अपने आसपास साफ-सुथरा माहौल चाहते हैं। मगर वे रोज सुबह उठते ही प्राकृतिक माहौल के बजाय कूड़े और दुर्गंध का सामना करने को विवश हैं। संभव है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान भी निकल आए। मगर यह स्मरण रखना चाहिए कि स्वच्छता केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। हमें इधर-उधर कचरा फेंकने की अपनी प्रवृत्ति पर लगाम लगाना ही होगा। निस्संदेह सरकार द्वारा जारी अपशिष्ट के स्रोत को अलग-अलग करने के लिए कचरा प्रबंधन प्रणाली इसमें प्रभावी साबित हो सकती है, लेकिन नागरिक भागीदारी के बिना यह संभव नहीं है।

– भगवती, नासिक, महाराष्ट्र

शहर की सूरत

शहरों में रोजगार के अवसर और चकाचौंध भरी जिंदगी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। छोटे शहर लगातार बड़े शहरों में तब्दील हो रहे हैं। आबादी के अनुपात में बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हो रहा है। अधिकांश शहरों में यातायात जाम, गंदगी, प्रदूषण और अवैध निर्माण की समस्या सामान्य बात हो चुकी है। शहरों की प्रमुख बुनियादी समस्या आवास, सड़क, अतिक्रमण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली-पानी और जल निकासी की है। बुनियादी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी नगर निकाय और राज्य सरकार की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, तभी गांव से पलायन के दौर को रोका जा सकेगा।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

सलाल बांध

चेनाब नदी पर सलाल बांध के तलछट की सफाई भारत ने शुरू की है। यहां बिजली बनाने की पूरी क्षमता का इस्तेमाल होगा।

बोल

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के हास्यास्पद, खराब ढंग से लिखे गए और अमेरिका विरोधी फैसले की समीक्षा के बाद मैं शुल्क को बढ़ाकर 15 फीसद कर रहा हूं। इन देशों में से कई दशकों से अमेरिका से अनुचित लाभ उठा रहे थे। – डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

बोल

संसद को संबोधित करने की तैयारी चल रही है। अगले हफ्ते यहां कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी। आप जानते हैं, भारत छोटा देश नहीं है। आबादी 1.4 अरब है। भारत बेहद शक्तिशाली और लोकप्रिय है। – बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री

सम-सामयिक

अंतरिक्ष : महाशक्तियों की जंग का नया अखाड़ा, कौन कितने पानी में

जनसत्ता संवाद

महाशक्तियों के लिए अंतरिक्ष अब जंग का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। रूस, चीन और अमेरिका सैन्य उपयोग के लिए समर्पित उपग्रहों के माध्यम से सामरिक-रणनीतिक बढ़त हासिल कर रहे हैं। हालांकि, भारत ने अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, लेकिन अंतरिक्ष में सामरिक ताकत बनने लायक पर्याप्त नहीं।

रूस ने 22 फरवरी 2022 को जब यूक्रेन पर हमला किया, तब रूस ने सबसे पहले वहां की उपग्रह संचार प्रणाली- वायासैट की केए-सैट प्रणाली पर काबू (हैक) कर लिया। इससे ना सिर्फ यूक्रेन की सेना की संपर्क क्षमता बाधित हुई, बल्कि पूरे यूरोप में हजारों संचार उपकरण भी प्रभावित हुए। इसी महीने की शुरुआत में, रूस के एक जासूसी अंतरिक्ष यान ने यूरोप के उपग्रह सिग्नल को बाधित किया। यूरोपीय मीडिया के अनुसार, यूरोप के सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि दो रूसी अंतरिक्ष यानों ने यूरोपीय महाद्वीप के ऊपर स्थित एक दर्जन महत्त्वपूर्ण उपग्रहों के संचार को बाधित किया।

दरअसल, वैश्विक शक्तियां अंतरिक्ष को भविष्य के युद्धक्षेत्र के रूप में देख रही हैं। आधुनिक युद्ध का स्वरूप ऐसा होता जा रहा है कि बढ़त के लिए अंतरिक्ष पर प्रभुत्व होना बहुत जरूरी है। संचार बाधित तो सब कुछ खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'गोल्डन डोम' प्रणाली अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को और बढ़ावा दे सकती है।

अप्रैल 2023 में अमेरिका की खुफिया एजंसी ने दावा किया कि युद्ध की स्थिति में चीन अपने दुश्मन के उपग्रहों को निष्क्रिय करने, उनका फायदा उठाने या उन्हें पकड़ने के लिए उन्नत साइबर हथियारों का विकास करने में सफल हो चुका है। इनमें वे हथियार हैं, जो संकेतों की नकल कर उपग्रहों को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऐसा होने पर उपग्रहों का एक समूह काम करना बंद कर सकता है, हथियार प्रणालियों को आदेश नहीं मिलेगा, महत्त्वपूर्ण खुफिया सूचनाएं व संचार का डेटा भी बाधित होगा।

चीन कुछ समय से ऐसे उपग्रहों का परीक्षण कर रहा है, जिनमें रोबोटिक हाथ लगे हैं। ये दुश्मन के उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा से बाहर खींच या धकेल सकते हैं। जून 2025 में चीन ने अंतरिक्ष में मौजूद अपने उपग्रहों में ईंधन भरने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। 2023 में, चीन ने कृषि और मौसम विज्ञान से संबंधित गतिविधियों की निगरानी के बहाने अपने याओगान 41 उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया। हालांकि, इसकी स्थिति ऐसी थी कि यह उपग्रह ताइवान और दक्षिण चीन सागर सहित एक बड़े क्षेत्र पर करीबी नजर रख सकता था। चीन के लगभग 600 उपग्रह हैं। इनमें से करीब 360 जासूसी उपग्रह हैं।

दूसरी ओर, उपग्रह और उपग्रह-रोधी- दोनों ही प्रौद्योगिकियों के मामले में अब भी अमेरिका ही अग्रणी है। वर्ष 2019 में अपने पहले कार्यकाल में, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का अंतरिक्ष कमान की स्थापना की। इसे अमेरिकी उपग्रहों को खतरों से बचाने और अंतरिक्ष युद्ध के लिए अपनी प्रणालियों को विकसित करने का दायित्व सौंपा गया। तीनों देशों के बीच अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की होड़ का एक परिणाम यह हुआ है कि अब बड़े और महंगे या बहुउद्देशीय उपग्रहों से हटकर कम लागत वाले और आसानी से नष्ट किए जा सकने वाले उपग्रहों की ओर रुझान बढ़ा है।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम

भारत ने जी सैट-20 जैसे उपग्रह और गगनयान अंतरिक्ष मिशन के अलावा एक अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम शुरू किया है। दुश्मन की प्रणालियों को बाधित करने के लिए अंतरिक्ष-आधारित प्रणालियों को विकसित और तैनात करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने 2018 में अपनी 'डिफेंस स्पेस एजंसी' की स्थापना की। इसके तुरंत बाद मार्च 2019 में इसने अपना पहला उपग्रह-रोधी शक्ति परीक्षण किया, जिसमें इसने पृथ्वी की कक्षा में अपने निष्क्रिय उपग्रह को मिसाइल से नष्ट कर दिया।

शोध

जल्द सुलझ सकती है रहस्यमय रेडियो संकेतों की गुत्थी

जनसत्ता संवाद

'नेचर एस्ट्रोनामी' में प्रकाशित एक नए अध्ययन में अंतरिक्ष के रहस्यमंय रेडियो संकेतों की प्रकृति को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। हाल के वर्षों में ऐसे रेडियो संकेतों के स्रोत खोजे गए हैं, जिनकी अवधि 18 मिनट से लेकर छह घंटे से अधिक तक है। अध्ययन के अनुसार, अब तक का सबसे लंबे समय तक सक्रिय 'लांग-पीरियड ट्रांजिएंट' जीपीएम जे1839-10 है, जो वास्तव में एक 'वाइट ड्वार्फ' तारा हो सकता है।

अंतरिक्ष से हर कुछ मिनटों या घंटों में दोहराए जाने वाले रहस्यमय रेडियो संकेत 'लांग-पीरियड ट्रांजिएंट्स' की खोज 2022 में हुई थी, लेकिन इनके बारे में तब अधिक जानकारी नहीं मिल पाई और खगोलविद इनका रहस्य सुलझाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। 'नेचर एस्ट्रोनामी' में प्रकाशित एक नए अध्ययन में इन संकेतों की प्रकृति को लेकर अहम जानकारी सामने आई है।

रेडियो खगोलविद 'पल्सर' से भली-भांति परिचित हैं, जो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रान तारे होते हैं। पृथ्वी से देखने पर ये इसलिए स्पंदित दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके ध्रुवों से निकलने वाली शक्तिशाली रेडियो किरणें लाइटहाउस की तरह अंतरिक्ष में घूमती हैं।

अब तक ज्ञात सबसे धीमे पल्सर भी कुछ सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। हाल के वर्षों में ऐसे रेडियो संकेतों के स्रोत खोजे गए हैं, जिनकी अवधि 18 मिनट से लेकर छह घंटे से अधिक तक है। विशेषज्ञों के अनुसार, न्यूट्रान तारे इतनी धीमी गति से घूमते हुए रेडियो तरंगें उत्पन्न नहीं कर सकते, जिससे वैज्ञानिकों के सामने नई पहेली खड़ी हो गई।

अध्ययन के अनुसार, अब तक का सबसे लंबे समय तक सक्रिय 'लांग-पीरियड ट्रांजिएंट' जीपीएम जे1839-10 है, जो वास्तव में एक 'वाइट ड्वार्फ' तारा हो सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह तारा अपने एक सहचर तारे की मदद से शक्तिशाली रेडियो किरणें उत्पन्न कर रहा है, और संभव है कि अन्य ऐसे स्रोत भी इसी तरह के हों। 'वाइट ड्वार्फ' मृत तारों के अवशेष होते हैं, जो आकार में पृथ्वी जितने, लेकिन द्रव्यमान में सूर्य के बराबर होते हैं।

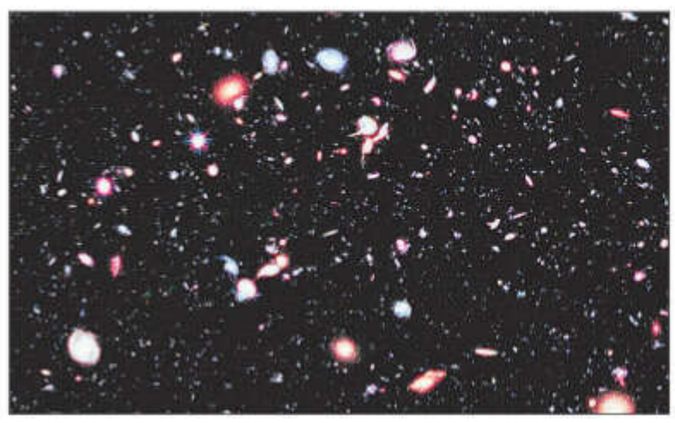

(फाइल फोटो)

वर्ष 2016 में पहले वाइट ड्वार्फ पल्सर की पुष्टि हो चुकी है। अब तक खोजे गए दस से अधिक 'लांग-पीरियड ट्रांजिएंट्स' में से 2025 में पहली बार दो को निश्चित रूप से 'वाइट ड्वार्फ एम-ड्वार्फ' द्वितारा प्रणाली के रूप में पहचाना गया, जिसने वैज्ञानिकों को नए सवालों पर विचार करने के लिए मजबूर किया। वर्ष 2023 में खोजे गए जीपीएम जे1839-10 की परिक्रमा अवधि 21 मिनट है और यह अन्य स्रोतों की तुलना में असाधारण रूप से लंबे समय से सक्रिय पाया गया। अभिलेखीय आंकड़ों में इसके संकेत 1988 तक दर्ज मिले। यह पृथ्वी से लगभग 15,000 प्रकाश-वर्ष दूर है और केवल रेडियो तरंगों में ही दिखाई देता है।

तीन महाद्वीपों में स्थित रेडियो दूरबीनों- आस्ट्रेलिया की एएसकेएपी, दक्षिण अफ्रीका की मीरकैट और अमेरिका की वेरी लार्ज ऐरे-से किए गए अवलोकनों में पाया गया कि इसके संकेत पूरी तरह नियमित हैं। संकेतों का यह घटनाचक्र नौ घंटे में दोहराया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक द्वितारा प्रणाली है। शोधकर्ताओं ने रेडियो आंकड़ों के आधार पर इस प्रणाली की ज्यामिति, तारों के बीच की दूरी और उनके द्रव्यमान का भी अनुमान लगाया है।

अध्ययन के मुताबिक, जीपीएम जे1839-10 'लांग-पीरियड ट्रांजिएंट' और वाइट ड्वार्फ पल्सर के बीच की 'मिसिंग लिंक' हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हालांकि रेडियो उत्सर्जन की भौतिकी को पूरी तरह समझने के लिए और शोध की जरूरत है, लेकिन यह अध्ययन इन रहस्यमय संकेतों की प्रकृति को समझने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

विश्व परिक्रमा

कृत्रिम मेधा : मानव जैसे रोबोट की कितनी जरूरत

जनसत्ता संवाद

नार्वे-अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनी वनएक्स ने दुनिया का पहला मानवनुमा रोबोट बनाने की हाल में घोषणा की। कुल 168 सेंटीमीटर लंबे और 30 किलोग्राम वजनी 'नियो' नामक इस रोबोट की कीमत लगभग 20,000 अमेरिकी डालर है। कंपनी का कहना है कि यह कपड़े तह करने और बर्तन धोने जैसे घरेलू काम स्वचालित ढंग से कर लेता है।

नियो में कृत्रिम मेधा (एआइ) प्रणाली अंतर्निहित है। हालांकि, जटिल कार्यों के लिए कंपनी का एक कर्मचारी वर्चुअल रियलिटी हेलमेट पहनकर उसे दूर से नियंत्रित करता है। इस दौरान आपरेटर घर के भीतर, रोबोट जो भी देखता है, उसे देख सकता है और यह प्रक्रिया भविष्य में सीखने के लिए रेकार्ड भी की जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष अन्य घरेलू मानवनुमा रोबोट भी बाजार में आ सकते हैं।

विश्वभर में 50 से अधिक कंपनियां ऐसे रोबोट विकसित कर रही हैं। वैक्यूम क्लीनर जैसे विशेष रोबोट तो आम हो गए हैं, परंतु मानव घरों का ढांचा रोबोट के अनुकूल नहीं है। कई सूक्ष्म कार्यों में विशेष मशीनें बेहतर परिणाम देती हैं।

रोबोट के प्रदर्शन को सुधारने के लिए वास्तविक दुनिया के विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता होगी, जो लोगों के घरों में काम करते समय एकत्र होंगे। इससे निजी जीवन से जुड़े संवेदनशील डेटा के संग्रहण का खतरा बढ़ता है और गोपनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

'इंटरनेशनल फेडरेशन आफ रोबोटिक्स' के अनुसार, व्यापक रूप से स्वीकार्य और उपयोगी घरेलू मानवनुमा रोबोट आने में अभी लगभग 20 वर्ष लग सकते हैं। वहीं जापानी शोधकर्ता हिरोशी इशिगुरो दशकों से मानव-सदृश 'जेमिनाइड' बना रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल सुविधा या मुनाफा नहीं बल्कि यह समझना है कि मानव होने का मतलब क्या है।

जानें-समझें

कृत्रिम मेधा का बाजार

वैश्विक होड़ में भारत की रणनीति क्या है

जनसत्ता संवाद

कृत्रिम मेधा की वैश्विक दौड़ में अमेरिका, चीन और यूरोप फिलहाल आगे हैं। इन सबके बीच भारत ने समावेशी राह पकड़ी है और डेटा, नवाचार और सरकारी नीतियों के दम पर देश कृत्रिम मेधा बाजार के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है।

कैसा है बाजार, क्या हैं संभावनाएं

दुनिया भर में कृत्रिम मेधा (एआइ) का बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है। साल 2025 से 2030 के बीच लगभग 36.6 फीसद की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ इसके बढ़ने का आकलन किया गया, जो साल 2030 तक लगभग 1811.75 अरब डालर तक पहुंच सकता है। अग्रणी देशों में पहला स्थान अमेरिका का है, जो उन्नत शोध, सरकारी व निजी निवेश और नीतिगत समर्थन के कारण सबसे उन्नत पारिस्थितिकी तंत्र वाला देश बना हुआ है। इसके बाद चीन है, जहां विभिन्न स्तरीय कानून और उनके पालन को सुनिश्चित करने वाले तंत्र पर आधारित सार्वजनिक निवेश का ढांचा है। भारत तीसरे पायदान पर है, जहां कंप्यूटर, उन्नत शोध, विकास और नवाचार से जुड़ी कुछ खामियां जरूर हैं। हालांकि, एआइ में तेज विकास कर रहा है।

चीन की रणनीति

साल 2017 की 'न्यू जेनरेशन एआइ डेवलपमेंट' योजना में वर्ष 2030 तक वैश्विक एआइ में नेतृत्व करने का लक्ष्य रखा गया था। 8.2 अरब डालर के 'नेशनल एआइ इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड' और नवाचार व रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए 138 अरब डालर के 'नेशनल वेंचर कैपिटल गाइडेंस फंड' जैसे सरकारी निवेशों को अलीबाबा और बाइटडांस जैसी बड़ी टेक कंपनियों के निजी निवेशों से मदद मिली है। व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून और डेटा सुरक्षा जैसे कानूनों को एल्गोरिदम, डीप सिंथेसिस व संबंधित प्रौद्योगिकियों से जुड़े नियमों के साथ जोड़ा गया है। इस ढांचे से जिम्मेदारियां तय होती हैं, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर नियंत्रण मजबूत होता है। अपने डिजिटल सिल्क रोड के माध्यम से चीन ने 'वैश्विक दक्षिण' पर भी निगाह डाली है।

(फाइल फोटो)

कृत्रिम मेधा (एआइ) वैश्विक आर्थिक वृद्धि को 0.8 फीसद तक बढ़ा सकती है और भारत के विकसित बनने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती है। इसका अर्थ है कि भारत का विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। – *क्रिस्टलिना जार्जीवा, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की प्रबंध निदेशक*

भारत अधिकतर अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। वाणिज्यिक उद्यम, जो जानकारी को स्वामित्वाधीन रखना चाहते हैं और मानवता के हित में उसे बढ़ाने के बीच चुनौतियां अवश्य होंगी, लेकिन इस संदर्भ में भारत बेहतर स्थिति में है। – *शांतनु नारायण, एडोब के मुख्य कार्यपालक अधिकारी*

संरचनात्मक चुनौती

वैश्विक एआइ केंद्र के रूप में उभरने की भारत की महत्त्वाकांक्षा को कुछ जमीनी चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है। भारत को सबसे पहले कंप्यूटर ढांचे पर ध्यान देना होगा। यहां ऊर्जा-कुशल डेटाकेंद्रों की सीमित उपलब्धता है, जिसे दूर करने की जरूरत है। 'एआइकोष', 'ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफार्म' और 'नैशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफार्म (एनडीएपी) जैसे प्रयास किए गए हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण व अद्यतन 'डेटासेट' तक सबकी समान पहुंच नहीं है। साफ है कि चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित समाधान खोजना होगा। हरित कंप्यूटिंग ढांचे में निवेश बढ़ाने, डेटासेट तक जिम्मेदारीपूर्वक पहुंच सुनिश्चित करने और निजी डेटा साझाकरण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनानी होंगी। शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग भी मजबूत करना होगा।

अमेरिका का दबदबा

अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा एआइ केंद्र बनकर उभरा है। एआइ में अमेरिकी दबदबा बनाए रखने के लिए 2019 में कार्यकारी आदेश जारी किया गया और 2020 में 'नेशनल एआइ इनीशिएटिव ऐक्ट' लाया गया। 'द क्रिएटिंग हेल्पफुल इनीशिएटिव्स टु प्रोड्यूज सेमीकंडक्टर्स' (चिप्स) कानून ने घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमता बढ़ाने में मदद की है, जो एआइ के लिए अहम है। अमेरिका ने मई 2025 में 'एआइ डीफ्यूजन रूल' को रद्द किया, जो उन्नत एआइ माडल और उच्च-स्तरीय चिप्स के वैश्विक आदान-प्रदान को कड़ाई से नियंत्रित करता था। वर्ष 2025 की एआइ कार्ययोजना से इसकी पुष्टि भी होती है, जो विदेश में अमेरिकी नेतृत्व को मजबूत करने के लिए नियमों में ढील देने, निजी क्षेत्र में नवाचार तेज करने और घरेलू एआइ ढांचा बढ़ाने पर जोर देती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका हर समाधान उपलब्ध कराने वाला देश बनने की योजना में है।

भारत की समावेशी राह

वर्ष 2024 में लाई गई 'इंडिया एआइ मिशन' नीति का उद्देश्य एक साझा और रियायती कृत्रिम मेधा ढांचा बनाना है। इसके लिए पांच साल में 10,300 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। भारत उद्यमों को सस्ते दामों में जरूरी उपकरण (38,000 जीपीयू और 1,050 टीपीयू) उपलब्ध करा रहा है, जिसका उद्देश्य घरेलू चिप व सेमीकंडक्टर निर्माण को आगे बढ़ाना और भारत में एआइ पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना है। लंबे समय तक चिप आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की योजना है। 'भाषिणी' और आगामी 'इंडिया एआइ डेटासेट' जैसे मंच भाषा और डेटासेट उपलब्धता पर काम कर रहे हैं। स्वदेशी माडल, उत्कृष्टता केंद्र और आइ कौशल विकास पर काम हो रहा है। भारत में एआइ शासन माडल मुख्य रूप से 'पहले सक्षम करें, फिर नियम बनाएं' नीति पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि एआइ नवाचार को फलने-फूलने देना चाहिए, लेकिन नैतिकता और सुरक्षा की कीमत पर नहीं।

व्यक्तित्व

वरुण : टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला नया सितारा

जनसत्ता संवाद

भारत टी20 विश्व कप के सुपर आठ में पहुंच चुका है। टीम की इस उपलब्धि में एक गेंदबाज का बहुत बड़ा योगदान है। ये वरुण चक्रवर्ती हैं, जो घरेलु क्रिकेट में तमिलनाडु की तरफ से खेलते हैं। उन्होंने वर्तमान टी20 विश्व कप में अबतक 10 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। हालांकि, भारत के लिए वे इस सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ पांच मैचों में हासिल की है। सुपर आठ मुकाबले में भारत को वरुण चक्रवर्ती से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें इस अहम मुकाबले में केवल एक ही विकेट मिला। उन्होंने यह विकेट तब लिया था जब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरपा रहे थे। चक्रवर्ती ने डेविड मिलर का अहम विकेट लेकर इस साझेदारी को तोड़ा। चौंतीस वर्षीय इस भारतीय खिलाड़ी को सुपर ओवर में अभी जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से भी खेलना है।

वरुण ने साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण किया था। वे एक ऐसे स्पिनर थे, जो काफी हद तक साइडस्पिन पर निर्भर रहते थे। पिच से कुछ स्पिन तो मिलती है, लेकिन साथ ही काफी ड्रिफ्ट भी होती है। बीच में उनकी गेंद पर काफी रन बनने लगे। इस वजह से 2021 के टी20 विश्व कप के बाद उन्हें टीम में मौका नहीं मिला। भारतीय टीम में मौका न मिलने पर उन्होंने अपने निजी कोच एसी प्रतिभान से सलाह ली। उन्होंने चक्रवर्ती को गेंद पर ओवरस्पिन डालने का सुझाव दिया था और इसी की मदद से चक्रवर्ती अपनी गेंदबाजी में काफी सुधार ला पाए।

तमिलनाडु प्रीमियर लीग में चक्रवर्ती ने भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन के साथ काम किया। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ भी समय बिताया है ताकि वे अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वर्ष 2025 की शुरुआत से वह टी20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। मौजूदा विश्व कप में भी अधिकांश बल्लेबाज चक्रवर्ती की गेंद पर संघर्ष करते दिखे। उन्होंने प्रति ओवर केवल 5.16 रन दिए हैं और हर आठ गेंदों में एक विकेट लिया है। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में वरुण ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आठ मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 22 विकेट लिए। इस दौरान वे एक बार चार और एक बार पांच विकेट भी ले चुके हैं।

वरुण ने 40 टी20 मैच की 38 पारियों में 68 विकेट ले चुके हैं, जिसमें एक बार उन्होंने पांच विकेट भी लिए हैं।

संपादकीय जागरण

मंगलवार, 24 फरवरी, 2026 : फाल्गुन शुक्ल - 7-8 वि. 2082

आत्मबल का इंधन ही सफलता की यात्रा संपन्न कराता है

व्यापार समझौते की राह

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्रंप की टैरिफ नीति को अवैधानिक करार देने के उपरांत भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार वार्ता टलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह यह कहा कि फिलहाल टैरिफ में बदलाव को लेकर कुछ कहना कठिन है, उससे इसे लेकर सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि अमेरिका से व्यापार समझौता कब होगा? जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने 25 प्रतिशत टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने एवं रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को खत्म करने की घोषणा की थी और उसके बाद दोनों देशों की ओर से व्यापार समझौते को लेकर संयुक्त बयान जारी किया गया था तो माना जा रहा था कि मार्च में यह समझौता हो जाएगा। फिर मार्च के स्थान पर अप्रैल में समझौता होने की संभावना व्यक्त की गई, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चिढ़े ट्रंप की ओर से सभी देशों पर पहले 10 और फिर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद व्यापार समझौते को लेकर संशय पैदा हो गया है। फिलहाल न तो यह कहा जा सकता है कि अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता कब होगा और न ही यह कि इस समझौते की टैरिफ दरें क्या होंगी?

यह ठीक है कि वाणिज्य मंत्रालय बदले हालात की समीक्षा कर रहा है, लेकिन बहुत कुछ ट्रंप प्रशासन के रवैये पर निर्भर करेगा, जिसके स्थिर रहने का ठिकाना नहीं। इन स्थितियों में भारत के लिए उचित यही होगा कि वह अन्य देशों से व्यापार समझौते संबंधी वार्ताओं को गति प्रदान करे। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपीय संघ आदि के साथ जो व्यापार समझौते हो चुके हैं, उन्हें अंतिम रूप देने का काम यथाशीघ्र किया जाए। यह सही है कि भारत समेत अन्य देशों के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है और उसके साथ व्यापार समझौता भारतीय कारोबारियों के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के हित में है, लेकिन भारत को अपने उत्पादों एवं सेवाओं की खपत के लिए अन्य विकल्प तलाशने का काम प्राथमिकता के आधार पर करते रहना चाहिए। इसमें इसलिए ढील देना उचित नहीं होगा कि अंततः अमेरिका से व्यापार समझौता होना ही है। भारत के हित में यही है कि उसके उत्पादों की खपत विश्व के अधिक से अधिक देशों में हो। भारत को अपने उत्पादों के लिए अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों को अनुकूल बाजार के रूप में इसलिए भी खोजना चाहिए, क्योंकि इससे ही वह ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के दबदबे को खत्म कर सकता है और उन देशों की आकांक्षा भी पूरी कर सकता है, जो भारत को चाइना प्लस वन रणनीति के तहत एक प्रमुख देश के रूप में देख रहे हैं। निःसंदेह यह सब तब संभव होगा, जब भारतीय कारोबारी अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता विश्वस्तरीय बनाएंगे।

स्वागतयोग्य कदम

वायु प्रदूषण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। ऐसे में 17 साल लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में संशोधन की सुगबुगाहट स्वागत योग्य कदम है। आइआइटी कानपुर द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी गई अंतिम तकनीकी रिपोर्ट इस दिशा में एक मील का पत्थर है। यह वाकई चिंता का विषय है कि देश में वायु गुणवत्ता के मौजूदा मानक आखिरी बार 2009 में निर्धारित किए गए थे। जबकि पिछले डेढ़ दशक में चिकित्सा विज्ञान और प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के शोध में काफी बदलाव आ चुका है।

17 साल लंबे इंतजार के बाद वायु गुणवत्ता मानकों में संशोधन की कवायद स्वागत योग्य कदम है, यह जल्द लागू किया जाए

मानकों को कड़ा करना केवल कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' की सफलता की भी अनिवार्य शर्त है। जब तक हमारे लक्ष्य ऊंचे नहीं होंगे, हम अपनी भावी पीढ़ियों को 'फेफड़ों की बीमारी' विरासत में देते रहेंगे। भले ही रिपोर्ट सौंपने में देरी हुई हो, लेकिन अब गेंद सीपीसीबी और सरकार के पाले में है। सरकार को बिना किसी और देरी के इन तकनीकी सिफारिशों को सार्वजनिक करना चाहिए और नए, पारदर्शी व सख्त मानकों की घोषणा करनी चाहिए। हवा की शुद्धता का यह नया पैमाना ही सार्वजनिक स्वास्थ्य की नई दिशा तय करेगा।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

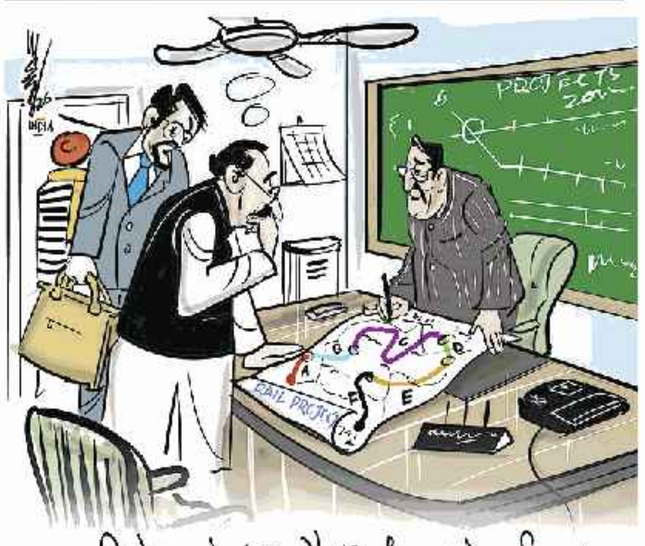

आप परियोजना के A, D और F खंड का लोकार्पण कर चुके हैं! अब B और E फिर C देश को समर्पित करेंगे!!

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या समय-समय पर आतंकियों की धरपकड़ यही संकेत करती है कि उनके लिए स्थानीय सहायता जारी है?

आज का सवाल

क्या दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद भारत के विश्व कप जीतने की दावेदारी कमजोर पड़ गई?

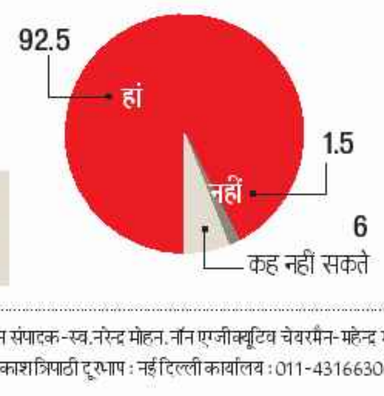

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

दूर किए जाएं माओवाद के उभार के कारण

आरके विज

ले सकता है कि 31 मार्च के बाद कुछ इलाकों में छिटपुट लड़ाई जारी रहे, पर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि विकास के कार्यों में कोई विलंब न हो

कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माओवादी) अब बिखरने की कगार पर है। यह संगठन 2012 से ही दंडकारण्य में लगातार कमजोर हो रहा था, लेकिन कुछ समय पहले उसे तगड़ा झटका लगा। अपनी कार्यनीति में बदलाव कर अगस्त 2024 से माओवादियों ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो सके। जैसे-जैसे सुरक्षा बलों ने उनके इलाकों में सुरक्षा कैंप बढ़ाने शुरू किए, वैसे-वैसे माओवादियों को आश्रय लेने एवं विचरण करने वाले स्थलों को छोड़ना पड़ा। मई 2025 में माओवादी पार्टी के महासचिव बसवराजू के मारे जाने और अक्टूबर 2025 में पोलित ब्यूरो सदस्य वेणुगोपाल उर्फ सोनू एवं केंद्रीय कमेटी सदस्य रूपेश द्वारा करीब 260 साथियों के साथ समर्पण करने के बाद संगठन लगभग बिखर गया। इनमें उत्तर बस्तर, पूर्व बस्तर, गढ़चिरौली और अबूझमाड़ के माओवादी थे। उनके समर्थन में गरियाबंद-धमतरी के माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और दिसंबर में महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ स्पेशल जोन के प्रभारी रामदेर और सचिव कबीर ने भी अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। लंबे समय तक मिलिट्री बटालियन का कमांडर रहा हिड़मा माडवी आंध्र में एक मुठभेड़ में मारा गया। अभी गत दिवस केंद्रीय कमेटी के देवजी और संग्राम ने भी आत्मसमर्पण कर दिया।

माओवादियों की खस्ता हालत देखकर लगता नहीं कि सशस्त्र आंदोलन के पुनर्जीवित होने के कोई आसार हैं। इसलिए जरूरी है कि जहां आंदोलन खत्म हो गया या दक्षिण-पश्चिम बस्तर जहां आंदोलन काफी कमजोर है, वहां सरकार को उस खालीपन को विकास से भरने की जरूरत है, जहां माओवादी विकास में अवरोध बने हुए थे।

केंद्र और राज्य की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास की नीतियों के तहत राज्य सरकारें आत्मसमर्पित माओवादियों को आवश्यक लाभ देकर उनके पुनर्वास की कार्रवाई कर रही है। सरकार की नीतियों में विश्वास कायम रखने के लिए यह जरूरी भी है, परंतु यह भी आवश्यक है कि उन सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाए, जिनके कारण माओवादियों ने ग्रामीणों को अपने पक्ष में कर लिया था। इनमें से सबसे जरूरी है दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। बस्तर क्षेत्र में बहुत से आदिवासी आयरन की कमी से ग्रस्त हैं और उन्हें समय पर दवाई नहीं मिल पाती। उन्हें पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता। इसलिए जरूरी है कि ग्रामीणों के बीच मोबाइल एंबुलेंस चला कर दवाइयों का वितरण किया जाए।

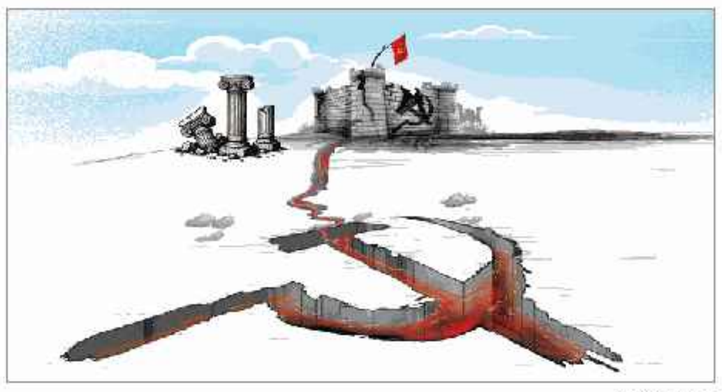

अवधेश राजपूत

चूंकि अंदरूनी इलाकों में कई सुरक्षा कैंप स्थापित हैं, इसलिए प्रारंभ में इन कैंपों से ही स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जाएं।

माओवादियों ने प्रभावित इलाकों में कई तालाब और कुएं खोदे और जमीनों का समतलीकरण कर उन्हें खेती लायक बनाने में आदिवासियों की सहायता की। इससे उन्हें काफी फायदा मिला, क्योंकि उनकी कथित जनताना सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों का भला करना नहीं, बल्कि उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना था। यही उद्देश्य सभी माओवादी गुटों का भी था, चाहे वह दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ हो, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन हो या चेतना नाट्यमंच। अब शासन का कर्तव्य बन जाता है कि वह ग्रामीणों को अच्छे बीज उपलब्ध कराए और सिंचाई के साधनों में सुधार करे, ताकि ग्रामीणों को पर्याप्त फसल मिल सके। तमाम आदिवासी वन-उपज पर निर्भर हैं। शासन ने तेंदूपत्ता और कई वन उपज के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की है, परंतु इमली, चिरौंजी और महुआ जैसी उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

तीसरा महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा के संबंध में है। माओवादियों ने कई जगहों पर क्रांतिकारी जनताना सरकार स्कूल खोलकर ग्रामीण बच्चों को वामपंथी शिक्षा दी और उन्हें शासन के विरोध में खड़ा किया और शासकीय मशीनरी के प्रति घृणा के बीज बोए। इसलिए जरूरी है कि सरकार अंदरूनी इलाकों में अधिक से अधिक आश्रम एवं स्कूल खोले, छात्रों में रोपे गए विचार बदले, ताकि वे नियमित पढ़ाई कर रोजगार के अवसर तलाश सकें। बस्तर अंचल में जो भी विकास हो, वह वहां के ग्रामीणों को केंद्र रखकर होना चाहिए। चूंकि आदिवासी जंगलों पर निर्भर रहते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं, इसलिए विकास से पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, यह भी सुनिश्चित करना होगा। कई ग्रामीण महिलाओं ने माओवादी संगठन इसलिए ज्वाइन किया, क्योंकि वे जबरन शादी से बचना चाहती थीं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में 'पुतुल' परंपरा के तहत समान्यतः लड़की की शादी मामा के लड़के से बचपन में तय कर दी जाती है। लड़की के युवा होने पर यदि शादी से मना किया जाता है तो उससे जबरदस्ती की जाती है। इसीलिए मर्जी से शादी करने के लिए बड़े बुजुर्गों के माध्यम से जागरूकता लाने की आवश्यकता है।

अधिकांश पुरुष माओवादियों की नसबंदी कर दी गई थी। हालांकि मेडिकल प्रोसिजर से इसे ठीक (रिवर्स) करना संभव है एवं किया भी जा रहा है, परंतु इसी के साथ टेस्ट-ट्यूब बेबी के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए। यह पुनर्वास नीति का ही एक अंग बने। कई आत्मसमर्पित माओवादी कुक थे या मशीनों पर काम करना जानते थे। उन्हें ऐसे पेशों में समाहित करना बेहतर होगा, जिसका उन्हें अनुभव है। कुल मिलाकर आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति को यदि कस्टमाइज करने की आवश्यकता हो तो किया जाए, ताकि आत्मसमर्पित माओवादियों का पुनर्वास बेहतर तरीके से हो सके। कई बड़े आत्मसमर्पित माओवादी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। कुछ समय तक उनके आचरण को देखते हुए उनके पुनर्वास पर भी ध्यान देना होगा।

केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक माओवाद के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जो अधिक दूर नहीं है। निःसंदेह माओवादी काफी कमजोर पड़े हैं। अब सात जिले ही माओवाद से प्रभावित बचे हैं। यदि 31 मार्च तक कुछ माओवादी बच भी जाते हैं तो भी शासन का पलड़ा भारी है। हो सकता है 31 मार्च के बाद भी कुछ इलाकों में छिटपुट लड़ाई जारी रहे, पर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि विकास के कार्यों में विलंब न हो।

(लेखक छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं)
response@jagran.com

लगातार कठिन होता संसद का चलना

अवधेश कुमार

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस संसद में सामान्य स्थिति पैदा नहीं होने दे रही है

बजट सत्र के समय पक्ष-विपक्ष के सांसद ● पीटीआइ

भारत की राजनीति आज ऐसी अवस्था में पहुंच गई है, जिसकी कल्पना नहीं की जाती थी। यह भारत के संसदीय इतिहास की अत्यंत गंभीर स्थिति है, जब लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, तो उसके समानांतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध सब्सटेंसिव मोशन। राहुल गांधी के विरुद्ध भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सब्सटेंसिव मोशन लाने की मांग की है। भाजपा ने पहले राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात की थी, किंतु अब सब्सटेंसिव मोशन लाने की पहल की है। सब्सटेंसिव मोशन विशेषाधिकार हनन से ज्यादा गंभीर होता है। सब्सटेंसिव मोशन स्वतंत्र प्रस्ताव होता है, जिसमें किसी सांसद के विरुद्ध स्पष्ट निर्णय सामने आता है। इस प्रस्ताव पर बहस और मतदान होता है तथा पारित होने पर सदन का आधिकारिक रुख और मत प्रकट होता है। यानी संबंधित सांसद का आचरण और चरित्र संसद के अनुकूल है या नहीं, उन्हें सांसद होना चाहिए या नहीं, उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने देना चाहिए या नहीं आदि। इसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और सदन की सदस्यता भी जा सकती है। चुनाव आयोग को उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की अनुशंसा भी की जा सकती है। जो भी हो, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलने के बाद से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में आना बंद कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव के बाद बहस और परिणाम तक लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने यह निर्णय लिया है। यही बात किसी सांसद या विपक्ष के नेता पर लागू नहीं होती। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव या सब्सटेंसिव मोशन स्वीकृत होने के बावजूद संबंधित सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें अपना पक्ष रखने का समय दिया जा सकता है।

लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर नौ मार्च को बहस होने की संभावना है। उसी दौरान यह पता चलेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन स्वीकृत होता है या नहीं? चूंकि लोकसभा में भाजपा नेतृत्व वाले राजग को बहुमत है इसलिए ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। यह बात सब्सटेंसिव मोशन पर लागू नहीं होती। बहुमत के आधार पर राजग राहुल गांधी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव पारित कर सकता है। हालांकि कांग्रेस में उनके समर्थकों में इससे कोई परेशानी नहीं दिखाई देती। उलटे वे यह कहते हुए प्रफुल्ल हैं कि संसद में एजेंडा तो राहुल गांधी ही सेट कर रहे हैं और अब सब्सटेंसिव मोशन के बहाने बहस भी उन्हीं के इर्द-गिर्द रहेगी। इससे सहज से अनुमान लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी और उनके इर्द-गिर्द के रणनीतिकार किस दिशा में जा रहे हैं। अगर उनकी नजर में यही सही अर्थों में राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करना है तो ऐसी कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। राहुल गांधी अपने राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।

लगता है कि कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि लोगों में उनके प्रति सहानुभूति पैदा हो और वे इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करें, लेकिन कांग्रेस के लोग जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अभियान चलाते रहे हैं उसका क्या? उनकी बेटी के सिविल सर्विस पास होने तक पर प्रश्न उठाए गए थे? कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा उनको लिखा गया पत्र तो और शर्मनाक है। कांग्रेस के सांसद लोकसभा अध्यक्ष के लिए ऐसी कठिन स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें फैसला लेने में ही समस्या हो। ओम बिरला यहां व्यक्ति नहीं लोकसभा अध्यक्ष जैसे गरिमापूर्ण पद पर हैं। उनसे व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है, उनसे नापसंदगी भी होगी, पर पद का सम्मान करने और विश्वास करने का प्राथमिक दायित्व भी नेता और संसद न निभाएं, तो यह शर्मनाक है। अगर राहुल गांधी के समर्थकों को लगता है कि संसद में चर्चा और बहस का एजेंडा सेट करना ही बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है, तो कुछ दिन पहले एसआइआर एवं चुनाव आयोग के संदर्भ में भी उन्होंने ऐसी ही स्थिति पैदा की थी। उन्होंने अपनी ओर से पूरी तैयारी के साथ एसआइआर और चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा किया, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की, लेकिन बिहार चुनाव परिणाम में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। महाराष्ट्र चुनाव में अदाणी मुद्दा उनके लिए सर्वोपरि था, लेकिन वहां भी करारी हार हुई।

लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सांसदों का निलंबन तब किया, जब वे वेल में जाकर लगातार अध्यक्ष की ओर कागज फेंक रहे थे, कोई आदेश या नियमन नहीं मान रहे थे। सदन संचालन के नियम और परंपरा हैं। उन्हें रौंदने पर उतारू लोगों के विरुद्ध अध्यक्ष को फैसला करना ही पड़ेगा।

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और आक्रामक हो गई है। वह नहीं चाहती कि एक दिन भी संसद में सामान्य स्थिति रहे और सदन सुचारु रूप से चले। राहुल ने राष्ट्रपति अभिभाषण से संबंधित मुद्दे पर किसी सत्र में भाषण नहीं दिया। वह मनगढ़ंत विषय लेकर आते हैं और उसे सदन में रखते हैं तथा अध्यक्ष के रोकने पर उन्हें आरोपित करते हैं। इस तरह के व्यवहार में कोई लोकतांत्रिक रास्ता निकल नहीं सकता।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अवसर

अवसर उस परिस्थिति का नाम है, जहां व्यक्ति के संकल्प और सिद्धि के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। इसे हम सौभाग्य की संज्ञा भी देते हैं। यह वह संधि-काल है जब मानवीय प्रयास और अनुकूल परिस्थितियां एक धरातल पर मिलते हैं, जिससे सफलता का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति सही समय पर सही दिशा में कर्म करता है, तो प्रकृति भी उसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बन जाती है।

अवसर की महत्ता को पहचानकर जो व्यक्ति पूर्ण मनोयोग से कर्म में संलग्न हो जाते हैं, वे प्रगति के उच्चतम सोपानों को स्पर्श करते हैं। इसके विपरीत, जो सुअवसर की उपस्थिति में भी प्रमादवश निष्क्रिय रहते हैं, उनके हिस्से में केवल आत्मग्लानि और निराशा ही आती है। यह कहावत बहुत सटीक है कि-अब पछताय होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यह हमें सचेत करती है कि कालचक्र के व्यतीत हो जाने के पश्चात दिखाई गई सजगता निरर्थक होती है। पीछे केवल पश्चाताप शेष रह जाता है। हमारी अर्जित शिक्षा, योग्यता और कौशल की सार्थकता इस बात में नहीं है कि हमने उसे कितना संचित किया, बल्कि इस बात में है कि अवसर आने पर हमने उसका उपयोग किस प्रकार किया। मेधावी वे नहीं हैं, जो अवसर के द्वार खटखटाने की प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि वे हैं, जो अपने पुरुषार्थ से स्वयं अवसर का सृजन करते हैं। अवसर कई बार कठिन श्रम की ओट में छिपा रहता है।

महान विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन आज भी प्रासंगिक है कि प्रत्येक कठिनाई के गर्भ में अवसर निहित होता है। संकट के समय में भी संभावनाओं को खोजना और उन्हें सफलता में रूपांतरित करना ही प्रखर बुद्धिमत्ता का लक्षण है। आपदा में अवसर की यह खोज केवल रणनीति नहीं, बल्कि एक सकारात्मक जीवन-दृष्टि है। अतः समय की गति को पहचानकर अपने गंतव्य की ओर अविलंब प्रस्थान करना ही बुद्धिमानी है।

योगेंद्र माथुर

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

आमजन भी रहें सजग

संपादकीय 'आतंकी गठजोड़' में तमिलनाडु और बंगाल से पकड़े गए आतंकियों के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ को उजागर किया गया है। फर्जी आधार कार्ड के सहारे भारत में बसे अधिकांश आतंकी बांग्लादेशी मूल के हैं, जिनके तार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें मिलकर भारत के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। भारत को पाकिस्तान-बांग्लादेश के इस आतंकी गठजोड़ और आतंकियों के बढ़ते दुस्साहस से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे भारत के भीतर गुप्त रूप से रहकर अपनी आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इन आतंकियों का नकली आधार कार्ड कब, कैसे, कहां और किसके द्वारा बना इसकी भी गहन जांच होना चाहिए एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आतंक के विरुद्ध लड़ाई में वैश्विक देशों और इस्लामी शक्तियों को भारत का साथ देना चाहिए। आतंकवाद मानवता का दुश्मन और संहारक है। किसी को भी इसका किसी भी रूप में समर्थन नहीं करना चाहिए। एक आम नागरिक से यही अपेक्षा है कि वे आतंक के खिलाफ वैचारिक लड़ाई में अच्छे और सही सोच के साथ आगे बढ़ें। अपने आसपास घटित होने वाली असामान्य घटनाओं और गतिविधियों पर नजर रखें। किसी को भी नौकरी पर रखने या मकान किराए पर देने से पहले उसके पहचान प्रमाण पत्रों की पुष्टि करें।

mohitsonikukshi@gmail.com

ट्रेनों की लेटलतीफी

भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो प्रतिदिन लगभग दो करोड़ 31 लाख यात्रियों एवं 33 लाख टन माल ढुलाई करता है। नियत समय पर ट्रेन के पहुंचने का आंकड़ा धीरे-धीरे कम हो रहा है। 2021-22 में यह 90 प्रतिशत था, जोकि 2023-24 में 78.67 प्रतिशत एवं उसके अगले वर्ष 73.62 प्रतिशत ही रह गया। यह स्थिति तब है, जब भारत में 15 मिनट के विलंब को गणना में नहीं लिया जाता। जर्मनी-रूस में पांच मिनट, नीदरलैंड में तीन मिनट एवं जापान में कुछ सेकेंड के विलंब की भी गणना देरी में कर ली जाती है। मिशन रफ्तार के अंतर्गत मालगाड़ी की रफ्तार को 25 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे का था। मेल-एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार 50 से 75 किलोमीटर करने की योजना थी। पर रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि 97 प्रतिशत मेल-एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार लक्ष्य से कम है। महज 62 ट्रेनों की रफ्तार 75 किमी से अधिक है। 60 ट्रेनों की स्पीड तो 30 किमी प्रति घंटा से कम निकली। बड़े स्टेशनों पर ट्रैक पर दबाव बहुत अधिक है। कानपुर सेंट्रल जंक्शन के समीप रेलवे लाइन की क्षमता का 175 प्रतिशत उपयोग हो रहा है। अर्थात जहां पर 100 ट्रेन चलनी चाहिएं, वहां पर 175 ट्रेनें दौड़ रही हैं। लगभग ऐसे ही हाल पटना जंक्शन एवं दानापुर खंड में भी हैं। देश को रेल लाइन बढ़ाने की जरूरत है। यदि ट्रेनें बढ़ती रहीं और ट्रैक में बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ट्रेन की स्पीड में कमी होती जाएगी।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

पुस्तकालयों की अनिवार्यता

वर्तमान समय को यदि ज्ञान और तकनीक का युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल प्लेटफार्म ने जानकारी को सहज, सुलभ और त्वरित बना दिया है। आज का युवा वर्ग ई-कंटेंट, आनलाइन पाठ्यसामग्री, ई-बुक्स और आडियो बुक्स की ओर तीव्र गति से आकर्षित हो रहा है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की आवश्यकता आज पहले से अधिक बढ़ गई है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का भंडार नहीं, बल्कि समाज की बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक परंपरा और नैतिक मूल्यों के संरक्षक हैं। यदि इनकी उपेक्षा की गई, तो ज्ञान-संस्कृति की जड़ें कमजोर पड़ सकती हैं। डिजिटल माध्यमों की तात्कालिकता के बीच पुस्तकालय मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। यह स्थिरता ही गहन चिंतन और मौलिक विचारों को जन्म देती है। देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न राज्यों में इनकी संख्या और गुणवत्ता में व्यापक अंतर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2018-19 तक देश में 46,746 सार्वजनिक पुस्तकालय थे, जिसका उल्लेख राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने किया था। यह संख्या आशाजनक प्रतीत होती है, परंतु देश की विशाल जनसंख्या और युवाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं कही जा सकती। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हजारों पुस्तकालय हैं, जबकि कुछ समृद्ध राज्यों में इनकी संख्या अत्यंत सीमित है।

कातिलाल मांडोत, नई दिल्ली

पोस्ट

अगर आप मैच में हालात के हिसाब से नहीं खेलते तो फिर हारना तय है। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध यही देखने को मिला। मदन लाल@MadanLal1983

भारत की हार को अहमदाबाद के स्टेडियम से जोड़कर देखने वाले भूल जाते हैं कि मुंबई में भी भारत 1987 विश्व कप सेमीफाइनल और 2016 टी-20 विश्व कप सेमीफाइनल हार चुका है। ऐसे आकलन के बजाय हम यह स्वीकार करें कि प्रतिद्वंद्वी दक्षिण अफ्रीका ने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया। पार्थिव पटेल@parthiv9

कांग्रेस ने सभी के लिए बैंकिंग सुविधाओं से लेकर डिजिटल भुगतान और कोविन वैक्सीन प्लेटफार्म तक का विरोध ही किया है। अब वह भारत के एआइ विजन के विरोध में जुटी है। अरविंद गुप्ता@buzzindelhi

नौकरशाहों के जनसंपर्क पर पूर्णतः अंकुश नहीं लगना चाहिए, पर अगर वे पीआर के बजाय अपने काम पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। चूंकि जनता की सेवा करना ही उनका काम है, इसलिए ऐसा करके वे कोई अहसान नहीं करते। हर छोटे-छोटे काम का इंटरनेट मीडिया पर बखान अच्छा नहीं लगता। ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

जनपथ

करना है आतंक पर मिलकर कड़ा 'प्रहार',
खड़ी हो गई कसि कमर भारत की सरकार।
भारत की सरकार न बिल्कुल बरते नरमी,
बना सख्त कानून निकाले सबकी गरमी।
लोग रहें निश्चिंत पड़े ना उनको डरना,
भारत को आतंक मुक्त है हमको करना!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एजीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 221

सेंसेक्स 83,294.66 ▲ 479.95 | सराफा दिल्ली के भाव | सोना ₹1,62,800 10 ग्राम ▲ ₹3,300 | चांदी ₹2,72,000 1 किलो ▲ ₹ 8,000 | डालर($) ₹90.89 ▼ ₹ 0.05

एक नजर में

पहले 10 माह में अपैरल निर्यात 1.6 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: वैश्विक अनिश्चितताओं और सप्लाई चेन से जुड़ी बाधाओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों (अप्रैल 2025 से जनवरी 2026) के दौरान देश के अपैलर निर्यात में 1.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एईपीसी) के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने कहा कि कुछ प्रमुख बाजारों को निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई है। इस दौरान अपैरल निर्यात इटली को 16 प्रतिशत, ब्रिटेन को 4.8 प्रतिशत, संयुक्त अरब अमीरात को 10.6 प्रतिशत, सऊदी अरब को 18.5 प्रतिशत, जर्मनी को 8.7 प्रतिशत और स्पेन को 7.1 प्रतिशत बढ़ा है। (प्रेट्र)

1.62 लाख रुपये प्रति दस ग्राम के पार पहुंचा सोना

नई दिल्ली: ट्रंप टैरिफ पर को लेकर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित संपत्तियों की मांग बढ़ने के कारण सोमवार को घरेलू बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। आल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में 3,300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका मूल्य 1,62,800 रुपये प्रति दस ग्राम पर हो गया है। इसी तरह, चांदी की कीमत आठ हजार रुपये या 3.03 प्रतिशत की तेजी के साथ 2.72 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। (प्रेट्र)

डिजिटल कर्ज कारोबार का विस्तार करेगी एयरटेल

मुंबई: दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने सोमवार को कहा कि वह अगले कुछ वर्षों में डिजिटल कर्ज कारोबार विस्तार में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी अपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) एयरटेल मनी लिमिटेड के जरिये डिजिटल कर्ज वितरण का कारोबार करती है। 20 हजार करोड़ रुपये के कुल निवेश में एयरटेल 70 प्रतिशत और भारती एंटरप्राइजेज 30 प्रतिशत योगदान देंगी। एयरटेल मनी को 13 फरवरी 2026 को ही आरबीआइ से एनबीएफसी लाइसेंस मिला है। (आइएएनएस)

इंश्योरेंस बेचना छोड़ कोर बिजनेस पर ध्यान दें बैंक : वित्त मंत्री

आरबीआइ की बोर्ड बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिस सेलिंग रोकने में असफल रहने पर बैंकों को सुनाई खरी-खोटी

- वित्त मंत्री ने कहा- होम लोन के साथ ग्राहकों पर बीमा खरीदने का दबाव डालते हैं बैंक
- आरबीआइ ने मिस सेलिंग पर हाल में जारी किए हैं दिशानिर्देश, एक जुलाई से लागू होने हैं नियम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: ग्राहकों को गलत जानकारी देकर बैंकिंग और बीमा उत्पाद बेचने की लगातार आ रही खबरों के बीच सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को जमकर खरी-खोटी सुनाई। वित्त मंत्री ने बैंकों के स्तर पर मिस-सेलिंग को रोकने में असफल रहने पर बैंकों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, 'बैंक अपने मुख्य व्यवसाय (कोर बिजनेस- जमा और लोन देना) पर ध्यान दें और मिस-सेलिंग (गलत तरीके से उत्पाद बेचना) बंद करें।' उन्होंने विशेष रूप से बीमा उत्पादों की जबरदस्ती या गलत तरीके से बिक्री पर नाराजगी जताई।

बजट बाद आरबीआइ के निदेशक बोर्ड के साथ होने वाली बैठक के पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए वित्त मंत्री ने कहा, 'मेरी पुरानी शिकायत रही है कि बैंक बीमा बेचने में ज्यादा समय लगाते हैं, जबकि यह जरूरी नहीं होता।' उन्होंने कहा कि कई ग्राहकों पर होम लोन के साथ अनावश्यक बीमा खरीदने का दबाव डाला जाता है, जबकि संपत्ति पहले से गिरवी रखी होती है और ग्राहक के पास पहले से बीमा हो सकता है। पहले आरबीआइ और आइआरडीएआइ के बीच नियामकीय अंतर था, जिससे ग्राहक परेशान होते थे। वित्त मंत्री की यह टिप्पणी तब आई है जब इंटरनेट मीडिया पर लगातार ग्राहकों की तरफ से अपनी आपबीती डाली जा रही है कि कैसे बैंक अधिकारी सामान्य बैंकिंग सेवा देने की जगह बीमा बेचने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बता दें कि 11 फरवरी, 2026 को आरबीआइ की तरफ से भी मिस-सेलिंग पर सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और इस बारे में बैंकों के दायित्व तय किए गए हैं। वित्त मंत्री ने आरबीआइ के हालिया दिशानिर्देश पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे बैंकों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि वह मिस-सेलिंग नहीं कर सकते। नियम एक जुलाई 2026 से लागू होंगे।

नई दिल्ली में सोमवार को आरबीआइ के निदेशक बोर्ड की बैठक के दौरान (बाएं से) केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआइ के गवर्नर संजय मल्होत्रा ● प्रेट्र

केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से महंगा हो रहा सोना, चिंता की बात नहीं

वित्त मंत्री से भारत में सोने की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के बारे में भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे दुनियाभर में केंद्रीय बैंकों की तरफ से की जा रही खरीदारी को वजह बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की नजर इस पर है, लेकिन कोई खास चिंता की बात नहीं है। सीतारमण ने कहा कि अभी तक सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव इसके दो सबसे बड़े वैश्विक खरीदारों भारत और चीन की वजह से होती रही है लेकिन अब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई केंद्रीय बैंक सोने व चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की काफी खरीदारी कर रहे हैं। हाल ही में इसकी वजह से इनकी कीमतों में अविश्वसनीय तरीके से वृद्धि देखने को मिली है।

अमेरिकी टैरिफ पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिका द्वारा घोषित टैरिफ परिवर्तनों पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय स्थिति की समीक्षा कर रहा है और प्रतिनिधिमंडल को आगे की वार्ताओं के लिए निर्णय लेना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि अभी इसके लिए कोई रोडमैप नहीं है। हालांकि, केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिटि इस विषय और दूसरे पहलुओं पर गौर करेगी।

सोने के आयात में वृद्धि से चिंतित नहीं: संजय मल्होत्रा

सोने की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, 'पिछले वर्ष अप्रैल से दिसंबर के दौरान सोना आयात 50 अरब डालर रहा, जो इसके पिछले वर्ष की समान अवधि से सिर्फ एक अरब डालर ज्यादा था। हालांकि, जनवरी-2026 में आयात तेजी से बढ़ा (मात्रा व मूल्य दोनों में) है। हालांकि, सोने का आयात बढ़ना आरबीआइ के लिए चिंता की बात नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि भारतीय इकोनमी आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। सरकार की नीतियां सही दिशा में हैं। दूसरे देशों के साथ कारोबारी समझौते किए जा रहे हैं, जिससे चालू खाते (विदेशी मुद्रा की कमाई और खर्चे का अंतर) की स्थिति मजबूत होगी। विदेशी निवेश आकर्षित करने की नीतियों का भी अच्छा असर दिखाई देगा। हाल ही में कई आइटी कंपनियों ने भारत में भारी-भरकम निवेश का एलान किया है। इसके साथ ही जीडीपी की स्थिति भी काफी अच्छी है। इन वजहों से आरबीआइ सोने के आयात में वृद्धि को लेकर चिंतित नहीं है।

भारत और फ्रांस के बीच दोहरे कराधान नियमों में हुआ बदलाव

- दोनों देशों ने संशोधन के लिए प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए
- मुख्य रूप से कैपिटल गेन से संबंधित टैक्स नियम को बदला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: टैक्स में दोहराव से बचने और टैक्स प्रक्रिया को और स्पष्ट बनाने के लिए भारत और फ्रांस ने डबल टैक्सेशन अवायडेंस कंवेंशन (डीटीएसी) में संशोधन के लिए प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की तरफ से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल तो फ्रांस की तरफ से वहां के राजदूत थिर्रे मैथ्यू ने हस्ताक्षर किए। दोनों देश टैक्स नियमों को जरूरत के मुताबिक अपडेट करना चाहते हैं। वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच डीटीएसी पर हस्ताक्षर किए गए थे। डीटीएसी इसलिए किए जाते हैं ताकि एक ही आय पर दोनों देशों में अलग-अलग टैक्स नहीं लगे। इससे निवेशकों को निवेश करने में आसानी होती है।

मुख्य रूप से कैपिटल गेन से संबंधित टैक्स नियम को बदला गया है। अब किसी कंपनी के शेयर को बेचने पर कैपिटल गेन लगाने का अधिकार उस देश को होगा, जहां कंपनी स्थित है। संशोधन के तहत दोनों देशों के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) क्लाज को अपडेट किया गया है। अब लाभांश पर 10 प्रतिशत की एकल दर तय की गई है। अगर किसी निवेशक के पास 10 प्रतिशत की शेयरहोल्डिंग है तो उन पर पांच प्रतिशत की रियायती दर लागू हो सकती है। संशोधन के तहत अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सूचना के आदान-प्रदान से जुड़े प्रविधानों को भी अपडेट किया गया है।

बैंक-आटो शेयरों में खरीदारी से 480 अंक उछला सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र: अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध बताए जाने के बाद निवेशकों की भावना में सुधार हुआ है। इसके चलते सोमवार को पीएसयू बैंकों, आटो व वित्तीय शेयरों में खरीदारी हुई और भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे।

बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 479.95 अंक की बढ़त के साथ 83,294.66 के स्तर पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार के दौरान यह 671.44 अंक बढ़कर 83,486.15 के उच्च स्तर पर पहुंचा था। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 141.75 अंक बढ़कर 25,713 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में अदाणी पोर्ट्स कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावरग्रिड, हिंदुस्तान यूनीलिवर, एचडीएफसी बैंक के शेयर बढ़कर बंद हुए।

भारत से सर्वाधिक निर्यात वाला उत्पाद बना आइफोन

- कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान देश से कुल 23 अरब डालर के आइफोन का निर्यात किया गया
- प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव और उत्पादन में विविधीकरण के चलते निर्यात में आया उछाल

नई दिल्ली, आइएएनएस: पिछले साल यानी 2025 में एपल का आइफोन भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला उत्पाद रहा। इस दौरान 23 अरब डालर के आइफोन निर्यात किए गए, जिनमें से ज्यादातर अमेरिका भेजे गए। उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि एपल के निर्यात में यह उछाल प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम जैसे उत्पादन प्रोत्साहन और चीनी सप्लायर से अलग उत्पादन के विविधीकरण के चलते हुआ।

2025 में जनवरी से दिसंबर के दौरान कुल 30.13 अरब डालर के निर्यात के साथ स्मार्टफोन पहली बार भारत की शीर्ष निर्यात श्रेणी में शामिल हो गया है और इसने आटोमोटिव डीजल ईंधन को पीछे छोड़ दिया है। कुल स्मार्टफोन निर्यात में एपल की हिस्सेदारी 76 प्रतिशत थी। एपल को मिलने वाला पांच साल का पीएलआइ मार्च, 2026 में खत्म हो जाएगा। देश में एपल के पांच असेंबलिंग प्लांट हैं। इनमें से तीन टाटा समूह द्वारा संचालित किए जाते हैं वहीं दो ताइवान की कंपनी फाक्सकान चलाती है। इन कंपनियों को 45 छोटी-बड़ी फर्मों से सप्लाई चेन का समर्थन मिलता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पाद बन गया है। इतना ही नहीं, देश में बिकने वाले 99 प्रतिशत से ज्यादा मोबाइल फोन देश में ही बनते हैं। मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में ऊपर आ गया है। भारतीय ग्राहकों के स्मार्टफोन खरीदारी के पैटर्न में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। काउंटरपाइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट में हाल ही में कहा गया था कि अब बजट सेगमेंट के बजाय लोग अधिक कीमत वाले स्मार्टफोन खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। आइफोन-16 बेस वेरिएंट 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन माडल बनकर उभरा है।

30.13 अरब डालर के कुल स्मार्टफोन का निर्यात हुआ जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान भारत से

भारत सहित उभरते बाजारों में दोहरे अंकों की राजस्व वृद्धि हुई

एपल के सीईओ टिम कुक ने कुछ दिनों पहले दिसंबर तिमाही के नतीजों का एलान करते हुए कहा था कि हमने भारत सहित उभरते बाजार में रफ्तार पकड़ना जारी रखा है। इन बाजारों में हमने मजबूत दोहरे अंकों को राजस्व वृद्धि दर्ज की है। कंपनी 26 फरवरी को मुंबई में एक और स्टोर खोलने जा रही है। कुक ने कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट और चौथा सबसे बड़ा पर्सनल कंप्यूटर बाजार बन गया है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय जागरण

शिक्षाविद् बोले, युवा कांग्रेस का प्रदर्शन नासमझी भरा काम

- कला-असहमति और प्रतिष्ठा की रक्षा कैसे की जाए, इसका अंतर समझें
- एआइ इंपैक्ट समिट में कांग्रेस की युवा शाखा ने किया था विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश के 160 प्रमुख शिक्षाविदों ने पिछले सप्ताह ''एआइ इंपैक्ट समिट'' में कांग्रेस की युवा शाखा द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को बहुत खेदजनक और नासमझी भरा काम करार दिया। कहा कि यह विपक्षी पार्टी की इस बात की असमर्थता को दर्शाता है कि लोकतांत्रिक असहमति और वैश्विक मंच पर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच अंतर कैसे किया जाए।

शिक्षाविदों ने सोमवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि ''राहुल गांधी से जुड़े'' विरोध प्रदर्शन ने ऐसे समय में एक दुर्भाग्यपूर्ण धारणा पेश की है, जब वैश्विक निवेशक और प्रौद्योगिकी से जुड़े लोग एआइ तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों में दीर्घकालिक भागीदार के रूप में भारत की विश्वसनीयता का आकलन कर रहे हैं। सांसद होने के नाते रचनात्मक लोकतांत्रिक आलोचना और ऐसे कार्यों के बीच अंतर करने की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, जो वैश्विक स्तर पर अनजाने में भारत की प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकते हैं। संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलिपुडी पंडित, आइआइटी रुड़की के निदेशक कमल किशोर पंत, आइआइटी धारवाड़ के निदेशक वेंकप्पैया आर. देसाई, आइआइटी जोधपुर के निदेशक अविनाश कुमार अग्रवाल व विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा प्रोफेसर शामिल हैं।

पिछले शुक्रवार को भारत मंडपम में ''एआइ इंपैक्ट समिट'' के दौरान एक प्रदर्शनी हाल में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षाविदों ने कहा कि ''एआइ इंपैक्ट समिट'' एक अंतरराष्ट्रीय मंच था, जहां भारत दुनिया के सामने अपनी तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा था।

हमारे कार्यकर्ताओं का हो रहा है उत्पीड़न : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : 'इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट' के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी ने अपने युवा विंग के नेताओं की गिरफ्तारी और हिरासत की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। पार्टी का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध करना कोई गुनाह नहीं है और ''उत्पीड़न'' की यह कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार को घेरते हुए एक्स पर कहा, शांतिपूर्ण असहमति को अपराध या खतरा नहीं माना जाना चाहिए। विरोध लोकतंत्र का दिल है, अपराध नहीं। शशिकांत सेंथिल सहित कांग्रेस के सात सांसदों ने प्रेस कान्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं के प्रति एकजुटता जताई।

केसी वेनूगोपाल ●

'कांग्रेस के भीतर से भी उठा स्वर, नग्नता का आचरण करना निंदनीय'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित विपक्षी गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा एआइ इंपैक्ट समिट में कांग्रेस के अशोभनीय प्रदर्शन की आलोचना के बाद कांग्रेस की ही वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा के बयान के सहारे भाजपा ने कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयास किया है। सांसद एवं भाजपा प्रवक्ता डा. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि अब कांग्रेस के भीतर से भी यह स्वर उठने लगा है कि इस तरह का हल्का, छिछोरा और नग्नता का आचरण करना निंदनीय है।

उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत को 'सपेरों का देश' कहे जाने को उचित ठहराए जाने का प्रसंग भी सुनाते हुए आरोप लगाया कि भारत की हर उपलब्धि और श्रेष्ठता को कमतर दिखाना तथा उसे धूमिल करने का प्रयास करना कांग्रेस का एक सहज, स्वाभाविक और योजनाबद्ध षड्यंत्रपूर्ण आचरण रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विश्व एआइ शिखर सम्मेलन में जहां भारत की बुद्धिमत्ता, तकनीकी कुशलता का उच्च कोटि का प्रदर्शन हुआ तो वहीं कांग्रेस की नग्नता का कुटिलतापूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। इसे लेकर पूरा देश न केवल स्तब्ध है, बल्कि आक्रोशित भी है। कांग्रेस के गठबंधन सहयोगियों ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई है।

सुधांशू त्रिवेदी ●

पूर्व भाजपा सांसद ने मुस्लिम महिलाओं से वापस लिए कंबल

जासं, जयपुर : राजस्थान में टोंक सवाईमाधोपुर संसदीय सीट से भाजपा के सांसद रहे सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने रविवार को क्षेत्र में कंबल वितरित किए। इस दौरान जौनापुरिया ने मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस ले लिए। उन्होंने कहा, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गाली दे, उन्हें कंबल लेने का हक नहीं है।

बताया गया है कि कंबल वितरित करते हुए पूर्व सांसद ने एक महिला से नाम पूछा। महिला ने अपना नाम सकूरान खान बताया। नाम सुनते ही जौनापुरिया ने उससे कंबल वापस ले लिया। जौनापुरिया ने कहा, यह मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम था। उधर, कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुईं मुस्लिम महिलाओं ने कहा, पहले तो हमें अन्य महिलाओं की तरह कंबल दिए गए। लेकिन बाद में कंबल वापस ले लिए। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा के पूर्व सांसद की मानसिकता उनकी पूरी पार्टी के सोच को दर्शाती है।

इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए अलंकार ने बनाई अपनी पार्टी

सोमवार को बांसुरी हाथ में लिए अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (राम) की औपचारिक घोषणा करते अलंकार अग्निहोत्री ● जागरण

जागरण संवाददाता, वृंदावन : यूजीसी नियमों के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपनी पार्टी का एलान कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (राम) के गठन और चिन्ह की औपचारिक घोषणा की। राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद बल्लभ गोस्वामी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार ने कहा, उनकी पार्टी का नाम भारतीय संविधान के भाग-3 में वर्णित मूल अधिकारों से प्रेरित है। मूल अधिकारों के हनन के विरोध और अधिकारों की रक्षा के लिए यह मोर्चा स्थापित किया गया है। इसे राम और कृष्ण के सांस्कृतिक प्रतीकों का समागम बताया। अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जनरल और ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। यूजीसी रेगुलेशन-2026 और एससी-एसटी एक्ट के क्रियान्वयन को लेकर भी आपत्ति जताई।

पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय का निधन

राज्य, कोलकाता : पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय का दिल का दौरा पड़ने से रविवार देर रात कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। उनके बेटे सुभ्रांशु राय ने बताया कि वह कई दिनों से कोमा में थे। उत्तर 24 परगना के हालीशहर श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राय को बंगाल की राजनीति का 'चाणक्य' भी कहा जाता था।

मुकुल राय ●

राय 1998 में तृणमूल कांग्रेस के गठन के समय उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पार्टी से मतभेद होने के बाद वह 2017 में भाजपा में शामिल हो गए थे। राय 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने, लेकिन चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राय के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

'लंबे समय तक संबंध के बाद शादी का वादा पूरा न करना अपराध नहीं

जास, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि दो पढ़े-लिखे बालिगों के बीच लंबे समय तक शारीरिक संबंध कायम रहने के बाद शादी का वादा पूरा न करने का अपराध नहीं है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने बस्ती कोतवाली निवासी श्याम बहादुर यादव की याचिका स्वीकार करते हुए की है। कोर्ट ने याची के खिलाफ चार्जशीट, समन आदेश समेत आपराधिक केस कार्यवाही को रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा, स्वीकृत तथ्य है कि पीड़िता व अभियुक्त 2016 से एक-दूसरे को जानते हैं।

उन्होंने शादी के वादे पर 2019 से शारीरिक संबंध बनाए। परिवार शादी को राजी था। वर्ष 2019 से 2025 तक संबंध कायम रहा और 2020 में दो बार गर्भपात भी कराया गया। कोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि लंबे समय तक शारीरिक संबंध कायम रखा है तो अवधारणा सहमति की होगी। बाद में शादी से इन्कार किए जाने पर दुष्कर्म का अपराध नहीं बनता। पीड़िता ने एफआइआर में यह तथ्य नहीं दिया कि वह तलाकशुदा है।

जागरण विशेष | एआइ इंपैक्ट

मरीज की जान जोखिम में पड़े उससे पहले मिल जाता अलर्ट

कानपुर के एलएलआर अस्पताल में एआइ आधारित 20 वेंटिलेटर पर उपचार शुरू, ये हेल्थ के प्रमुख पैरामीटर पर रखते हैं हमेशा नजर

अंकुश शुक्ल ● जागरण

कानपुर : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) केवल तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एआइ को भारत का ''भाग्य और भविष्य'' बताए जाने का आशय अब अस्पतालों में स्पष्ट दिखने लगा है। जीएसवीएम मेडिकल कालेज से संबद्ध लाला लाजपत राय (एलएलआर) अस्पताल के मेडिसिन आइसीयू-एचडीयू वार्ड में एआइ आधारित 20 अत्याधुनिक वेंटिलेटर पर गंभीर मरीजों का उपचार इसका उदाहरण है। इन वेंटिलेटर में स्थापित एआइ साफ्टवेयर मरीज के बीपी, हृदय गति, सांस लेने की गति, आक्सीजन स्तर जैसे प्रमुख हेल्थ पैरामीटर पर निरंतर नजर रखता है। निर्धारित मानक से जरा भी कम-ज्यादा होते ही सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है, जिससे डाक्टर समय रहते उपचार में आवश्यक बदलाव कर सके। परिणामस्वरूप उपचार अधिक सटीक, त्वरित और प्रभावी बन रहा है। गंभीर श्वसन स्थितियों, निमोनिया, सेप्सिस, आघात, तथा न्यूरोमस्कुलर विकारों से जूझ रहे मरीजों को विशेष लाभ मिल रहा है। दिल्ली में आयोजित एआइ इंपैक्ट समिट के बाद आम जनजीवन में एआइ की बढ़ती भूमिका को केंद्र में रखते हुए दैनिक जागरण ने विशेष शृंखला शुरू की है। यह इसकी पहली किस्त है और अब प्रत्येक मंगलवार को इस विषय पर विशेष स्टोरी पढ़ने को मिलेगी।

लाला लाजपत राय चिकित्सालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेंटिलेटर और उन पर उपचाराधीन मरीज ● जागरण

अब डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी का असर नहीं पड़ रहा

जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला कहते हैं कि एआइ वार्ड के कारण डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ की कमी का उपचार पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। सामान्य तौर पर वेंटिलेटर वाले मरीजों की निगरानी के लिए इनकी व्यवस्था अलग से करनी होती है, लेकिन एआइ वेंटिलेटर गंभीर स्थितियों के मरीजों की 24 घंटे डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ के बिना निगरानी करते हुए अलर्ट देते हैं। इसके लिए कक्ष में केवल तकनीकी जानकार को बैठाकर पूरी रिपोर्ट डाक्टरों तक पहुंच रही है। इमरजेंसी में भर्ती होने वाले गंभीर मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है। एआइ आधारित 20 वेंटिलेटर मिल जाने के बाद इमरजेंसी में आइसीयू बेड की संख्या 58 हो गई है।

प्राचार्य प्रो. संजय काला

एआइ वार्ड को टेलीमेडिसिन सुविधा से भी जोड़ा गया है। इसके माध्यम से देश के उच्च चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ जांच रिपोर्ट के आधार पर परामर्श दे रहे हैं। जटिल सर्जरी या गंभीर स्थिति में भी विशेषज्ञ राय तत्काल उपलब्ध हो रही है। इससे न केवल उपचार की गुणवत्ता बेहतर हुई है, बल्कि मरीजों और स्वजन को भरोसा भी मिला है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सलाह मिल रही है। इतना ही नहीं, अब आयुष्मान वार्ड में भी 30 बेड के नीचे सेंसर युक्त एआइ चिप लगाकर चौबीसों घंटे निगरानी की तैयारी अंतिम चरण में है। यह व्यवस्था मरीजों के पल्स रेट, बीपी और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों पर सतत नजर रखेगी तथा किसी भी असामान्यता पर डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ को तुरंत सूचित करेगी। इससे आकस्मिक जटिलताओं की संभावना घटेगी और मरीज सुरक्षित वातावरण में उपचार पा सकेंगे। डाक्टर की टीम त्वरित प्रतिक्रिया से मरीज की जांच कर उनके जीवन की रक्षा कर सकेंगे। इसकी शुरुआत मार्च के पहले सप्ताह से करने की तैयारी है।

उपचार प्रक्रिया सरल व व्यवस्थित हुई: जीएसवीएम मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कालेज बन गया है, जहां संबद्ध अस्पताल में एआइ की सहायता से गंभीर मरीजों का उपचार व्यवस्थित रूप से हो रहा है। कालेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला के अनुसार करीब 3.95 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित ये एआइ एडवांस वेंटिलेटर श्वसन क्रिया को रोगी की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करते हैं और उपचार परिणामों को बेहतर बनाते हैं। प्रतिदिन करीब साढ़े तीन हजार ओपीडी मरीजों और औसतन सौ से अधिक भर्ती मरीजों का एलएलआर अस्पताल में उपचार होता है। एआइ ने उपचार प्रक्रिया को सरल, व्यवस्थित और समयबद्ध बनाया है। बड़े सड़क हादसों से लेकर गंभीर बीमारियों तक, एआइ तकनीक जीवन बचाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। स्पष्ट है कि यदि तकनीक का सही और संवेदनशील उपयोग हो, तो वह केवल सुविधा नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की मजबूत आधारशिला बन सकती है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

ढाका से रिश्ते सुधरने की उम्मीद

ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ मुलाकात को दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. भारतीय उच्चायुक्त ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान विभिन्न मोर्चों पर लोकतांत्रिक बांग्लादेश के साथ बेहतर सहयोग करने की प्रतिबद्धता तो दोहरायी ही, विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया. बांग्लादेश में नयी सरकार के आने के तुरंत बाद ढाका-अगरतला बस सेवा के ट्रायल रन की शुरुआत भी रिश्तों को बेहतर करने की प्रतिबद्धता का सूचक है. कोलकाता होकर जाने वाली यह बस सेवा त्रिपुरा को ढाका के रास्ते कोलकाता से जोड़ती है और इससे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी राज्यों के बीच बांग्लादेश के जरिये यात्रा आसान हो जाती है. वर्ष 2003 में शुरू हुई यह बस सेवा कोविड के समय बंद थी, और फिर मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में रिश्ते खराब होने के दौर में बंद हो गयी थी. बांग्लादेश ने भारतीय यात्रियों के लिए वीजा सेवा की पूर्ण बहाली की बात भी कही है. दरअसल, बांग्लादेश में चुनाव से पहले सुरक्षा हालात के कारण ढाका ने सामान्य वीजा सेवा बंद कर दी थी, हालांकि आपातकालीन वीजा सेवाएं जारी थीं. भारत भी अपनी तरफ से वीजा सेवा को पहले की तरह बहाल कर सकता है, लेकिन इसका फैसला बाद में लिया जायेगा. जाहिर है, भारत की तरफ से भी बांग्लादेश की नयी सरकार के साथ संबंध सामान्य बनाने की कोशिशें जारी हैं. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री जयशंकर का पहुंचना शुरुआती संदेश था कि नयी दिल्ली बीएनपी को भविष्य के स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देख रही है. फिर बांग्लादेश में चुनावी परिणाम आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई संदेश भेजा था. उस दिन दोनों ने फोन पर बात भी की थी. उसके बाद नयी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका गये थे. ओम बिरला ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ बैठक तो की ही थी, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जल्द भारत आने का आमंत्रण भी दिया था. गौरतलब है कि मोहम्मद यूनुस के 18 महीने के कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गये थे. आपसी रिश्ते अब पटरी पर लौटते हैं, तो इसका लाभ दोनों ही देशों को होने वाला है.

बांग्लादेश की नयी सरकार ने ढाका-अगरतला बस सेवा का ट्रायल रन शुरू करने के साथ-साथ वीजा सेवा की पूर्ण बहाली की बात कही है, तो भारत भी अपनी तरफ से आपसी संबंध सुधारने की पहल कर रहा है. इससे दोतरफा रिश्तों के पटरी पर लौटने की उम्मीद है.

एआइ समिट में दिखी भारत की क्षमता

बालेन्दु शर्मा दाधीच
सीइओ, एल्गो टेक्नोलॉजीज, दुबई
balendudadhich@gmail.com

इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट ने भारतीय प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का मौका दिया. भारतीय स्टार्टअप कंपनी सर्वम एआइ ने 105 अरब पैरामीटर वाला एक ऐसा भाषायी मॉडल पेश किया, जो लोकप्रिय वैश्विक मॉडलों को टक्कर दे सकता है. खास बात यह है कि इसे वैश्विक मॉडलों की तुलना में बहुत ही कम संसाधनों के साथ बनाया गया है और यह भारतीय भाषाओं का बेहतरीन समर्थन करता है. 'भारत जेन' जैसे अन्य स्वदेशी मॉडलों ने भी ध्यान खींचा.

अभी-अभी संपन्न इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट में पांच लाख से अधिक लोगों की भागीदारी एक बड़ी उपलब्धि रही. इस आयोजन ने और भी बहुत कुछ दिया है- भारत को भी और एआइ के वैश्विक इकोसिस्टम को भी. एआइ की होड़ में अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं. लेकिन इस समिट ने संदेश दिया कि भारत इस दौड़ में तीसरे खंभे के रूप में उभर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर 'मानव एआइ' की अवधारणा पेश की- ऐसी तकनीक, जो इंसानों की हो, इंसानों द्वारा बनायी गयी हो, और इंसानों के भले के लिए काम करे. यह सोच अमेरिका और चीन के तकनीकी वर्चस्व के मुकाबले एक नैतिक और मानवीय विकल्प पेश करती है. भारत लंबे अरसे से सामाजिक रूप से जिम्मेदार एआइ की बात करता रहा है और कुछ साल पहले इसी थीम पर हमारे यहां एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (रेज, 2020) भी हो चुका है.

मौजूदा समिट अपनी श्रेणी के चुनिंदा और बड़े वैश्विक शिखर सम्मेलनों में से एक रहा. इस तरह के सम्मेलन पिछले कुछ वर्षों में ब्लेचली पार्क (ब्रिटेन), फ्रांस, कोरिया आदि में भी हुए हैं और इसी तरह का अगला शिखर सम्मेलन 2027 में स्विटजरलैंड में होगा. दिल्ली शिखर सम्मेलन में राजनीति, कारोबार और तकनीक की दुनिया के वैश्विक दिग्गजों की मौजूदगी महत्वपूर्ण थी. इसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए. दिग्गज कंपनियों के सीइओ, जैसे- गूगल के सुंदर पिचाई, ओपनएआइ के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के दारियो अमोदेई भी नयी दिल्ली आये थे. इतने दिग्गज व्यक्तित्वों की मौजूदगी वैश्विक राजनीति, कारोबार और टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती अहमियत का सबूत है. दुनिया की बड़ी तकनीकी कंपनियों के लिए भारत का मतलब है डेढ़ अरब लोगों का बाजार, करोड़ों युवा इंजीनियर, और अथाह डाटा का खजाना. एआइ के लिहाज से ये सभी बहुत कीमती हैं और कोई भी आइटी दिग्गज इन्हें अनदेखा करना नहीं चाहेगा. समिट में कई आर्थिक उपलब्धियां दर्ज हुईं. दुनियाभर के निवेशकों ने ढांचागत क्षेत्र में 250 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के वादे किये. डीप टेक, यानी अत्याधुनिक तकनीक के लिए 20 अरब डॉलर की वेंचर कैपिटल का वादा भी किया गया. ओपनएआइ, एंथ्रोपिक, एनवीडिया, एएमडी, आइबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक एआइ कंपनियों, इंफोसिस, टीसीएस, लार्सन एंड टूब्रो आदि प्रमुख भारतीय कंपनियों और राज्य सरकारों के साथ भागीदारी के समझौते भी हुए हैं. सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धि रही भारत का पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होना. अमेरिकी अगुवाई में बना यह एक महत्वपूर्ण मंच है, जो एआइ चिप्स और तकनीकी आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा के लिए बनाया गया है. ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देश पहले से ही इसमें शामिल हैं. भारत को इसमें शामिल किये जाने का अर्थ है कि अमेरिका प्रौद्योगिकी और एआइ में भारत को एक भरोसेमंद साझेदार मानता है.

किसी विकासशील देश में एआइ को केंद्र में रखते हुए पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ है. भारत ने इस मंच का उपयोग 'ग्लोबल साउथ' के देशों की प्रतिनिधि शक्ति के रूप में किया. अस्सी से ज्यादा देशों ने 'नयी दिल्ली एआइ घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर किये, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एआइ के नियम-कायदे केवल अमेरिका और यूरोप तय न करें, बल्कि उसे सही अर्थों में समावेशी और लोकतांत्रिक बनाया जाये. भारत ने इतने देशों को सामने ला खड़ा किया, जो उसकी अपनी राजनीतिक महत्ता के साथ-साथ एआइ जैसी रूपांतरकारी तकनीक पर इसके नजरिये की स्वीकार्यता का प्रतीक भी है. इस समिट ने भारतीय प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का मौका भी दिया. भारतीय स्टार्टअप कंपनी सर्वम एआइ ने 105 अरब पैरामीटर वाला एक ऐसा भाषायी मॉडल पेश किया, जो लोकप्रिय वैश्विक मॉडलों को टक्कर दे सकता है. खास बात यह है कि इसे वैश्विक मॉडलों की तुलना में बहुत कम संसाधनों के साथ बनाया गया है और यह भारतीय भाषाओं का बेहतरीन समर्थन करता है. 'भारत जेन' जैसे अन्य स्वदेशी मॉडलों ने भी ध्यान खींचा. आइआइटी, गुवाहाटी के एक छात्र शालिग्राम देवांगन ने मात्र 1.1 लाख रुपये की लागत में बना दस भारतीय भाषाओं में काम करने वाला एआइ मॉडल दिखाया. यह कम खर्च में बड़ा काम करने की भारतीय क्षमता का जीता-जागता उदाहरण है. भारत ने टीबी की जांच के लिए एआइ आधारित एक्स-रे स्कैनिंग, सरकारी सेवाओं के लिए बहुभाषी वॉयस बॉट्स और किसानों के लिए मौसम पूर्वानुमान जैसे उपयोगी प्रयोगों को दुनिया के सामने रखा. इन उदाहरणों ने यह साबित किया है कि भारत की तकनीक आम आदमी के काम आ सकती है. एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के 250 से अधिक एआइ पेटेंट ने दिखाया कि भारत की एआइ क्षमताएं केवल ढांचागत क्षेत्र, सॉफ्टवेयर और सेवाओं तक सीमित नहीं हैं.

समिट के बाद अब नजरें 'इंडिया एआइ मिशन 2.0' पर हैं. इसके तहत 20 लाख नागरिकों को एआइ का प्रशिक्षण देने, एआइ विकास और शोध के लिए 20,000 अतिरिक्त जीपीयू उपलब्ध कराने और स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल लॉन्च करने की योजना है. हालांकि हकीकत यह है कि भारत अब भी 90 फीसदी जीपीयू आयात करता है. जीडीपी का सिर्फ 0.7 प्रतिशत ही अनुसंधान एवं विकास पर खर्च होता है, डाटा सुरक्षा के कड़े कानूनों का अभाव है और एआइ के कारण 2030 तक 30 करोड़ नौकरियों के प्रभावित होने का अनुमान है. फिर भी, भारत एआइ इंपैक्ट समिट, 2026 एक ऐसा आईना है, जिसमें भारत की दोनों तस्वीरें दिखती हैं. हमारी क्षमताओं, कामयाबियों और महत्वाकांक्षाओं से इनकार नहीं है. सर्वम एआइ जैसे स्टार्टअप की सफलता, आइआइटी के होनहार छात्रों का नवाचार और 86 देशों तथा दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों को साथ लाने की कूटनीतिक सफलता निःसंदेह महत्वपूर्ण है. दूसरी तरफ रोबोट डॉग का मुद्दा, सम्मेलन के दौरान सड़कों पर पैदल चलते प्रतिनिधि और अव्यवस्थाओं के कुछ मामले भी थे. इन सब पर भी गहराई से विचार करना होगा. इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट से यकीनन भारत में एआइ का फलक विस्तार लेगा- शोध, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, विकास, अर्थव्यवस्था, रोजगार, कौशल आदि पर इसका ठोस प्रभाव पड़ेगा. सबसे बड़ी बात यह कि एआइ की दुनिया में हमारी मजबूत उपस्थिति भी रेखांकित होगी. लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सच है कि खुद को अमेरिका और चीन की श्रेणी में लाने के लिए हमें अभी कई बड़ी बाधाएं पार करनी हैं. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

फरवरी की यह गर्मी खेती के लिए चेतावनी है

पंकज चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार
pc7001010@gmail.com

फरवरी का महीना वह समय होता है जब रबी की फसलें और आम के बगीचे अपने पूर्ण यौवन पर होते हैं. पर 2026 की यह फरवरी डराने वाली है. सूरज की तपिश ने समय से पहले ही मार्च के अंत वाले रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं. जलवायु परिवर्तन अब कोई दूरगामी चेतावनी नहीं, हमारे खेतों की मेड़ पर खड़ा एक कड़वा सच है, जिसका सबसे घातक प्रहार हमारी खाद्य सुरक्षा पर हो रहा है.

फरवरी का महीना आमतौर पर गुलाबी ठंड और वसंत की मंद बयार का प्रतीक माना जाता रहा है. यह वह समय होता है जब रबी की फसलें और आम के बगीचे अपने पूर्ण यौवन पर होते हैं. पर 2026 की यह फरवरी डराने वाली है. उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, औरैया और बुंदेलखंड के पठारों से लेकर बिहार के कैमूर और समस्तीपुर तक, सूरज की तपिश ने समय से पहले ही मार्च के अंत वाले रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं. फरवरी के मध्य में ही देश के एक बड़े हिस्से में पारा 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है, जो सामान्य से करीब पांच से सात डिग्री अधिक है. यह 'ग्लोबल वार्मिंग' का वह क्रूर चेहरा है, जो सीधे हमारी थाली और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रहार कर रहा है. भारत में 'सर्दियों का संकुचन' अब एक स्थायी संकट बनता जा रहा है.

जलवायु परिवर्तन का सबसे घातक प्रहार हमारी खाद्य सुरक्षा और आम पर हो रहा है. रबी की मुख्य फसल गेहूं के लिए फरवरी का दूसरा पखवाड़ा बालियों में दाना भरने की अवस्था का होता है. इस नाजुक दौर में अचानक बढ़ी गर्मी 'थर्मल स्ट्रेस' पैदा कर रही है. जब तापमान 30 डिग्री के ऊपर बना रहता है, तो पौधों के भीतर चयापचय की प्रक्रिया असामान्य रूप से तेज हो जाती है और दाना पूरी तरह विकसित होने से पहले ही सख्त होने लगता है. परिणामस्वरूप, दाना छोटा, हल्का और झुर्रियों वाला रह जाता है. कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि तापमान में इसी तरह की वृद्धि जारी रही, तो गेहूं की पैदावार में प्रति हेक्टेयर 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. सागर और औरैया के खेतों से आ रही रिपोर्टें बताती हैं कि गेहूं की बालियां समय से पहले सफेद पड़ रही हैं. यही संकट बिहार में आम के मंजरों पर भी मंडरा रहा है. विशेषज्ञ विश्लेषण बताते हैं कि आम का पुष्पन जाड़े के अंत और वसंत की शुरुआत में स्थिर तापमान और मध्यम आर्द्रता में होता रहा है. किंतु तापमान की वर्तमान अनिश्चितता ने इस प्रक्रिया को 'रोलर-कोस्टर' बना दिया है. लगातार 27-30 डिग्री से ऊपर का तापमान मंजर को समय से पहले परिपक्व कर देता है, जिससे फूलों की गुणवत्ता घटती है और वे झड़ने लगते हैं. इसके विपरीत, यदि अचानक तापमान गिरता है, तो फूलों का खुलना असमान हो जाता है. सुबह की अत्यधिक नमी फफूंदजनित रोगों का जोखिम बढ़ा रही है, जबकि दोपहर की शुष्क हवा पराग के अंकुरण को बाधित कर रही है. नतीजा, या तो फूल गिर रहे हैं, या निषेचन के बाद भी फल टिक नहीं पा रहे हैं. पछिया हवा की बढ़ती तीव्रता ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है, जिससे मंजरों की यांत्रिक गिरावट बढ़ गयी है.

बुंदेलखंड और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में इस साल पश्चिमी विक्षोभ की विफलता ने आग में घी का काम किया है. आमतौर पर सर्दियों में होने वाली बारिश फसलों के लिए अमृत समान होती थी, पर इस वर्ष शुष्कता और बढ़ती गर्मी ने मिट्टी की नमी सोख ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले एक दशक में फरवरी के महीने में लू जैसी स्थितियों की आवृत्ति बढ़ी है. यह पैटर्न स्पष्ट संकेत दे रहा है कि भारत के मौसम चक्र से 'वसंत' ऋतु धीरे-धीरे गायब हो रही है और हम सीधे कंपकंपाती सर्दी से झुलसाने वाली गर्मी के दौर में प्रवेश कर रहे हैं. इसका असर केवल गेहूं और आम पर ही नहीं, सरसों और दलहन पर भी पड़ रहा है. सरसों की फलियों में तेल की मात्रा कम होने की आशंका है और चने के पौधों में फूल समय से पहले ही झड़ रहे हैं. इस विकट परिस्थिति का निदान अब केवल पारंपरिक खेती के ढर्रे पर चलकर संभव नहीं है. हमें जलवायु अनुकूल कृषि की ओर युद्धस्तर पर बढ़ना होगा. मिट्टी की नमी बचाने के लिए गन्ने की सूखी पत्तियों, भूसे या सूखी घास से 'मल्चिंग' करना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है. यह तकनीक सतह के तापमान को स्थिर रखती है और पानी के वाष्पीकरण को रोकती है. इसके साथ ही, सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) को अपनाना होगा. बागों की मेड़ों पर कटहल, बांस या नीम जैसे 'विंड ब्रेक' (वायुरोधी अवरोध) लगाने चाहिए, ताकि तेज पछिया हवाओं से फूलों और फलों का बचाव हो सके.

पुष्पन के दौरान बोरॉन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित छिड़काव फूलों की जीवन क्षमता बढ़ा सकता है. कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए मौसम पूर्वानुमान आधारित छिड़काव ही कारगर होगा. सरकार और संस्थागत सहयोग की भूमिका भी अब केवल मुआवजा वितरण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. ब्लॉक स्तरीय मौसम परामर्श और सटीक पूर्वानुमान आज किसानों के लिए सबसे बड़े 'निर्णय-सहायक उपकरण' हैं. जलवायु परिवर्तन के इस दौर में फसलों की किस्मों का विवेकपूर्ण चयन भी महत्वपूर्ण है. जलवायु परिवर्तन अब कोई दूरगामी चेतावनी नहीं, हमारे खेतों की मेड़ पर खड़ा एक कड़वा सच है. यदि देश के कुल अनाज उत्पादन में बड़ी कमी आती है, तो इसका असर किसानों की आय पर ही नहीं, देश की जीडीपी और आम जन की रसोई पर भी पड़ेगा. फरवरी की यह असाधारण तपिश एक चेतावनी है कि यदि हम आज नहीं जागे, तो भविष्य के वसंत केवल लोकगीतों में ही जीवित बचेंगे. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

फिलिस्तीनी कैदियों के दर्द को समझे अंतरराष्ट्रीय समुदाय

इस्राइली संसद (नेसेट) एक विधेयक पारित करने की कोशिश कर रही है, जिसके पारित होने पर इस्राइली अधिकारियों को फिलिस्तीनियों को कानूनी रूप से मृत्यु दंड देने का अधिकार मिल जायेगा. इस घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शायद ही किसी का ध्यान गया है, पर फिलिस्तीनियों के ऊपर मंडराता यह एक और खतरा है. यह विधेयक उस समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार बन पायी थी. नवंबर में यह विधेयक पहली बार संसद में प्रस्तुत हुआ और जनवरी में इसके प्रावधान सामने आये. प्रावधान के तहत सजा सुनाये जाने के 90 दिनों के भीतर फांसी, और अपील का कोई अधिकार नहीं. इस्राइलियों पर हमले की योजना बनाने या उनकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार फिलिस्तीनियों को मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा. हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है. दशकों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने फिलिस्तीनी कैदियों की अनदेखी की है. बीते ढाई वर्षों में, बिना किसी आरोप या आरोप सहित इस्राइली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों पर हो रहे सामूहिक अत्याचार पर वैश्विक स्तर पर लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है. यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो यह फिलिस्तीनी लोगों और उनकी संपत्ति पर इस्राइली बस्तियों द्वारा किये जा रहे हिंसक हमलों के विरुद्ध किसी भी शांतिपूर्ण प्रतिरोध को कमजोर कर देगा. इस्राइल द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की कमजोर बयानबाजी ने पिछले कुछ दशकों से, और विशेष रूप से पिछले ढाई वर्षों में, उसे शह दी है और उसने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन जारी रखा है. यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था को बचाना और अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहता है, तो समय आ गया है कि वह अपने दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन करे. अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान में कमजोर बयान की बजाय इस्राइल पर प्रतिबंध लगाये. फिलिस्तीनियों के विरुद्ध अपराध के दोषी इस्राइली अधिकारियों को जवाबदेह ठहराये. **-मोहम्मद अल्ववीक**

बोधि वृक्ष

जहां धर्म है, वहीं कृष्ण हैं

श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस क्षण आप स्वयं के वश में होते हैं, उस समय स्थितियां अनुकूलता में बदल जाती हैं. अतः राग-द्वेष से विमुख होकर ही दुनिया में कार्य करना चाहिए. 'आत्मवश्यैर्विधेयात्मा', अर्थात आत्मवश होकर अपने आपको अपने वश में रखकर ही सफलता से कार्य पूरा किया जा सकता है. यदि दूसरों के वश में चले रहे हैं, तो लक्ष्य भटकेगा ही, क्योंकि जब तक आपको बाहर की दुनिया संचालित कर रही है, तब तक आप कठपुतली ही हैं. मन और इंद्रियां प्रकृति के वश में आसक्ति और विरक्ति दो धाराओं के बीच बहती हैं, अतः दोनों में अनुशासन भी जरूरी है. वैसे भी, नियमों के अनुशासन में जीवन जीना ही अनुशासन है. नियम में रहने से ही आदतें बनती हैं. मन नियमित है, तो नियमितता से बुद्धि लय में आती है. विपरीतताएं मिटती हैं. जो मन हवा के रुख के अनुसार बहता था, वह अनुशासित होते ही स्थिर होगा, फिर व्यक्ति किसी भी तरफ जाकर नहीं खड़ा होगा. न्याय-अन्याय के सामीप्य को समझेगा, अनुशासित मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके, आसक्ति और विरक्ति से ऊपर उठकर, स्वयं को अपने में अवस्थित कर, प्रभु के शाश्वत रूप में जोड़ कर चलेगा. तब उसे प्रभु प्रसाद मिलना शुरू हो जायेगा. व्यक्ति जब अपने अनुशासन में जीने लगता है, तब वह 'आत्मवश' होता है. अर्थात, इस अवस्था में इंद्रियां तो दौड़ायेंगी ही, मन दौड़ायेगा, पर अनुशासन जीवन में है, तब वह स्वयं के वश में हो सच्चा जीवन जियेगा. विचलित नहीं होगा. नियम से आदतें नियमित होंगी, अनुशासित-व्यवस्थित होंगी, तब मन सुमन बनेगा. व्यक्ति जब अपने को व्यवस्थित कर लेगा, तब शास्त्र के निषिद्ध विषयों का भोग नहीं करेगा. यही मर्यादा मय जीवन का संदेश है. जीवन में हर व्यक्ति को अपनी मर्यादाएं बांधनी पड़ती हैं. जीवन चलाने के लिए जो विधान शास्त्र सम्मत है, उसी पर चलने का संदेश कृष्ण देते हैं. अर्थात आत्मानुशासन में जियें और जीवन चलाने के लिए जो अनिवार्य कार्य है वही करें. घृणा वाले कार्यों से दूर रहें. यही जीवन है. यही धर्म है. जहां धर्म है, वहीं कृष्ण हैं.

-श्री सुधांशु जी महाराज

कुछ अलग

बड़ों के अकेले पड़ जाने की पीड़ा

डॉ मोनिका शर्मा
टिप्पणीकार
monikasharma.writing@gmail.com

बीते दिनों दिल्ली के एक युवक की संवेदनशील पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. पोस्ट में लिखा गया था कि वह रात साढ़े तीन बजे अस्पताल के बाहर अपनी कार में बैठा है और लगभग छत्तीस घंटे से सोया नहीं है. उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है. वह हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है. उसे यह भी अफसोस है कि वह नौकरी के कारण परिवार से दूर हो गया है. अपने माता-पिता के साथ समय नहीं बिता पाया- 'पापा को वक्त नहीं दे पाया... मैं एक बेटा होने में असफल रहा...' युवक ने पिता को हार्ट अटैक आने के बाद दुखी मन से स्वयं को 'नाकाम बेटा' बताया.

वास्तव में, बीमारी से जूझते पिता को देख लिखी गयी भावुक पोस्ट अनेक युवाओं के लिए थोड़ा ठहरकर सोचने की बात लिये है. गिनती के ये शब्द अपनों के साथ समय बिताने की अहमियत समझाते हैं. समय रहते अपने माता-पिता को समय देने की एक मानवीय चेतावनी लिये हैं. यह कटु सत्य है कि करियर की दौड़ में आगे बढ़ते बच्चों को बड़ों की प्रतीक्षा याद ही नहीं रहती. माता-पिता से जुड़ाव की अनमोल अनुभूति को भुला बैठते हैं. बच्चों का योग्य बनना उन्हें पीछे मुड़कर देखने की सोच से ही दूर कर देता है. आगे बढ़ने की आपाधापी में अनुभूतियां फीकी पड़ जाती हैं. बदलते बर्ताव के इस मोर्चे पर 'आउट ऑफ साइट, यानी आउट ऑफ माइंड' वाली स्थिति बन जाती है. बच्चे सोच ही नहीं पाते कि मां-बाप के जीवन से एक-एक दिन कम हो रहा है. बीतता जा रहा यह समय कभी लौटकर नहीं आयेगा. वहीं बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए अपना जीवन जीना भूल जाने वाले अभिभावक थके शरीर और टूटते मन के इस पड़ाव पर अकेले पड़ जाते हैं. सेहत से जुड़ी परेशानी में तो बिल्कुल ही टूट जाते हैं. मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के अनुसार, वृद्धावस्था में अकेलापन बुजुर्गों की समय से पहले जान जाने का अहम कारण है. एक निश्चित उम्र के बाद भावनात्मक और शारीरिक रूप से अकेलेपन को झेलना हर व्यक्ति के लिए तकलीफदेह होता है.

यह सच है कि बड़ों के अकेले पड़ जाने की पीड़ा को बच्चों का मन भी समझता है, पर कामकाजी मजबूरियों की आपाधापी उनसे जुड़े रहने का समय नहीं देतीं. नेशनल अलायंस फॉर केयरगिविंग और एएआरपी की रिपोर्ट की मानें, तो 47 प्रतिशत लोग अपने माता-पिता की चिंता में भावनात्मक रूप से टूटने लगते हैं. अपराधबोध के घेरे में आ जाते हैं. ऐसे में बुजुर्ग माता-पिता से जुड़े रहने के मोर्चे पर समय की टिक-टिक को सुनना भी जरूरी है. समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता. जीवनभर के लिए एक गहरी टीस मन में रह जाती है.

आपके पत्र

शादी समारोह में बंद हो हर्ष फायरिंग

आज भी शादी, विवाह और अन्य उत्सवों के दौरान हर्ष फायरिंग की पुरानी परंपरा जारी है. इस पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता है. हर्ष फायरिंग के दौरान कई बार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. एक पल की लापरवाही से खुशी मातम में बदल जाती है और परिवार प्रभावित होता है. यह सामाजिक कुरीति है, जिसे रोकने के लिए समाज के प्रबुद्ध जनों को आगे आना चाहिए. साथ ही सरकार को कड़े कानून बनाकर हर्ष फायरिंग पर रोक लगानी चाहिए. क्योंकि, यह प्रथा सभ्य समाज के लिए कलंक के समान है.

हिमांशु शेखर, गयाजी

अब तक नहीं बने सड़क और नाले

रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के रतनपुरवा वार्ड नंबर चार के लोग वर्षों से सड़क और नाले के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. नगर परिषद कार्यालय महज सौ मीटर दूर होने के बावजूद यहां सुव्यवस्थित सड़क और नाले का निर्माण ठंडे बस्ते में पड़ा है. कच्ची सड़क होने के कारण बरसात में यह इलाका जलमग्न हो जाता है और स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है. यहां के लागों ने कार्यपालक अधिकारी से पीसीसी सड़क और आरसीसी नाले के निर्माण की मांग की है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ.

लव राज, पश्चिम चंपारण

एआइ भारत को बदलेगा और भारत एआइ को बदलेगा.
नंदन नीलेकणी, इंफोसिस चेयरमैन

- **270** अरब डॉलर (करीब 22.5 लाख करोड़) से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले भारत को इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान.
- **250** अरब डॉलर का निवेश डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर सुविधाओं और हाइ-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए प्रस्तावित है.
- **20** अरब डॉलर की प्रतिबद्धता डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए जतायी गयी है.

एआइ शक्ति का केंद्र बनेगा भारत

देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026 कई कारणों से चर्चा में रहा है, लेकिन इस आयोजन ने एक देश के तौर पर भारत के भविष्य के लिए कई तरह की सकारात्मक संभावनाओं का आधार तैयार किया है. इस सम्मेलन में भारत को दुनिया की 'एआइ राजधानी' बनाने के उद्देश्य के साथ की गयी अरबों डॉलर के निवेश की घोषणाओं ने युवाओं के लिए बेहतर कल की उम्मीद जगायी है. इस बार के इन दिनों में बात भारत में एआइ के क्षेत्र में उठाये गये बड़े कदमों, प्रस्तावित निवेश और भविष्य की कार्य योजनाओं पर...

इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026 में जारी यूथ एआइ एस्पिरेशंस एंड एडॉप्शन रिपोर्ट, जो 3005 ग्रामीण युवाओं की प्रतिक्रिया पर आधारित है, बताती है कि 55 प्रतिशत युवा लगभग हर दिन एआइ का उपयोग करते हैं, जबकि 28 फीसदी कभी-कभार इसका उपयोग करते हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक एआइ का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करनेवाले महज 17 फीसदी लोग हैं. जाहिर है शहर से लेकर गांव तक, स्कूली शिक्षा से लेकर खेती-किसानी तक एआइ एक अहम जरूरत की तरह सबकुछ में शामिल है. बेशक वर्ष 2022 में चैट जीपीटी के लॉन्च को एआइ क्रांति की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है, लेकिन भारत इससे पहले से ही स्वयं को तैयार कर रहा था. वर्ष 2017 से 2024 तक एआइ के विकास और नवाचार के आकलन के आधार पर तैयार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल एआइ वाइब्रेंसी टूल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) प्रतिस्पर्धा में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है. एक अनुमान के मुताबिक 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1.7 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा कर सकती है. नयी दिल्ली में आयोजित एआइ समिट में वैश्विक दिग्गज भी बड़े निवेशों और अहम समझौतों के साथ भारत को एआइ शक्ति का केंद्र बनाने के लक्ष्य में साथ आये हैं, जिससे देश में एआइ के विस्तार को एक मजबूत आधार मिला है.

हैदराबाद, पुणे व बेंगलुरु में बनेंगे माइक्रोसॉफ्ट के एआइ बेस

माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एवं सीइओ सत्या नडेला ने 50 बिलियन डॉलर (लगभग 4.15 लाख करोड़ रुपये) के निवेश के साथ भारत को वैश्विक एआइ मानचित्र पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करने का विजन साझा किया है. कंपनी ने भारत सरकार के 'भाषिणी' मिशन के साथ साझेदारी की है, जिससे एआइ सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में ग्रामीण भारत तक पहुंचाया जा सकेगा. इस निवेश का एक अनिवार्य हिस्सा सुरक्षा और 'रिस्पॉन्सिबल एआइ' के लिए रखा गया है. माइक्रोसॉफ्ट के इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में मौजूदा डेटा सेंटर्स की क्षमता को विस्तार दिया जायेगा और अत्याधुनिक हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित किये जायेंगे. माइक्रोसॉफ्ट भारत को 'ग्लोबल साउथ' के लिए अपना मुख्य आधार बनायेगा. यहां तैयार किये गये एआइ समाधानों का दुनिया भर में निर्यात किया जायेगा.

'एडीवीएएनटीएआइ' प्रोग्राम के तहत 2026 के अंत तक भारत में 20 लाख छात्रों, डेवलपर्स और सरकारी कर्मियों को एआइ स्किल्स में प्रशिक्षित करने का विशाल लक्ष्य रखा गया है.

एआइ-फर्स्ट इंडिया पर गूगल का मेगा निवेश

गूगल के सीइओ सुंदर पिचाई ने भारत को 'एआइ-फर्स्ट' राष्ट्र बनाने के लिए 15 बिलियन (लगभग 1.25 लाख करोड़) के निवेश की घोषणा की है. इस निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक विशाल 'फुल-स्टैक एआइ हब' स्थापित करने में जायेगा. यह केंद्र हजारों उच्च-तकनीकी नौकरियां पैदा करेगा और भारत को एआइ समाधानों का वैश्विक निर्यातक भी बनायेगा. कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए गूगल एक नयी फाइबर-ऑप्टिक सबसी केबल परियोजना शुरू कर रहा है. यह केबल भारत को सीधे अमेरिका और अन्य प्रमुख वैश्विक केंद्रों से जोड़ेगी. गूगल की शाखा गूगल डॉट ओआरजी ने 60 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है. इसमें से 30 मिलियन सरकारी सेवाओं में नवाचार के लिए और 30 मिलियन वैज्ञानिक अनुसंधान (स्वास्थ्य, कृषि और जलवायु) के लिए आवंटित किये गये हैं. भारत की कार्यशक्ति को एआइ-सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है.

अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से 1.1 करोड़ छात्रों तक जेनरेटिव एआइ टूल्स पहुंचाये जायेंगे.

40 लाख छात्रों को एआइ साक्षर करेगा अमेजन

ई कॉमर्स और क्लाउड दिग्गज अमेजन ने भारत के डिजिटल भविष्य को नयी दिशा देने के लिए 35 बिलियन (लगभग 2.9 लाख करोड़) के भारी-भरकम निवेश की घोषणा की है. यह निवेश 2030 तक पूरा किया जायेगा.

- अमेजन विशेष रूप से तेलंगाना और महाराष्ट्र में अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करेगा, जो भारतीय स्टार्टअप्स और सरकारी संस्थानों को उच्च-क्षमता वाली एआइ कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करेंगे.
- वर्ष 2030 तक अमेजन ने 1.5 करोड़ लघु और मध्यम व्यवसायों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है. एआइ-संचालित 'सेलर असिस्टेंट' जैसे टूल्स के माध्यम से छोटे व्यापारियों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलेगी. कंपनी का लक्ष्य भारत से होने वाले इ-कॉमर्स निर्यात को 80 बिलियन तक ले जाना है.
- भविष्य की कार्यशक्ति तैयार करने के लिए अमेजन 40 लाख स्कूली छात्रों को एआइ साक्षरता और क्लाउड कौशल प्रदान करेगा.
- भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अमेजन ने 'रूफस' जैसे जेनरेटिव एआइ शॉपिंग असिस्टेंट और बहुभाषी मॉडल्स पेश किये हैं, जो स्थानीय भाषाओं में खरीदारी को आसान बनायेंगे.

स्वदेशी एआइ क्लाउड की ओर बड़ा कदम है यह डील

वैश्विक निवेश दिग्गज ब्लैकस्टोन और भारतीय एआइ स्टार्टअप नेयसा के बीच हुआ समझौता इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक रहा. ब्लैकस्टोन ने नेयसा के लिए लगभग 10,000 करोड़ के कुल निवेश पैकेज का ऐलान किया है. निवेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में 20,000 से अधिक उच्च-क्षमता वाले जीपीयू (जैसे एनवीआइडीआइए एच200/बी200) के डेप्लॉयमेंट में जायेगा. यह बैंकिंग, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए 'स्वदेशी एआइ क्लाउड' तैयार करेगा. ब्लैकस्टोन नेयसा को अपने वैश्विक डेटा सेंटर पोर्टफोलियो (जैसे क्यूटीएस और एयरट्रेंक) तक पहुंच प्रदान करेगा. इससे नेयसा को वैश्विक स्तर पर जीपीयू की निर्बाध आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार में मदद मिलेगी. इस निवेश के जरिये नेयसा भारतीय स्टार्टअप्स और उद्यमों को 'एआइ-एज-ए-सर्विस' मॉडल पर सस्ती कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करेगा, जिससे छोटे डेवलपर्स भी भारी निवेश के बिना बड़े एआइ मॉडल तैयार कर सकेंगे.

नया अध्याय लिखेगी एनवीडिया-योट्टा साझेदारी

इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026 में डेटा सेंटर कंपनी योट्टा व एनवीडिया के बीच साझेदारी हुई, जिसके तहत योट्टा ने भारत में एनवीडिया के 20,736 'ब्लैकवेल अल्ट्रा' जीपीयू तैनात करने की योजना बनायी है. ये चिप वर्तमान मॉडल्स की तुलना में 30 गुना अधिक गति से डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे भारत एशिया का सबसे बड़ा एआइ हब बनेगा.

- इस गठबंधन का मूल उद्देश्य भारत के डेटा को स्वदेशी सीमाओं के भीतर रखना है. यह सुनिश्चित करेगा कि भारत का क्रिटिकल डेटा विदेशी क्लाउड पर निर्भर रहने के बजाय देश में ही प्रोसेस और सुरक्षित हो.
- योट्टा ने अपने 'शक्ति क्लाउड' के माध्यम से 10,000 जीपीयू को सरकारी मिशनों और स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित किया है. इससे छोटे डेवलपर्स को भी 'पे-पर-यूज' मॉडल पर सस्ती और उच्च-स्तरीय कंप्यूटिंग शक्ति मिल सकेगी.
- एक बिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश के साथ एनवीडिया अपना प्रीमियम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे भारत में ला रहा है. इससे भारतीय शोधकर्ताओं को जटिल एआइ मॉडल ट्रेन करने के लिए अब विदेशी सर्वरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
- ग्रेटर नोएडा और नवी मुंबई स्थित योट्टा के डेटा सेंटर्स इस एआइ क्रांति के मुख्य केंद्र होंगे, जिनके अगस्त 2026 तक पूरी तरह सक्रिय होने का लक्ष्य है.

'इंडिया एआइ मिशन' यहां करेगा काम

भारत सरकार ने 'इंडिया एआइ मिशन' के लिए 10,300 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है, जिसके तहत-

- सरकार 38,000 से अधिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का नेटवर्क तैयार कर रही है. हाल ही में 20,000 अतिरिक्त जीपीयू जोड़ने की घोषणा की गयी है.
- स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को मात्र 65 रुपये प्रति घंटा की रियायती दर पर ये कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं, ताकि संसाधन की कमी नवाचार में बाधा न बने.
- एआइ-आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स पर निवेश किया जायेगा, जो एक्स-रे और स्कैन का विश्लेषण कर कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों का जल्दी पता लगा सकेंगे.
- 'हाइब्रिड एआइ मॉडल' के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों तक विशेषज्ञ परामर्श पहुंचाने के लिए निवेश हो रहा है.
- 'मौसम जीपीटी' और 'किसान इ-मित्र' जैसे एआइ चैटबॉट्स पर निवेश किया जा रहा है, जो किसानों को स्थानीय भाषाओं में मौसम और कीटों की जानकारी देते हैं.
- ड्रोन व सेटेलाइट डेटा के जरिये मिट्टी की सेहत और सिंचाई प्रबंधन के लिए एआइ समाधान विकसित किये जा रहे हैं.
- स्कूलों और कॉलेजों में एआइ साक्षरता पहुंचाने के लिए निवेश 15,000 स्कूलों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब्स' स्थापित करने की योजना है.
- सरकारी सेवाओं को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासनिक कार्यों में एआइ का एकीकरण कर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है.

भारतीय निवेशक बढ़ा रहे एआइ का दायरा

वैश्विक दिग्गजों के साथ भारतीय औद्योगिक घरानों ने भी 25 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा कर भारत को 'एआइ सुपरपावर' बनाने का संकल्प लिया है.

'जियो इंटेलिजेंस' विजन पर काम शुरू

अगले 7 वर्षों में मुकेश अंबानी एआइ पर 10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे. इसके तहत जामनगर में गीगावाट-स्केल के एआइ-रेडी डेटा सेंटर्स का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसका 120 मेगावाट हिस्सा 2026 के अंत तक सक्रिय हो जायेगा. इन डेटा सेंटर्स को रिलायंस के 10 गीगावाट ग्रीन पावर सरप्लस से चलाया जायेगा. 'जियो इंटेलिजेंस' एआइ की लागत को आम भारतीयों के लिए न्यूनतम स्तर पर लायेगा.

विकसित होगा 'क्लीन एनर्जी हब'

एआइ बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए गौतम अडानी 8.3 लाख करोड़ का निवेश करेंगे. इसका मुख्य लक्ष्य 5 गीगावाट क्षमता का विशाल डेटा सेंटर नेटवर्क स्थापित करना है, जिसे पूरी तरह अडानी ग्रीन एनर्जी की सौर व पवन ऊर्जा से संचालित किया जायेगा. यह दुनिया का सबसे बड़ा 'नेट-जीरो' एआइ बुनियादी ढांचा होगा. इस मॉडल के तहत ग्रुप गूगल के साथ मिलकर विशाखापत्तनम में 'क्लीन एनर्जी हब' विकसित कर रहा है.

बनेगा ग्रीन एनर्जी एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर

टाटा और ओपनएआइ मिलकर भारत में 100 मेगावाट का एआइ बुनियादी ढांचा बनायेंगे, जिसे 1 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकेगा. टीसीएस 'हाइपरवॉल्ट' इकाई के जरिये हरित ऊर्जा आधारित एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी.

बनेगी एआइ फैक्ट्री

एलएंडटी व्योमा, एनवीडिया के साथ मिलकर चेन्नई और मुंबई में 'एआइ फैक्ट्री' का निर्माण करेगी. इसके लिए एलएंडटी धोलेरा, गुजरात में 25,000 करोड़ के निवेश से 250 मेगावाट का ग्रीन एआइ डेटा सेंटर तैयार किया जा रहा है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेज है देश की रफ्तार

वर्ष 2025 भारत ने शक्तिशाली स्वदेशी मॉडल बनाने से लेकर किफायती एआइ समाधानों को वैश्विक स्तर पर निर्यात करने तक कई उपलब्धियां हासिल की हैं और ग्लोबल एआइ सुपरपावर के रूप में अपनी पहचान बनायी है.

- देश ने अपना स्वदेशी एलएलएम 'शुका वी1' (सर्वम एआइ) लॉन्च किया. 70 अरब पैरामीटर वाला यह मॉडल भारतीय भाषाओं और ऑडियो के लिए अनुकूलित है, जिसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 4096 एनवीआइडीआइए एच100 जीपीयू का समर्थन प्राप्त है.
- भारत के पास अब 38,000 जीपीयू का अपना विशाल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है.
- इंडिया एआइ मिशन के तहत जीपीयू की लागत में 50-60 प्रतिशत की भारी कटौती की गयी है. पहले जहां इसके लिए 200-250 रुपये प्रति घंटा देना होता था, अब यह 115 प्रति घंटे की दर पर उपलब्ध है.

- भारत ने 'एआइ यूजर' से 'एआइ प्रोवाइडर' बनने की ओर एक बड़ा कदम उठाया. पेरिस में आयोजित यूरोप के सबसे बड़े टेक इवेंट वीवा टेक में लॉन्च किये गये 'भारत जीपीटी मिनी' को वहां के प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल ने अपनी छात्र सेवाओं के लिए अपनाया है.
- जोहो और फ्रेशवर्क्स अब साधारण चैटबॉट्स के बजाय 'एआइ एजेंट्स' बना रहे हैं, जो वैश्विक कंपनियों के जटिल कार्य संभाल रहे हैं.
- कुंभ जैसे विशाल आयोजनों में 'भाषिणी' ऐप ने लाइव अनुवाद के जरिये लाखों लोगों की भाषाई बाधाओं को दूर किया गया.
- सरकार 'युवा एआइ फॉर ऑल' नामक एक निःशुल्क राष्ट्रीय एआइ साक्षरता पाठ्यक्रम भी चला रही है, जो ग्यारह भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है.

राशिफल — डॉ एनके बेरा

- **मेष** : रोजी-रोजगार के क्षेत्र में उलझनों का निवारण.
- **वृष** : स्वजनों के स्वास्थ्य की चिंता होगी. सामान्य आर्थिक लाभ होगा.
- **मिथुन** : परिश्रम का पूरा फल मिलेगा. शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
- **कर्क** : संकल्पित काम पूरे होंगे. भौतिक सुख-सुविधा बढ़ेगी.
- **सिंह** : वाक्पटुता एवं चतुराई से बिगड़े हुए काम पूरे होंगे.
- **कन्या** : नये लोगों से संपर्क. महिला मित्र के माध्यम से लाभ.
- **तुला** : सामयिक-सामाजिक विकास. शत्रुओं पर विजय मिलेगी.
- **वृश्चिक** : अवसरों का फायदा उठाएं. परिवार में मांगलिक कार्य होगा.
- **धनु** : नवीन व्यापारिक योजना सफल. आर्थिक लाभ होगा.
- **मकर** : बुद्धि-प्रतिभा का विकास. वांछित उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा.
- **कुंभ** : जमीन-मकान, स्थिर संपत्ति संपत्ति से संबंधित काम सिद्ध होंगे.
- **मीन** : घरेलू आवश्यकताओं पर अधिक व्यय करना पड़ेगा.

शब्दपहेली — 2837

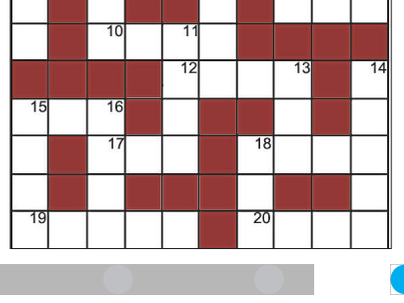

बायें से दायें : 1 चमक-दमक, सज-धज, ठाट-बाट (2,2), 3 कमी होना, दाने-दाने को मोहताज होना (2,3), 6 रत्नों का समूह, समुद्र (4), 8 पांव के नीचे की तली (3), 9 रुष्ट, दुखी, अप्रसन्न (3), 10 कान में धीरे से कही हुई बात (4), 12 चुनौती (4), 15 वर यात्र (3), 17 गति, चाल, वेग (3), 18 दया करने वाला (4), 19 अपने को तुच्छ समझने का भाव (3,2), 20 पाल में बांधने का रस्सा (4)

ऊपर से नीचे : 1 मुख्य आधार या सहारा (3,2), 2 उदाहरण, मिसाल (3), 4 लिखित आज्ञा पत्र (4), 5 जो जायज न हो, अनुचित (4), 7 कली, बिना खिला हुआ फूल (3), 8 जिले का प्रशासनिक उपखंड (4), 11 जिस पर कशीदे काढ़े गए हों (4), 13 चाल-चलन, ढंग (3), 14 संतोषी, सहने वाला (5), 15 एक प्रकार की मिठाई (4), 16 द्रव्यता, चंचलता (4),18 दबा-कुचला हुआ, पिछड़ा, विदीर्ण (3)

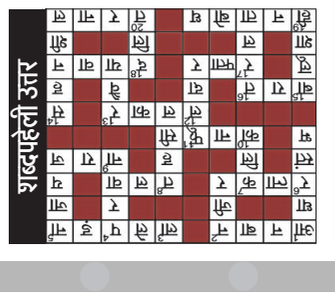

सुडोकू नवताल — पहेली नंबर 6228

		6	4		5	8		
9				1				7
6	5			4			7	1
	4						2	
1	2			6			9	8
3				8				9
		8	6		9	5		

सुडोकू नवताल - 6227 का हल

2	4	5	6	9	8	1	7	3
1	7	6	4	3	5	8	2	9
3	8	9	1	2	7	6	5	4
9	1	7	3	6	2	4	8	5
5	6	3	8	7	4	9	1	2
4	2	8	5	1	9	3	6	7
7	3	1	9	5	6	2	4	8
8	9	2	7	4	1	5	3	6
6	5	4	2	8	3	7	9	1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने हैं. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है.
- आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

Be part of Community and Get Early Access to All.

✅ I Give My Earliest Newspapers updates from 5 AM in Private channel with All Editions

♦ Indian Newspaper

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ International Newspapers channel

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ Magazine Channel

National & International
[Genaral & Exam related]

♦ English Editorials

[National + International Editorials]